हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

21 जनवरी, 1976

खण्ड 1 अं 8

अधिकृत विवरण

बुधवार, 21 जनवरी, 1976

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उतर (8) 1

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (8)26

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर (8)30

अनुपस्थिति की अनुमति (8)31

वर्ष 1976– 77 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (8)31

परिशिष्ट–

तारांकित प्रश्न संख्या 1555 का उत्तर । (i)–(iv)

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 21 जनवरी, 1976

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–।, चण्डीगढ में 14.00 बजे हुई ।

अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker Question Hour.

तारांकित प्रश्न संख्या 1412

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी राम लाल वधवा, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1440

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, चौधरी दल सिंह, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1517

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री

औमप्रकाश गर्ग, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Defaulter Cooperative Societies

***1521. Rao Dalip Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the district-wise total number of Co-operative Societies which are defaulters in the State during the years 1973-74 and 1974-75 to-date; and

(b) the district-wise number of cases of embezzlement in the Cooperative Societies, if any, detected in the State during the years 1972-73, 1973-74 and 1974-75 to-date ?

गृह तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी) :

(क) विवरण 'क' सदन की मेज पर रखा जाता है ।

(ख) विवरण 'ख' सदन की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण 'क'

सहकारिता का वर्ष 30 जून को समाप्त होता है इसलिये विभाग के आंकड़े हर वर्ष 30 जून को इकट्ठे किए और रखे जाते हैं । इस कारण सूचना 30 जून तक तैयार की गई है ।

क्रमांक	जिले का नाम	ऐसी समितियों की संख्या जो बैंकों के ऋणों की

		अदायगी में डिफाल्टर हैं	
		1973–74	1974–75
1	अम्बाला	771	733
2	भिवानी	357	4-31
3	गुडगांवा	1,089	1,348
4	हिसार	841	923
5	जीन्द	331	348
6	करनाल	536	603
7	कुरूक्षेत्र	617	645
8	महेन्द्रगढ़	310	485
9	रोहतक	338	383
10	सोनीपत	282	321

विवरण ' ख '

क्रमांक	जिले का नाम	1972–73	1973–74	1974–75	1975–78 (30–11–75)

1	अम्बाला	73	62	63	28
2	भिवानी	40	16	18	1
3	गुडगांवा	26	42	40	5
4	हिसार	32	36	31	-
5	जीन्द	36	25	31	15
6	करनाल	48	31	68	29
7	कुरूक्षेत्र	30	78	71	32
8	महेन्द्रगढ़	11	37	28	4
9	रोहतक	17	34	13	15
10	सोनीपत	21	13	16	5
11	सिरसा	-	-	-	4
	जोड़	334	374	379	138

राव दलीप सिंहः क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि हरियाणा प्रान्त में टोटल सोसाइ– टीज कितनी हें?

श्रीमती शारदा रानी : 30 जून, 1975 को कुल सोसाइटीज 14,135 थी ।

राव दलीप सिंह : मंत्री महोदया नेबताया कि 6 हजार

220 सोसाइटीज डिफाल्टर्ज हैं । यह तादाद बहुत ज्यादा है । जिन लोगों ने लोन लिया है, जब तक वे उसे वापिस नहीं करेंगे तब तक दूसरे गरीब लोगों को लोन मिल नहीं सकता । इस समस्या को हल करने के लिए क्या मैली महोदया कोई खास योजना या प्रोग्राम बनायेगी?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, 6 हजार 220 नम्बर दिखता तो बहुत ज्यादा है लेकिन उनमें जिस सोसाइटी की तरफ 50 परसैन्ट या 50 परसैन्ट से ज्यादा अमाउन्ट रह गया है उनको हम डिफाल्टर करार दे देते हैं । उनसे पैसा वसूल करने का तरीका आर्बीट्रेशन प्रोसिडिंग्ज से या एरियर आफ लैन्ड रेविन्यू प्रोसिडिंग्ज से है ।

मलिक सतराम दास बतरा : क्या मंत्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि कितनी ऐसी सोसाइटीज हैं जिनका रिकार्ड पुलिस और कोर्ट में है, कितनी सोसाइटियां ऐसी हैं जिनका रिकार्ड गुम है और कितनी ऐसी सोसाइटीज हैं जिन का कुल कितना गबन है?

श्रीमती शारदा रानीः मेरे पास इन्फर्मेशन अलग–अलग ईयरवाइज है । सन् 1975–78 की राशि नौ लाख 38 हजार है ।

राव बंसी सिंह : क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि सन् 1973–74 की भिवानी. गुड़गांव, हिसार, करनाल, जींद, मोहिन्द्रगढ और रोहतक जिलों की सोसाइटीज की जो फिगर्ज दी हैं, इन सब

के अन्दर सन् 1974–75 के अन्दर ओवर ड्यूज अधिक होने का क्या कारण हे?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि सूखा पड़ने के कारण रिकवरी नहीं हो पायी । इस साल ओवर डयू बहुत कम है । पिछले साल की अपेक्षा इस साल ओवरडयूज बहुत घटे हैं ।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): क्या मत्री महोदया को इल्म है कि कुछ कोआपरेटिव सोसाइटीज ने सैक्रेटरीज और खजानचियों से मिल कर गरीब लोगों के जिम्मे फर्जी कर्जे दिखा रखे हैं? अब रिकवरी उनके जिम्मे आ रही है । अगर यह बात ठीक है तो क्या उनका कर्जा माफ कर दिया जायेगा? जिन्होंने फर्जी कर्जा दिखाया है क्या उनके खिलाफ कोई कार्य– वाही की जायेगी?

श्रीमती शारदा रानी: अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि फर्जी कर्जा दिखाना बहुत बडा जुर्म है । जो ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है, केसिज दर्ज किये जाते हैं । इस प्रकार के आदमी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं । जहां तक फर्जी कर्जा दिखाने का सवाल है उनके बारे में न सिर्फ हमारा कोआपरेटिव डिपार्टमैंट जांच कर रहा है बल्कि पुलिस के जरिए भी जांच करवायी जाती है ।

राव बंसी सिंह : क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि 30

जून 1975 तक सारे हरियाणा में इम्बैजलमेंट का कुल कितना रुपया था?

श्रीमती शारदा रानी : सन् 1975–76 में 9 लाख 38 हजार रुपया है ।

श्री जगजीत सिंह टिक्काः क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि पुलिस में कितने केसिज इम्बैजलमैंट के दिये गये और कब–कब दिये गये और उनका अमाउन्ट कितने साल से बकाया है? क्या उनको निपटाने की कोशिश की जायेगी?

श्रीमती शारदा रानीः सभी को निपटाने के लिए कई कदम उठाये हैं । सन् 197 4–7 5 में जो केसिज हैं वे 4 हजार 949 हैं । इनमें 78 लाख 13 हजार रुपये का अमाउन्ट इनवाल्वड है ।

श्री प्रेम सुख दास : क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि जो केसिज आर्बीट्रेशन के द्वारा सुलझाये जाते हैं उनमें टाईम बहुत ज्यादा लगता है, उनका काफी दिनों तक सिलसिला चलता है, उस तरीके को चेंज करके सरकार कोई आसान तरीका बनायेंगी?

श्रीमती शारदा रानी :. अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहती हूं, मैं गलती से पहले आर्बीट्रेशन केसिज की फिगर्ज दे गई । पुलिस के केसिज 27 अक्तूबर, 1975 से पहले के 412 हैं और उसके बाद के 53 केसिज हैं । कुल टोटल 465 केसिज हैं ।

चौधरी पीर चन्दः क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि इनमें कुल हरिजन सोसाइटीज कितनी हैं और उनमें कितनी रकम दी गई है?

श्रीमती शारदा रानीः हरिजन सोसाइटीज के बारे में आप अलग सवाल पूछें, यह तो सब के बारे में पूछा गया है ।

राव दलीप सिंहः क्या मंत्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि सन् 1972–73, 1973–74 और 1974–75 में ऐम्बैजलमैंट की कितनी अमाउन्ट है?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय सन् 1972–73 में 47 लाख 69 हजार थी जिसमें से कुछ अमाउन्ट की रिकवरी हो कर अब 44 लाख 53 हजार रह गई है । सन् 1973–74 में 37 लाख 95 हजार थी और सन् 1974– 75 में 52 लाख 53 हजार थी और 1975–78 में 9 लाख 38 हजार ।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): मंत्री महोदया ने बताया कि जिन्होंने फर्जी तौर पर रकम दूसरों के नाम लिखी है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी लेकिन जो रिकवरी के बारे में कहा उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि जिन्होंने पैसा लिया ही नहीं है वह किससे वसूल होगा?

श्रीमती शारदा रानी : मैंने अभी बताया कि आर्बीट्रेशन प्रोसिडिंग्ज के जरिए वसूल किया जायेगा । अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्रीमिनल केसिज बना कर ऐज एरियर आफ लैन्ड रैविन्यू भी

वसूल किया जायेगा । जिन्होंने भी गड़बड़ की है किसी का कोई पैसा राइट आफ नहीं किया गया है सारा पैसा वसूल करने की कोशिश की जायेगी ।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं कि पिछले दिनों इस प्रकार की गड़बड़ होती रही है । किसी तरह से कुछ होशियार आदमियों ने 10–20 आदमियों से लिखवा लिया और कोआपरेटिव सोसाइटी बना ली और उसके नाम से कर्ज लेकर उस रकम को खुद हड़प कर गये दूसरे लोगों के अंगूठे टिकवा लिए कर्जे की रकम उनके नाम लिखवा दी । ऐसी बातें हुई हैं । उन सब की पूरी तरह से अध्यक्ष महोदय जांच कर रहे हैं । आपको मालूम है कि आजकल पेमैंट चौक से की जाती है । शायद इस बात का प्रबन्ध तभी हुआ था, जब आपके पास महकमा था । अब तो आइडैंटिटी कार्ड होता है, किसी बोगस आदमी को कर्जा नहीं दे सकते हैं । ऐसे केसिज बहुत दिनों के पुराने केसिज हैं । हमारे सामने यह दिक्कत है कि जिन्होंने अंगूठे और दस्तखत कर दिये हैं, हम तो उन्हीं को जिम्मेवार मानते हैं । अब इस बात को साबित करना बड़ा कठिन है । जिसने अंगूठा लगाया है पैसा उसने लिया अथवा पैसा कोई दूसरा हड़प कर गया । लेकिन कोशिश इस बात की है कि जांच करवायी जायेगी और जिसने इस प्रकार की गड़बड की है उसी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । इस प्रकार के मामले की जांच के बारे में हम कदम उठा रहे हैं ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : क्या मत्री महोदया बतायेंगी कि जो केसिज पुलिस में पांच–छः साल से हैं या पांच छः साल से इन्वैस्टीगेशन नहीं हुई है तो क्या उन केसिज की इन्वैस्टीगेशन जल्दी से जल्दी करायेंगे क्योंकि अब महकमा पुलिस और कोआपरेटिव डिपार्टमैंट दोनों ही एक ही मिनिस्टर साहब के पास हैं ।

श्रीमती शारदा रानी : जी हां, हमने इन्वैस्टीगेशन जल्दी करने के लिये बहुत कदम उठाये हैं । हमने पुलिस डिपार्टमैंट को यह कहा है कि इन्वैस्टीगेशन जल्दी करके इनको जल्दी से ऐक्सपीडाइट करे और इसके लिये एक स्पैशल पुलिस सैल बना दिया गया है जिसके अन्दर काफी स्टाफ है रू एक डी ० एस ० पी ०, 10 इन्सपैक्टर्ज, कुछ हैड कांस्टेबल्ज और कांस्टेबल्ज हैं । इस तरह से इसको ऐक्सपीडाइट करने के लिये एक अलग सैल बना दिया गया है ।

चौधरी रिजक राम : मंत्री महोदया ने फरमाया है कि सात हजार के करीब ऐसे केसिज हैं जो आर्बीट्रेशन में दिये गये हैं । है उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह केसिज भी एम्बैजलमैंट से ताल्लुक रखते हैं या इन्डीपैडैन्ट हैं?

श्रीमती शारदा रानीय अध्यक्ष : महोदय, माननीय सदस्य को समझना चाहिए कि जो केसिज ऐम्बैजलमैंट से ताल्लुक रखने वाले हों, वह तो एक तरह से क्रिमीनल केसिज बन जाते हैं और

जो केसिज आर्बीट्रेशन में जाते हैं, वहू जनरली डिफाल्टर्ज केसिज होते हैं इन्हें केवल ऐम्बैजलमैंट ही नहीं मान सकते ।

श्री अमर सिंह : आनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी यह फरमाया है कि जो बोगस अंगूठे लगाकर कर्जे दिये गये हैं और ऐक्चुअली उसको होशियार आदमी ले गये, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है । क्या मली महोदया यह बतायेंगी कि जब तक उनकी जांच पड़ताल न हो जाये, तब तक उनकी रिकबरी स्टे करने का प्रबन्ध करेंगी क्योंकि जिनके अंगूठे लगे हुए हैं, उन्हीं को तंग किया जा रहा है?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, जब भी हमें इस प्रकार की शिकायतें मिलती हें या लोग आकर बताते हैं या लिखकर देते हैं तो हम उनकी पूरी तरह से जांच करवाते हैं । लेकिन अगर किसी ने अंगूठा लगा दिया तो कानून के मुताबिक कोई ऐक्सक्यूज नहीं है, वह तो गलती जरूर है और उसका खामियाजा उसे भरना ही होगा । अगर किसी ने जान– बूझकर अंगूठा लगा दिया तो इस बात का क्या सबूत है कि उसने कर्जा नहीं लिया है ।

चौधरी रिजक राम : अध्यक्ष महोदय, ऐसे केसिक गवर्नमैंट के और अफसरान के नोटिस में भी आये हैं कि लोगों ने रुपया लिया नहीं, लेकिन फर्जी उनके अंगूठे लगाकर रुपया वसूल कर लिया गया और उसमें भी या तो उनके अँगूठे लगवा लिये या

अँगूठे गलत लगाए गए? जहां पर ऐसे केसिज नोटिस में आये हैं, क्या मली महोदया बताएंगे कि उनकी रिकवरी के लिये बाकायदा अदालत में जाना पडेगा या आर्बीट्रेशन से रुपया वसूल किया जायेगा?

श्रीमती शारदा रानीः हम इस प्रकार के केसिज की जहाँ पर कि लोग कहते हैं कि अँगूठे हमारे नहीं हैं, पुलिस से जाँच करवाते हैं और इस बात की पूरी तरह से इन्कवायरी होती है । इसके लिये हम फौरेन्सिक लैबोरेटरी की भी मदद लेते हैं ।

चौधरी रिजक राम : जहां पर ऐसे केसिज नोटिस में आये हैं कि बोगस अंगूठे लगाकर रुपया ले लिया गया, क्या उनकी रिकवरी के लिये उनको कोर्ट आफ ला में बाकायदा दावा करना पड़ेगा या आर्बीट्रेशन के जरिये पैसा वसूल हो जायेगा?

श्रीमती शारदा रानी : कोशिश यह की जाती है कि पैसा आर्बीट्रेशन से वसूल कर लिया जाये लेकिन अगर और कोई बस न चले तो फिर केस पुलिस में भी देना पड़ता है ।

Mr. Speaker : It is provided in the Cooperative Societies Aet itself. You will find it in the Act itself.

चौधरी रिजक राम : मैंने तो यह इसलिये पूछा है कि मली महोदया ने यह फरमाया था कि जहां ऐम्बैजलमैंट है वहां रिकवरी आर्बीट्रेशन से हो ही नहीं सकती ।

श्रीमती शारदा रानीः मैंने तो यह नहीं कहा कि

आर्बीट्रेशन से रिकवरी हो ही नहीं सकती ।

चौधरी मेहर चन्द रू:क्या मंत्री महोदया यह फरमायेंगी कि कोआप्रेटिव मार्किटिंग सोसाइटी, भट्टू में जो ऐम्बैजलमैंट हुई है उस पर क्या ऐक्शन लिया है?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, 14 हजार सोसाइटियां हैं । यहां पर एक–एक सोसाइटी का ब्यौरा तो नहीं मांगा जा सकता । वह भट्टू के लिये अलग से नोटिस देकर सवाल पूछ ले ।

तारांकित प्रश्न सं ० 1530

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी चांद राम, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Bund on Sahabi Nadi

***1552. Chaudhri Ram Parshad :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to construct a Bund on `Sahabi-Nadi' to protect the following villages from floods :

(i) Pawati

(ii) Panwar

(iii) Khijuri

(iv) Badhoj and

(v) Lalpur ?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : No, Sir.

चौधरी राम प्रशाद : अध्यक्ष महोदय, मती महोदय ने जो जवाब 'नो सर' दिया है, इससे काम नहीं चल सकता जबकि यहएक बड़ी समस्या है और इससे हमारा बुरा हाल है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, इन्होंने जो 5 गांवों के नाम दिये हैं, उनमें से तीन में तो कभी फल्ड आया ही नहीं और दो गांव जिनमें हाई फ्लड के वक्त आज से कुछ साल पहले थोड़ा–बहुत फ्लड आया, वहाँ के लिये एक स्कीम बनायी गयी थी और जिन लोगों को ये रिप्रेजैन्ट करते हैं, उन लोगों ने यह लिखित रूप में दिया है कि हम गांवों के चारों तरफ रिंग बन्ध. नहीं बनवाना चाहते । इसलिये अब उन गांवों के लोगों की मर्जी के खिलाफ वह नहीं बनवायेंगे ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि झज्जर तहसील के गांवों में भी फ्लड आता है वहाँ के लिए भी कोई ऐसी योजना बनायेंगे ।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, झज्जर तहसील में 5 ऐसे गांव हैं जिनमें फ्लड आता है लेकिन जहां तक रिंग बांध बनाने का सवाल है, अभी तक किसी भी गांव में रिंग बान्ध बनाने का विचार नहीं है ।

चौधरी मनफूल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह फरमायेंगे कि वे कौन से 5 गांव हैं, क्योंकि हमारे हल्के में तो सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां फ्लड आता है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब फ्लड आने की बात नहीं है । जहां पर फ्लड ज्यादा अफैक्ट करता है उसकी बात है । साहबी नदी तो हमारी स्टेट के लिये असैट है, लायविलिटी नहीं है । उसकी वजह से ग्राउन्ड वाटर रीचार्ज होता है और अच्छी फसल होती है । साहबी नदी की वजह से तो वह इलाका आबाद है ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: स्पीकर साहब, मेरा सवाल यह है कि जब बारिश ही नहीं हुई तो इनके यहाँ पर फ्लड कहाँ से आ गया? हम तो बारिश की वजह से तड़प रहे हैं और यह फ्लड की बात करते हैं ।

चौधरी मनफूल सिंह: क्या मिनिस्टर साहब फरमायेंगे कि वे कौन से पांच गांव हैं जो हमारे यहाँ ज्यादा फ्लड अफैक्टिड है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : वे हैं सुमाना, सुरथली, समसपुर माजरा, कोसली, सुरा ।

Construction of Morni Panchkula Road

***1558. Shri Jagjit Singh Tikka :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether it is a fact that construction of Morni

Panchkula road was started from both ends;

(b) if so, the total length of the said road metalled from each end;

(c) the total middle length of the said road which remains to be constructed and metalled ; and

(d) the time by which the road as referred to in part (a) above is likely to be completely metalled and made all weather road for vehicular traffic ?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma) :

(a) Yes.

(b) From Panchkula and. 6.00 K.M.

From Morni end. 4.70 K. M.

(c) 20.20 K. Ms.

(d) No definite date can be given, as the completion of the road will depend on availability of funds.

श्री जगजीत सिंह टिक्का : क्या मंत्री महोदय यह करमाने की कुपा करेंगे कि इस रोड पर बस कब तक चलवा देंगे? मेरा कहने का मतलब बहु है अगर पक्की नहीं बन सकती तो चाहे कच्ची बनाकर जैसे हिमाचल में कच्ची सड़कों पर बस चलती है बस चलने के काबिल कब तक बना देंगे?

Pandit Chiranji Lal Sharma : I am afraid, the Transport Department will not take the risk of plying a bus on this road unless it is metalled.

श्री हरि सिंह : मंत्री महोदय ने यह फरमाया है कि कोई डैफीनिट डेट नहीं बता सकते, क्योंकि जब फन्डज मिलेंगे तो बनेगी । गवर्नर साहब के ऐड्रैस में और बजट में भी यह कहा गया है कि 250 गांवों को सड्कों से कनैक्ट कर दिया जायेगा तो इसका मतलब यी है कि इसके लिये आलरैडी प्रोवीजन है । तो क्या वह इसको बनाने की कृपा करेगे?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Mr. Speaker, Sir, the question relates to Morni Panchkula road.

राव अभय सिंहः मंत्री महोदय को याद होगा कि उन्होंने पिछले सैशन में भी यह फरमाया था कि ऐसी सत्के यानी ऐसी लिंक रोड्ज जिनमें एक–एक दो–दो फर्लान्ग के टुकड़े बनाने रह रहे हैं और बाकी कम्पलीट हैं, उनको पहरने बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या मैं यह पूछ सकता हू कि रिवाडी हल्के में जो कुकके कम्पलीट होनी रह रही हैं, उनको जल्दी से पूरा करने को कोशिश करेंगे?..

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । पिछले सैशन के जवाब पर अब सप्लीमैंट्री नहीं हो सकता ।

राव अभय सिंह : वह तो मैंने इनको याद दिलाया है ।

Mr. Speaker : This is not a supplementary to this question. It, therefore, does not arise.

Construction of Road from Siwani to Bawani Khera Via Shiarwa

***1564. Chaudhri Amar Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct road from Siwani to Bawani Khera *via* Shiarwa; if so, when ?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma) : No, Sir.

श्री गुलाब सिंह जैन : क्या मंत्री महोदय यह फरमायेंगे कि 31 मार्च, 1975 को भिवानी के पंचायती राज सम्मेलन में जो चौधरी बंसी लाल जी ने सड़क बनाने के लिए ऐलान किया था, जहां तक मुझे मालूम् है 47 लाख रुपये का ऐस्टीमेट बना था, क्या उस वायदे को पूरा करने का विचार है?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Mr. Speaker, Sir, whatever commitment was made by the former Hon'ble Chief Minister will be duly honoured. But the question is that the Hon'ble former Chief Minister, Chaudhri Bansi Lal, did not make **a** categorical commitment that the road will be constructed or completed by such and such date. As the hon. Member has himself admitted, it just involves a cost of Rs. 47 lakhs. It is one road which is 46 kms. in length. Practically all villages on this road are already connected from one way or the other. Since this is a case of duplicate links, the Government is not in a position to construct it now or within a very short span of time.

श्री अमर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को इल्म है कि बवानी खेड़ा नई तहसील बनी है और वहां पर लोगों को 40— 40 मील दूर से अपने काम के लिए आना पड़ता है? जैसे कि

सिवानी वाया छाडुवा और पहले मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल ने इसे बनवाने की कुमिटहेंट भी की थी क्योंकि यहां पर बहुत इंटीरियर से लोगों को आना पड़ता है । क्या इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस सड़क को बनाने की कृपा करेंगे?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Mr. Speaker, I have already replied to the question. The Government would certainly consider the desirability of completing this road to facilitate the movement of people to T,ehsil Head-quarters, Bawani Khera. But an amount of Rs. 47 lakhs means some thing and for one road, I am afraid, cannot be spent.

Floods Affected Villages.

*1578. Chaudhri Phul Singh Kataria : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total number of villages affected due to recent floods in Rohtak district and particularly in Jhajjar Tehsil and the details of facilities being provided to the floods affected people in the villages which are still under flood water together with the number of those villages which are still surrounded by the floods water as at present ;

(b) the names and the exact location of the roads which were washed away by the recent floods water in Tehsil Jhajjar of district Rohtak and the steps being taken by the Government to construct all metalled roads to link those gaps which were washed away by the floods water ; and

(c) the number of Harijan families which were affected on account of recent floods in Tehsil Jhajjar of

district Rohtak and the total amount of compensation paid by the Government to those floods affected families ?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma) :

(a and b) A statement is laid on the Table of the House.

(c) 992 Harijan families were affected by the recent floods in Jhajjar Tehsil. The value of relief given by the Government in the form of (i) loans for house repair (ii) loans for purchase of seed, Fodder etc. (iii) suspension of taccavi loans and (iv) house repair grant to these families is Rs. 2, 92,935/-,

Statement

(a) 212 villages of Rohtak District were affected by the recent floods, out of which 98 villages are in Jhajjar Tehsil. The details of the facilities provided to the flood affected people of Rohtak district are as under :—

1. House repair grant. Rs. 2,00,000

2. Loans for house repair. Rs, 3,00,000

3. Loans for purchase of fodder/seed etc. Rs. 7,00,000

4. Suspension of recovery of Land Holding Rs. 5,97,704

Tax in eluding Cess,

5. Suspension of recovery of Taccavi loans. Rs, 3,76,101

6. Sirkis for temporary shelter.
3,940 Nos.

7. Empty cement bags for protection of
46,200 Nos.
village abadis.

8. Dewatering of flood water Rs. 10,85,363

No village in Jahjjar Tehsil is at present surrounded by the flood water or under flood water.

Sr. No.	Name of Road	location portion. Exact affect From K.M.	of To K.M.	Steps bein taken to restore the washed away gaps.
1	2	3	4	5
1.	Matanhail Kosli Road.	10.15	11.50	Immediate repair such as patch work has been done and the road is motorable, The reach requires trengthening and this will be completed by close

				of financial year.
2.	Akheri Madan pur to Mundehra	0.00	1.00	Immediate repairs to the road have been done. The reach is being raised and strengthened. The road is open to traffic.
3.	Chhuchakwas Koyalpuri road.	2.00 6.50	4.00 7.50	Material required for repairs is being collected. The repairs will be taken up shortly. The road is open to traffic
4.	Jhajjar Chhuchakwas road (Z. P.)	5.50	8.00	Immediate repairs such as patch work has been done. The reach requires strengthening for which material is being collected. The road is open to traffic.
5.	Dighal Beri Chhuchakwas	12.00	14.40	Immediate repairs such as patch

	road.			work has been done and earth work on berms has been restored. The reach requires strengthening for which material is being collected. The road is open to traffic.
6.	Charra Dujana Beri Kalanaur road.	15.00	17.00	Immediate repairs such as patch work has been done and earth work on berms has been restored. The reach requires strengthening for which material is being collected. The road is open to traffic.
7.	JhajjarDhaur road.	0.00	1.00	Immediate repairs such as patch work has been done. The reach requires strengthening which is being

				done. The road is open to traffic.
8.	Rohtak Jhajjar Rewari road.	30.30 33.10 33.70	32.20 33.70 35.20	Immediate repair such as patch work has been done. The reaches require raising and earth work for raising is under progress. Collection of material is also being done. The road is open to traffic.
9.	Jhajjar Subana road.	0.00 5.00 6.80 8,30 16,60 17,40	2.20 6.00 7.00 9.30 17.20 18.10	immediate repair such as patch work has been done and earth work on berms has been restored.. The reaches require strengthening for which material is being collected, The road is open to traffic.

10.	Jhajjar Charra road.	0.00 8.00	0,20 9.00	Immediate repair such as patch work has been done and earth work on berms has been restored. The reaches require strengthening for which material is being collected. The road is open to traffic.
11.	Dighal Sampla (Upto Kultana) . ,	6.90	7.60	Immediate repair such as patch work has been done and earth work on berms has been restored. The reaches require strengthening for which material is being collected. The road is open to traffic.
12.	Jhajjar Badli road.	9.00	14.00	Immediate repair such as patch work has been done and earth work on berms has

				been restored. The reaches require strengthening for which material is being collected. The road is open to traffic.
13.	Badli Ladpur Munimpur road.	0,60 3.80	0,80 4,20	Repairs have been carried out. The road surface has been patched and earth work on berms restored, The road is open to traffic.
14.	Badli Pelpha road.	0.70 2.50	1.30 2.70	Repairs have been carried out. The road surface has been patched and earth work on berms restored. The road is open to traffic.
15.	Village approach road from Jhajjar Gurgaon road to village Munimpur via Kaloi.	0,00	0,93	The damaged length requires raising and reconstruction. Earth work is

				under progress.
16.	Jhajjar F. Nagar road to Sondhi.	1.00	2.20	Repairs are under progress. The road is open to traffic.
17.	Kheri Sultanpur road.	0.00	3.00	The damaged length requires raising and reconstruction. Earth work is under progress. The road is open to traffic.
18.	Village approach road from Jhajjar Subana road to village Saludha.	0.00	1.00	Immediate repair such as patch work has been done. The reach requires strengthening and this work is under progress. The road is open to traffic,
19.	Jhajjar Jhazgarh Chhuchakwas Dadri (Up to Boundary) road.	0.00	2.00	Immediate repair such as patch work has been done and earth work on berms restored. The road

				is open to traffic.
20.	Bahadur Garh Jhajjar road.	15.40 16.30	15.60 18.00	Immediate repair such as patch work has been done and earth work on berms has been restored. The road is open to traffic.

चौधरी फूल सिंह कटारिया: स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि हरिजनों को मकान की मरम्मत, चारा, बीज आदि के लिए इतना रुपया दया गया । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास कुछ आदमियों की शिकायत. आई है कि जिनके मकान टूटे फूटे हैं उनको कुछ नहीं मिला?

Pandit Chiranji Lal Sharma: No such complaints have come to my notice or that of Government. However, it is possible complaints might have come to the notice of the Deputy Commissioners, who may he looking into the grievances. .

मलिक सतराम दास बत्तरा : स्पीकर साहब, रोहतक और खासकर झज्जर तहसील में कभी फ्लड आता है और कभी फैमिन हो जाता है, क्या मंत्रो महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहाँ पर रैगुलर पानी को सप्लाई और उस फ्लड के पानी के निकास के लिए कोई लौंग टर्म योजना बनाने का सरकार का विचार है

Pandit Chiranji Lal Sharma: As for famine, Sir, **I** wish to inform the Hon. Member that Jawahar Lal Nehru Project has been started. It will give lot of relief to some villages in Tehsil Jhajjar. As for floods, ways and means are being found out to give requisite relief to the people.

चौधरी रिजक राम : क्या मत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो हाउस रिपेयर के लिए ग्रान्ट दी गई है वह कितने रुपए की दी गई हे?

Pandit Chiranji Lal Sharma: Well, it all depends upon the extent of damage to a particular house, but maximum upto Rs. 300/—

श्री अमर सिंह रू क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करते कि जो तीन सौ रुपया दिया गया है वह कितने हल्कों में दिया गया है?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Well, Sir, I don't know whether the Hon. Member needs the information for Tehsil Jhajjar or some villages of that Tehsil. Let him make the question clear.

Shri Amar Singh: I want to know about Tehsil Jhajjar.

Padint Chiranji Lal Sharma: The total amount is Rs. 70,000.

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मं वी महोदय बताने की कृपा करेगे कि झज्जर तहसील में तीन–तीन सौ रुपया कितने

आदमियों को दिया गया हे?

Pandit Chiranji Lal Sharma: For that a separate nitice is needed. **I** am not now in a position to give categorical information.

चौधरी फूल सिंह कटारिया : मंत्री महोदय. ने झज्जर तहसील में बीस सड़कों की लिस्ट दो है जिन पर काम चल रहा हे । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे. कि सीरियल नम्बर 3 पर छूछकवास कोयलपुरी सड़क है और वहाँ मैटिरियल भी पड़ा हुआ है वहाँ पर पुल भी बनेगा या नहीं?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Mr. Speaker, Sir, we would certainly provide bridges wherever necessary. But during these rains, heavy damage has been caused to the roads. A sum of Rs. 60 lakhs is required for special repairs and necessary repairs are being carried out to whatever extent is possible.

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सीरियल नम्बर आठ पर जो सड़क झज्जर रोहतक है वहां पर 1970 से मैटिरियल पड़ा हुआ है और उसको ऊंचा चौड़ा करने के लिए सोलिग भी हुआ हुआ है लेकिन वह सड़क पूरी नहीं हुई है, क्या इस साल में उसको पूरा करने की कृ पा करेंगे?

Pandit Chiranji Lal Sharma :The decision, just to widen this road, has been taken much earlier and it is being widened in stages. It will be completed as early as possible. Of

course, it all depends upon availability of funds.

मलिक सतराम दास बत्तरा : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रोहतक सैं भिवानी को सडक जो काफी दिनों में खराब है उसको कब तक ठीक कर दिया जाएगा?

Pandit Chiranji Lal Sharma : I hope. we will be in a position to complete this road by the end of this financial year. The work is in progress. Hundreds of labourers are working on this and I have myself been to this road.

तारांकित प्रश्न सं ० 1425

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, चौधरी राम लाल वधवा, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

तारांकित प्रश्न सं ० 1441

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्यों कि डस समय माननीय सदस्य, चौधरी दल सिंह, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Construction of Houses by the Housing Board

***1518. Shri Om Parkash Garg:** Will the Minister for Finance be pleased to state--

(a) the district-wise and category-wise total number of houses constructed by the Housing Board., Haryana, since its constitution to-date together with the places of location thereof;

(b) the district-wise and category-wise number of

houses the possession of which has been given to the allottees and the time by which the possession of the remaining houses mentioned in part (a)above is likely to be given to the remaining allottees; and

(c) the category-wise number of houses which are proposed to he constructed by the Board in the year 1976 in district Kurukshetra?

गृह एंव स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी) :

(क) तथा (ख) सूचना विवरण के रूप में सदन की मेज पर रखी जाती है ।

(ग) कुरूक्षेत्र में वर्ष 1976 के दौरान, 94 माई, 155 लाई और 135 ईः डबल्यु : एस श्रेणी के मकान बनाये जाने का विचार है ।

विवरणिका'

(क) प्रत्येक जिले में जिस–जिस श्रेणी के मकान आवास बोर्ड द्वारा बनाये गये हैं

उनका ब्योरा निम्न प्रकार है :–

क्र.स.	जिले का नाम	जगह जहां मकान बनाये गये हैं	मकानों की ईः डब्ल्यू	श्रेणीवार संख्या कुल लाईः	माईः	जोड़

एसः

1	गुडूगांवा	फरीदाबाद सै क्टर–7	500	-	-	
		फरीदाबाद सैक्टर–22	468	252	164	
		जोड़	968	252	164	1,384
2	करनाल	पानीपत	109	32	78	
		करनाल	244	64	132	
		जोड़	353	96	210	659
3	अम्बाला	अम्बाला	119	44	48	
		यमुनानगर	117	6	25	
		पंचकूला	147	84	51	
		जोड़	383	134	124	641
4	सोनीपत	सोनीपत	129	16	78	223
		कुल जोड़	1,833	498	576	2,907

(ख) जिलेवार तथा श्रेणीवार मकानों की संख्या, जिनका कब्जा अलाटियों को दे दिया गया है, निम्न प्रकार है :–

क्रः सः	जिले का नाम	जगह जहां मकान बने हैं	मकानों की ईः डब्ल्यूरू एसः	श्रेणीवार लाईः	संख्या भाईः	कुल जोड़
1	गुडगावा	फरीदाबाद सैक्टर–7	500	-	-	
		फरीदाबाद सैक्टर–22	468	252	164	
		जोड़	968	252	164	1,384
2	करनाल	पानीपत	109	32	77	
		करनाल	177	53	63	
		जोड़	286	85	140	511
3	अम्बाला	अम्बाला	59	3	26	
		यमुनानगर	117	6	24	
		पंचकूला	130	30	30	
		जोड़	306	39	80	423
4	सोनीपत	सोनीपत	129	16	78	223

कुल जोड़	1,689	392	462	2,543

शेष मकानों का कब्जा अगले दो मास में दिये जाने की सम्भावना है ।

श्री गुलाब सिंह जैन : क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि हिसार जो एक बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियल टाउन है और डिविजनल हैडक्वार्टर भी है सरकार वहां हाउसिंग कालोनी बनाने की कृपा करेगी?

श्रीमती शारदा रानी : जी हां । इसके लिए जमीन भी ऐक्वायर की जा रही है ।

श्री प्रेम सुखदास : क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि सिरसा जो एक नया जिला बना है वहां पर भी हाउसिंग कालोनी बनाने की कृपा की जाएगी?

श्रीमती शारदा रानी : जी हां, वहां पर भी बनाने का विचार कर रहे हैं और वहां पर भी जमीन ऐक्वायर की जा रही है ।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : स्पीकर साहब., कुछ ऐसे अलौटीज हैं जिनका मकान अलाट हुए हैं और उन्होंने उन मकानों को आगे किराए पर उठा दिया है । क्या मती महोदया बताने की कृपा करेंगी कि उनकी अलाटमैंट कैन्सिल करके जिनके पास

मकान आदि नहीं है उनको दिया जाएगा?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, हमारे नोटिस में ऐसी कोई चीज नहीं है । अगर मैम्बर साहब के नोटिस में ऐसी चीज हो और अगर वह हमारे नोटिस में लाएंगे तो उनकी इच्छानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि रोहतक जिला जो सब से बड़ा जिला है वहां पर भी हाउसिंग कालोनी बनाने का विचार है और अगर है तो कब तक?

श्रीमती शारदा रानी : वहां पर कालोनी बन रही है और 1976– 77 के अन्त तक बन जाएगी ।

श्री के ० एन ० गुलाटी : स्पीकर साहब, वैसे तो हाउसिंग बोर्ड का काम काबिले तारीफ बुश लेकिन हाउसिंग कालोनीज में जो सड़कें बनती हैं वह बारिश के दिनों में टूट जाती हैं और वहां पर पानी इकटठा हो जाता है जैसे कि फरीदाबाद में 22 सैक्टर में हुआ है । क्या मंत्री महोदया इस कठिनाई को दूर करने की कृपा करेंगी?

श्री अध्यक्ष : यह सप्लीमेन्टरी इस क्वैश्चन से अराइज नहीं होता ।

राव बंसी सिंहः क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा

करेंगी कि जिला महेन्द्रगढ में हाउसिंग कालोनी बनाने का विचार है और अगर है तो कब तक?

श्रीमती शारदा रानीः अध्यक्ष महोदय, नारनौल में इस प्रकार की कालोनी बनाने का इरादा है ।

लाला गौरी शंकर : क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि जींद में जो हाउसिंग कालोनी बन रही है वह कब तक बनकर तैयार हो जाएगी और हाउसिज कब तक अलाट हा जाएंगे. श्रीमती शारदा रानी अध्यक्ष महोदय, वहां पर 1976–77 के अन्त तक काम पूरा हो जाएगा ।

चौधरी पीर चन्द : क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि हिसार और सिरसा के अन्दर जमीन ऐक्वायर करने का काम 1976–77 के अन्दर कम्पलीट हो जाएगा?

श्रीमती शारदा रानीः स्पीकर साहब, हिसार और सिरसा में जमीन ऐक्वायर करने का काम 1976–77 में पूरा हो जाएगा ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मंत्री महोदया बताने की कृ पा करेंगी कि जिला स्तर में नीचे भी हाउसिंग कालोनी बनाने का विचार है?

श्रीमती शारदा रानी : जी हां, फरीदाबाद जिला स्तर से नीचे है, राई जिला स्तर से नीचे है, पानीपत जिला स्तर से नीचे है और यमुनानगर जिला स्तर से नीचे है । इन जगहों पर हम

हाउसिंग कालोनीज बना रहे हैं ।

चौधरी मेहर चन्द : क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि हमारे हिस्से में भी कोई हाउसिंग कालोनी आएगी कि नहीं?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, उनके हिस्से में कहां बनाने से आ सकती है?

Mr. Speaker : Housing colonines are not meant for the Hon. Members

चौधरी रामजी लाल डागर : स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहिबा यह बताने की कृपा करेंगी कि हाउसिंग कालोनी बनाने का क्या क्राइटेरिया है?

श्रीमती शारदा रानी : जहां पर आवश्यकता होती है वहां पर हाउसिंग कालोनी बनाई जाती है और साथ–साथ जमीन और फण्डज का भी ध्यान रखा जाता है ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: क्या मन्त्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि पिपली और लाडवा में भी कोई हाउसिंग कालोनी बनाने का सरकार का विचार है?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इंडस्ट्रीयल टाऊन्ज को प्राथमिकता देना, यह सरकार की नीति है । जहां इंडस्ट्रीयल लेबर है वहां हाउसिंग प्रौबलम्ज

एक्यूट होती हैं । वैसे जरूरत तो बहुत जगह होती है । उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर्ज को प्राथमिकता देते हैं ।

राव अभय सिंह : स्पीकर साहब, अभी मुख्य मन्त्री महोदय ने बताया कि ऐसे टाऊन्ज को प्राथमिकता दी जाती है जो कि एंडस्ट्रियल टाऊन्ज होते हैं । मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि रिवाडी जो एक इंडस्ट्रीयल टाऊन है क्या वहां पर भी कोई हाउसिंग कालोनी बनाने का सरकार का इरादा हे?

श्री बनारसी दास गुप्त : अध्यक्ष महोदय, रिवाडी में ऐसी लेबर नहीं है जो बाहर से आकर काम करते हों । वहां पर तो पहले ही लोगों ने अपनी काटेज इंडस्ट्रीज लगा रखी हैं और उनके रहने का प्रबन्ध पहले से ही है ।

श्री गुलाब सिंह जैन : स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर महोदया बताएंगी कि हिसार में जो जमीन एक्वायर की गई है वहां पर कब तक हाउसिंग कालोनी बन जाएगी और वहां पर कितने मकान बनाने की सरकार की योजना है?

श्रीमती शारदा रानी : इस बारे में आनरेबल मैम्बर अलग से नोटिस दें तो हम बता देंगे ।

श्री के०एन० गुलाटी : क्या मिनिस्टर साहिबा यह बताएंगी कि बल्लभगढ का जो एरिया है क्या वहां पर सरकार हाउसिंग कालोनी बनाने का विचार रखती है?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, अगर गुलाटी साहब फरीदाबाद से आगे नम्बर आने दें तो बल्लभगढ में भी हाउसिंग कालोनी बनाने का विचार किया जा सकता है । वैसे फरीदाबाद और बल्लभगढ के बीच में बनाई हुई हए ।

Bus Stand in Bawal Constituency

***1553. Chaudhri Ram Parshad : Will the Minister for Transport be** pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Bus Stands at the following places in the Bawal Assembly Constituency-

(i) Bawal Balni, (iii)Pranpura, (iv) Khandora, (v) Tankari,

(vi) Bharwas and (vii) Khori; and

(b) if so, the time by which the Bus Stands at the said places are expected to be constructed?

शिक्षा तया परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) :

(क) नहीं ।

(खां) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

चौधरी राम प्रशाद : स्पीकर साहब, मैंने यह पूछा था कि बावल कांस्टीचुएन्सी में कुछ जगहों पर बस–स्टैन्ड बनाए जाएगे कि नहीं । पिछली बार इन्होंने कहा था कि बनाए जाएने

और अब कहते हैं कि प्रश्न ही नहीं उठता । इस का कारण क्या है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, वावल में एक क्यू–शैल्टर बनाने का सरकार का विचार है, जिसका काम 1975–76 में पूरा होने की संभावना है ।

श्री गुलाब सिंह जैन : हिसार में बस स्टैन्ड बनाने के लिये लाइव स्टाक फार्म की जमीन एक्वायर की गई थी और वहां पर कुछ दुकानें बनी हुई थीं जो लीज पर दी हुई थीं, अब ऐडमिनिस्ट्रेशन वाचं न तो उन दुकानों का कब्जा ही देते हैं और न ही वहां पर बस स्टैण्ड बनाया जा रहा है । क्या सरकार इस तरफ कोई ध्यान देने की कृपा करेगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : आनरेबल मेम्बर इस के लिये अलग से नोटिस दें ।

चौधरी राम प्रशाद : स्पीकर साहब, हमारे हल्के में एक खोरी गांव है । सरकार इस गांव को आदर्श गांव बनाने जा रही है और अभी वहां इंदिरा चक्रवर्ती जी ने जाकर नींव पत्थर भी रखा है । अब हम यहां पर बस स्टैण्ड बनाने के बारे में मन्त्री महोदया से पूछ रहे हैं तो वे कहती हैं कि अभी इसका प्रश्न ही नहीं उठता । प्रश्न क्यों नहीं उठता?

(कोई उत्तर नहीं गया)

चौधरी फूल सिंह कटारिया : स्पीकर साहब क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि झज्जर में पहले जो बस स्टैण्ड था, वहां पानी भर गया है और लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है । सरकार कब तक वहां नया बस स्टैण्ड बनाने का विचार रखती है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : इसके लिये आनरेबल मेम्बर अलग से नोटिस दें । वैसे मैं आनरेबल मेम्बर की जानकारी के लिये बता देती हूं कि जो भी बड़ी बड़ी जगहें हैं वहां पर यह काम बड़ी जल्दी से किया जा रहा है । जैसे जैसे पैसा मिलता जाएगा, काम और तेजी से होगा ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : स्पीकर साहब, कोई तीन दिन की बात हए, इन्होंने कहा था कि झज्जर में बस स्टैण्ड बहुत ही जल्दी बन जाएगा और अब यह कह रही हैं कि जैसे जैसे फण्ड मिलता जाएगा, काम और तेजी से होगा ।

Mr. Speaker : Well, questions are not for cross-examination. These are for seeking information. You are already in possession of the information.

चौधरी पीर चन्द : क्या मिनिस्टर साहिबा बताने की कृपा करेंगी कि उकलाना में' भी बस स्टैण्ड बनाने की सरकार की कोई योजना है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : आनरेबल मेम्बर डसके लिये अलग से नोटिस दें ।

Common Facility Workshops in the State

***1555. Rao Dalip Singh:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the district-wise total number of Common Facility Workshops set up in the State to-date;

(b) the present strength of staff working in each Common Facility Workshop;

(c) the total amount invested on machinery and equipmert in each Common Facility Workshop; and

(d) the total turnover of services rendered in each Common Facility Workshop during 1974-75 to-date?

Mr. Speaker: Extension has been sought for answering this question which has been granted. The communication received from the Minister concerned in this connection is as under-

D.O.No. 117—ECI-76/224

"Maha Singh Minister

Agriculture Deptt. Haryana, Chandigarh.

Chandigarh, Dated the 31-1-76

Subject:—Starred Assembly Question No.1555 asked by Rao Dalip Singh, M.L.A. regarding Common Facility

Workshops.

Dear Shri Sarup Singh,

I write to inform you that starred assembly question No. 1555 asked by Rao Dalip Singh, M.L.A, was received in the Secretariat (in Development & Panchayat Department) on the 7th Jan., 1976. The date fcr answer of this question has not yet fixed. As most of the information pertaining to this question is yet to be collected from twenty four common facility workshops located at different development Blocks, I shall, therefore, feel grateful if a time for 3-4 weeks is given for the purpose.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/—

(Maha Singh)

Ch. Sarup Singh,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh."

Bus Service to Morni

***1559. Shri Jagjit Singh Tikka:** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a Bus Service operates Upto Morni *via* Thapli only in fair weather; and

(b) if so, the time by which Bus Service to Morni is likely to operate in all weather conditions?

शिक्षा तथा परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) :

(क) जी हां ।

(ख) हरियाणा राज्य परिवहन मोरनी तक सभी ऋतुओं में बस सेवा मोरनी तक पक्की सडक पूरी हो जाने पर चलायेगी ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदया ने अपने उत्तर में कहा है कि हरियाणा राज्य परिवहन बस सेवा मोरनी तक पक्की सड़क पूरी हो जाने पर चलाई जाएगी । क्या वे बताने की कृपा करेंगी कि सरकार ने जिस तरह से मल्लाह में ट्रांसपोर्ट बस सेवा बगैर पक्की सड़क के चालू कर रखी है, अगर पी० डब्ल्यु ० डी० वाले अभी उसी तरह की कच्ची सड़क बना दें तो उसी प्रकार मोरनी में बस सेवा चालू कर दी जाएगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, जब सड़क बन जाएगी उसके बाद ही देख सकते हैं कि उस पर बस सेवा चालू हो सकती है कि नही ।

Construction of Tehsil Building at Bawani Khera

***1565. Chaudhri Amar Singh:** Will the Minister for

Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Tehsil building at Bawani Khera in Bhrwani District; if so, the time by which this building is likely to be constructed ?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma) : There is no proposal as yet The time when this construction work would be taken up cannot be anticipated at this stage, as this would depend on the availability of funds.

श्री अमर सिंह : क्या मिनिस्टर साहब बताएगे कि दूसरी विल्डिग्ज बनाने के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की गई है उसके लिये कोई जमीन ऐक्वायर की गई है था नही?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, the Government proposes to just construct judicial complexes/court complexes at all district headquarters and also at sub-divisional headquarters. The judicial complexes/court complexes have already come up in Hissar and Gurgaon. In Kurukshetra, Bhiwani and Sonepat the construction has been started. So far as the question of constructing tehsil building at Bawani Khera is concerned, for the present the build ng at the disposal of the tehsil is sufficient and the work will definitely be started when the Government is in a position to spend.

श्री गुलाब सिंह जैन : क्या मिनिस्टर साहब बताएगे कि हिसार में जो मिनि सैक्रेटेरिएट की कंस्ट्रकशन का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, उस को सरकार कब तक स्टार्ट करने जा रही है?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Atleast I have no knowledge of the fact that the work of constuction of Mini-

Secretariat has been held up. I shall certainly look into it.

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मिनिस्टर साहब बताएगे कि बहादुरगढ़ में मिनि सैक्रेटेरिएट कब तक बन जाएगा?

Pandit Chiranji I al Sharma : Bahadurgarh has recently become a Sub-Division and the Government is proposing to acquire some land and the question of construction of building thereon will arise at a later stage.

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि ट्रेजरी की बिल्डिंग के लिये अलग से प्लान है । क्या उनके नोटिस में यह बात है कि ट्रेजरी का कार्यालय रैस्ट हाउस में है और चूकि ट्रेजरी की बिल्डिंग का कार्य बहुत जरुरी है अत सरकार कब तक वह बिल्डिंग बनाने का विचार रखती है?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Yes, I am aware of the fact that the Rest House building is being used for the tehsil. As for the strong room, we will certainly look into it.

श्री प्रेम सुख दास : स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब बताएगे कि सिरसा जिला जो कि अभी–अभी बना है, वहां पर भी मिनि सैक्रेटेरिएट बनाने का सरकार का कोई विचार है?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sirsa has recently come into being is a District, Sir, and the same policy will apply to Sirsa district also.

Physical Possession of Residential Plots to the Harijan and Landless Persons

***1579. Chaudhri Phul Singh Kataria : Will the** Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the tehsil-wise total number of Harijan and landless persons who have been given physical possession of plots in Districts of Rohtak, Mohindergarh and Sonepat during the last 3 years ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide plots to the Harijans and landless persons in urban area of the State?

Mr. Speaker : Extension has been sought for answering this question, which'has been granted. The communication received from the Minister concerned in this connection is as under-

''चिरंजी लाल, अ. सः पत्राकः टी. ओ एस. डी. 76 / 1844

मंत्री, राजस्व विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ

दिनांक 19— 1—76

विषय :— चौधरी फूल सिंह कटारिया, एम० एल० ए० द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न नं ० 1579 जिसका उत्तर 21—1—76 को देय है ।

प्रिय श्री सरुप सिंह जी

कृपया तारांकित विधान सभा प्रश्न नं ० 1579 जो कि 2 1– 1– 76 की सूची में चौधरी फूल सिंह कटारिया, एम. एल. ए. के नाम से है, की ओर ध्यान देने का कष्ट करें । इस प्रश्न का उत्तर अभी तक तैयार नहीं है क्योंकि सम्बन्धित उपायुक्तों से प्राप्त हुई सूचना अधूरी है । इस सूचना को एकत्रित करने के लिये समय चाहिये । अतः आपसे प्रार्थना है कि इस प्रश्न को 3–2–78 के बाद किसी तिथि को उत्तर के लिये निश्चित कर दिया जाये ।

श्री सरुप सिंह आपका

अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा, हस्ताक्षरित

चण्डीगढ ।''

(चिरंजी लाल)

Mr. Speaker : The Question hour is over.

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Absorption of Engineers and Overseers in the State.

***1412. Chaudhri Ram Lal Wadhwa :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether the requirement of the State Government for providing employment to the Engineers and Overseers is less than the number of students who finally pass the Engineering and Overseers' courses every year from the institutions in Haryana ; and

(b) if reply to part (a) above is in the affirmative, the steps taken by the Government to absorb all such Engineers and Overseers?

राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल शर्मा):

(क) व (ख) सूचना इकट्ठी करने में जो समय और परिश्रम लगेगा उस से विशेष लाभ न होगा ।

Government and privately owned Agricultural Tubewells in the State

***1440. Chaudhri Dal Singh : Will the Minister for Irrigation and Power b pleased to state-**

(a) the total number of Government and Privately owned Agricultural Tubewells in the State as on 31/3/68 and 31/3/75, separately ; and

(b) the total area irrigated by privately owned and Government owned Agricutural tube wells in the State during the years 1968 and 1975, separately?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) :

(अ) सरकारी और निजी नलकूप 31—3—68 और 31—3—75 को कार्य कर रहे थे उनका विवरण निम्नलिखित है —

क्रम संख्या	नलकूपो की संख्या

	गहरे सरकारी नलकूप	31-3-68	31-3-75
	सीधी सिंचाई के गहरे		
1	नलकूप	634	1039
2	सरकारी आवर्धक नलकूप	280	923
3	निजी कृषक नलकूप	388989	1914

(ब) निजी नलकूपों द्वारा सीचा गया क्षेत्र और सरकारी नलकूपों पर वर्ष 1968 और 1975 को खर्च हुई विद्युत की यूनिटस निम्नलिखित हैं –

क्रम संख्या	सींचा गया क्षेत्र	वर्ष 1968		वर्ष 1975	
1	निजी कृषक नलकूप	329114	हैक्टेयर	883000	हैक्टेयर
	गहरे सीधी सिंचाई के				
2	सरकारी नलकूप	21011339	यूनिटस	12358000	यूनिटस
		77769	हैक्टेयर	48000	हैक्टेयर
	सरकारी आवर्धक				
3	नलकूप	5892760	यूनिटस	50333000	यूनिटस

गहरे नलकूपों से सींचे गये क्षेत्र की बुकिंग उस नहर के सींचे गये क्षेत्र में सम्मिलित है जिसमें इनका पानी डाला गयी ।

Judicial Courts At Kurukshetra

***1517. Shri Om Parkash Garg :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the date by which the Judicial Courts are expected to be opened at Kurukshetra ; and

(b) whether any arrangement for housing the said Courts has been made at Kurukshetra and, if not, the time by which the same is likely to be made?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) :

(क) – 19–1–76 से केवल एक कोर्ट ।

(ख) – हां, प्रश्न नही उठता ।

Text-Books and Exercise Books Supplied to Students

***1530. Chaudhri Chand Ram :** Will the Minister for Education be pleased to state the names of Agencies through which the prescribed Text-Books and Exercise Books etc., at controlled prices are proposed to be supplied to students in the State at School, Colleges and University stages?

शिक्षा मंत्री (श्रो माडू सिंह मालिक) : आवश्यक सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाती है ।

विवरणिका

पाठ्य पुस्तके

विद्यालय स्तर

प्रारम्भिक तथा माध्यमिक कक्षाओं की पाठ्य–पुस्तकें नियन्त्रित मूल्यों पर नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा के अधीन कार्य कर रहे सरकारी पाठ्य पुस्तक बिक्री केन्द्रों द्वारा अनुमोदित बिक्री एजैन्टों तथा विद्यार्थी–स्टोरों के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध की जाती हैं ।

9 वीं, 10 वीं तथा 11 वीं कक्षाओं की पाठ्य प्रूस्तके विद्यार्थियों को नियन्त्रित मूल्यों पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अपने बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध की जाती हैं । प्राइवेट प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को नियन्त्रित मूल्यों पर प्रकासको की अपनी व्यवस्था अनुसार उपलब्ध की जाती हैं ।

महाविद्यालय / विश्वविद्यालय स्तर

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों / विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए नियत पाठ्य पुस्तकें दो श्रेणियों में बांटी गई हैं –

(1) विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तके ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परन्तु प्राइवेट प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें ।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकें, विश्वविद्यालय प्रैस, पुस्तक विक्रेताओं एवं महाविद्यालय स्टोरों के माध्यम से उपलब्ध की जाती हैं । प्राईवेट प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तके उनकी अपनी वितरण व्यवस्था/पुस्तक विक्रेताओं द्वारा वितरित की जाती हैं ।

अभ्यास पुस्तिकाएं

अभ्यास पुस्तिकाएं विद्यार्थियों को नियन्त्रित मूल्यो पर विद्यालया/महाविद्यालय– विद्यार्थी–स्टोरों के माध्यम से उपलब्ध की जाती हैं । ये अभ्यास पुस्तिकाएं हरियाणा में कार्य कर रहे अनुमोदित निर्माताओं द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय विद्यार्थी–स्टोरों में उपलब्ध की जाती हैं ।

विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए अभ्यास पुस्तिकाएं बेचने की एजेन्सी स्वयं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है ।

Rural Indebtedness

***1425. Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Revenue be pleased to state the steps taken by the State Government to abolish the rural indebtedness in the State under the Twenty-Point Economic Programme announced by the Prime Minister?

राजस्व मन्त्री (पंडित चिरन्जी लाल शर्मा) : ग्रामीण कर्जा को हरियाणा में समाप्त करने के लिये वर्णित श्रेणियों के व्यक्तियों से अपेक्षित कर्जो की वसूली पर प्रथम पग के रुप में कानून बनाकर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । यह प्रतिबन्ध सर्व प्रथम एक वर्ष की अवधि के लिये लागू होगा । राज्य सरकार के पास इस अवधि को समय समय पर क्ष दो वर्ष तक बढ़ाने का प्राधिकार है । कुछ प्रकार के कर्जो को घटाने/समाप्त करने के लिये विधेयक बनाने पर विचार हो रहा है ।

Test Report For Electricity Connections For Agricultural

Tubewells

***1441. Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total number of Test Reports for Electric connections for Agricultural Tubewells pending with the Haryana State Electricity Board as on 31.3.75 ; and

(b) the time by which electric connections for the Agricultural tubewells as referred to in part (a) above are likely to be given to the farmers ?

Chief Minister (Shri Banarsi Dass Gupta) : (a) 8361.

(b) By end of March, 76 subject to the availability of funds and material.

Sub-Treasury Office

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

494. Chaudhri Amar Singh: Will the Minister for Finance be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Treasury Office at Bawani Khera in Bhiwani District; if so the time by which the Treasury is likely to be opened there ?

वित मंत्री (श्री राम सरन चंद मित्तल) : जी हां, श्रीमान् जी, वबानी खेड़ा, जिला भिवानी में नान–बैकिंग उप–खजाना खोलने का प्रस्ताव है । जैसा ही उप–खजाना भवन, सुदृढ़ कल तथा करैसी चौस्ट के निर्माण हेतू धन राशि उपलब्ध होना सम्भव हो जायेगी, वहां पर उप–खजाना खोल दिया जायेगा

Patwaris in the States

495. Rao Dalip Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the district-wise total number of Patwaris in the State as at present :

(b) the district-wise number of Patwaris, out of those referred to in part (a) above who are substantive permanent ; and

(c) the district-wise number of Patwaris, who have more than five years and ten years of service but have not been confirmed so far 7

"**Assembly Business**

Most Immediate

Subject:—Un-starred Assembly Question No, 495.

Will the Secretary, Haryana Vidhan Sabha, kindly refer to the subject noted above ?

2. The reply to the Un-starred Assembly Question No. 495 appearing in the list of Un-starred Questions, on the 21st January. 1976, in the name of Rao Dalip Singh, M.L.A., is not ready. The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/

Revenue Minister, Haryana.

To

The Secretary,

Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh.

U.O. 230-ARSII (4)-76/344,
Chandigarh, dated the

20th Jan., 1976'.

Model Village in Tehsil Mahendergarh.

496. Rao Dalip Singh : Wrll the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether the Government has decided to develop the village Sigri (Gandhi Nagar) in tehsil Mahendergarh in a Model village ; and

(b) if the reply to part (a) above is in the affirmative, the stage of the development work in the said village ?

कृषि मंत्री (कर्नल महा सिंह) : (ए) नहीं ।

अनुपस्थिति की अनुमति

Mr. Speaker : I have received an application from Chaudhri Ram Lal, M.L.A., asking for leave of absence from the House because he is unable to attend this session as he has been detained under MISA in Central Jail, Ambala.

Mr. Speaker : Question is—

That the permission for leave of absence be granted.

The motion was carried,

वर्ष 1976–77 के बजट पर अनुदानों की मांगो पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : According to the past practice and in order to save the time of the House, all the Demands for Grants appearing on the Order Paper will be deemed to have been read and moved together:—

That a sum not exceeding Rs. 27,32,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the

course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 1—Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 4,63,52,677 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 2—General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 12,32,50,840 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 3—Home Department.

That a sum not exceeding Rs. 3,28,31, 470 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 4—Revenue Department.

That a sum not exceeding Rs. 1,52,33,251 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 5—Excise and Taxation Department.

That a sum not exceeding Rs. 3.79,02,395 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 6—Finance Department.

That a sum not exceeding Rs. 2,02,93,436 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 7—Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 20,04.29,730 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No.8—Buildings and Roads Department.

That a sum not exceeding Rs. 35,85.60.030 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No . 9—Education Department.

That a sum not exceeding Rs. 17,20,85,770 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 10—Medical and Public Health Departments.

That a sum not exceeding Rs. 10,82,53,140 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 11—Urban Development Department.

That a sum not exceeding Rs. 2,01,94,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 12—Labour and Employment Departments.

That a sum not exceeding Rs. 2,86,25,840 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 13—Social Welfare and

Rehabilitation Departments.

That a sum not exceeding Rs. 92,94,55,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 14—Food and Supplies Department.

That a sum not exceeding Rs. f5,39,81,670 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 15—Irrigation Department.

That a sum not exceeding Rs. 2,97,46,095 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect f the charges under Demand No. 16—Industries Department.

That a sum not exceeding Rs. 14,25,36,660 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 17—Agriculture Department.

That a sum not exceeding Rs. 4,71,81,790 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. .8—Animal Husbandry Depart ment.

That a sum not exceeding Rs. 27,87,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-17 in respect of the charges under Demand No. 19—Fisheries Department.

That a sum not exceeding Rs. 1,56.06,050 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand .No. 20—Forest Department.

That a sum not exceeding Rs. 3,24,18,360 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 21—Community Development Department.

That a sum not exceeding Rs. 26,33,74,650 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 22—Co-operation Department.

That a sum not exceeding Rs. 37,43,41,317 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 23—Transport Department.

That a sum not exceeding Rs. 15,89,150 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 24—Tourism Department.

That a sum not exceeding Rs. 42,07,05,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 25—Loans and Advances.

Hon'ble Members can raise discussion on these Demands but while speaking they will indicate the Demand

Number on which they want to raise discussion. Guillotine will be applied at 5-45 P.M.

राव दलीप सिंह (कनीना) स्पीकर साहब, कई रोज से बजट पर चर्चा चल रही है और गवर्नर साहब के एडैरस पर भी चर्चा चली । आज डिमांडज के ऊपर जो डिसकशन दरो रही है और मैं भी दों–चार डिमांडज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । वे हैं डिमांड' नम्बर 22, 14, 21, 17, 23, 13 और 25 । स्पीकर साहब, कोआपरेशन का जौ महकमा है यह बहुत ही अहम महकमा पं । यह महकमा गरीब वर्ग की सेवा करता है, विकास के बड़े कार्य करता है, हरिजनों के लिये, बैकवर्ड क्लासिज के लिये और वीवर्ज के लिये बड़ी अच्छी स्कीमें बनाता है और उनको लोन देता है लेकिन स्पीकर साहब, इस महकमें में भी जैसे चर्चा चल रही थी, बहुत भारी ऐम्बैजलमैंट चल रही है । एक सोसाइटी है जो एक आदमी की सोसाइटी है और वह आदमी सौ पचास आदमियों को मिस–गाइड करके लोन ले जाता है और जिसकी वसूली भी बाद में गरीब आदमियों से होती है । इस किस्म की कमियां हैं जिनमें सुधार की जरूरत है । अभी–अभी एक क्वैश्चन के सिलसिले में बताया गया था कि एक साल में 47 लाख की ऐम्बैजलमैंट हुई, एक साल में 52 लाख त्ही हुई और एक साल में 9 लाख की हुई तो यह राशि कोई छोटी राशि नहीं है । इससे एक तो जिस गरीब आदमी को कर्जा मिलना चाहिये था उसे कर्जा नहीं मिला और दूसरे विकास कार्य ठप्प हुए । इस संबंध में मैं यह चाहूंगा कि इनका जो आडिट डिपार्टमैंट है इसको मजबूत

बनाया जाए ताकि यह हर सोसाइटी का हर साल आडिट कर सके । जब हर एक सोसाइटी का सालाना आडिट होगा तो ऐम्बैजलमैंट किसी हद तक कम हो जाएगी और रुपये का सही इस्तेमाल हो सकेगा । हमारे जो लैड डिवैल्पमैंट बैक हैं ये भी काफी कर्जा देते हैं । इन बैंकों ने सारे प्रदेश में पिछले साल 13 करोड रुपये का कर्जा दिया जिससे किसानों को कुएं बनाने में, पम्पिग सैट्स लगाने में, मोटरें लगाने में बड़ी सहूलियत हुई है लेकिन इस बैक में भी लोन का मिस–यूटिलाइजेशन बहुत भारी होता है । जो मैनोपलिस्ट सोसाइटीज हैं वे कर्जा लेकर जाती हैं, 10– 11 हजार रुपये अपने भाई के नाम, चर्चे के नाम, ताऊ के नाम यानी दस–दस लोन ले जाते हैं और उसे मिस यूटिलाइज करते हैं । इस प्रकार से विकास के कार्यों में रुकावट आती है, क्योंकि जिसको कुआं लगाने के लिये या मोटर लगाने के लिये पैसे की जरूरत है और पैसा उसको मिलता नहीं है तो वह कहां से कुआं या मोटर लगाएगा? तो इससे विकास के कार्य में दोनों तरफ से रुकावट आती है । आज ऐम्बैजलमैंट के केसिज की तादाद 900 है । इसका मतलब है कि एक करोड़ की राशि ऐसी है जो लोगों को दी थी लेकिन वह इस्तेमाल नहीं की गई । तो मेरी प्रार्थना है कि ऐसे केसिज बहुत कम होने चाहिये । महकमे को देखना चाहिये कि वह जिसको लोन देता है आया वह उसे ठीक यूटिलाइज कर रहा है या नहीं । अगर महकमा इस बारे में कामयाब नहीं हो सका तो मैं यह कहूंगा कि हमारे इस महकमे में बहुत भारी कमियां हैं । पहले की निस्बत तो इसमें सुधार है । पहले कई–कई लाख का

गबन होता था किसी साल 47 लाख और किसी साल 52– 52 लाख का होता था । इसके अलावा अब जो मिनी बैकंस बनाने जा रहे हैं, यह बहुत अच्छी स्कीम है । इस स्कीम के तहत हर पटवार हल्के में एक–एक मिनी बैक होगा जो किसानों को और गरीब लोगों को हर तरह के लोन देगा और चीनी शूगर भी वहां से तकसीम होगी । होल टाईम उसका सैक्रेटरी रहेगा और सुबह 9 से सांय पांच तक वह खुला रहा करेगा । तो यह एक बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें लोन का मिस–यूटिलाइजेशन नहीं होगा और न कोई ऐम्बैजलमैंट होगी । यह एक बडा अच्छा कदम है । दूसरे लेबर कन्स्ट्रकशन सोसाइटियां ज्यादातर ऐसी हैं जो बोगस हैं । कई आदमियों ने तो सच्ची बनाई हुई हैं लेकिन कईयों ने श्डयूल्ड कास्टस वगैरह के नाम लेकर बनाई हैं जो कि बोगस हैं इसलिये उनको खत्म किया जाए और उनको जो लोन दिया है उसे रिकवर किया जाए ।

इसके बाद स्पीकर साहब, फूड एंड सप्लाई का जो महकमा है, यह भी बहुत जरूरी है । हर गांव में चीनी और आटा टाईम पर गरीब लोगों को मिल जातु यह जरूरी चीज है लेकिन इसमें बोगस राशन कार्डों की बहुत समस्या हए । इस महकमें ने सारे प्रान्त से 67,000 बोगस राशन कार्ड निकाले हैं, इसके लिये मैं उनको दाद देता हूं । यह घपला कई सालों से चला आ रहा था लेकिन अब यह इन्होंने डिटैकट कर लिया है । इन राशन कार्डों से पांच लाख आदमी बोगस थे जो कई साल तक राशन

लेते रहे । अढाई साल तक बोगस राशन कार्डों पर ब्लैक में चीनी बिकती रही । दो सौ रुपये फालतू में चीनी की बोरी कहा भी बिक सकती है । चार–पांच लाख रुपये की चीनी हर महीने ब्लैक में बिकती रही । मुझे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि महकमा यह कहता है यह तादाद ज्यादा है इसलिये हम डिपो होल्डरों पर ऐक्शन नहीं ले सकते । तो मैं यह कहूंगा कि यह जवाब इनका कोई सही जवाब नहीं है । इस तरह से तो अगर एक प्रान्त के अन्दर ज्यादा कत्ल होने लग जाएं और प्रशासन की तरफ से जवाब हो कि क्योंकि केसिज की तादाद ज्यादा है इसलिये हम कोई ऐकशन नहीं ले सकते तो यह कोई प्रौपर जवाब नहीं है । तो मैं यह चाहूंगा कि जिन्होंने बोगस राशन कार्ड बना कर चीनी का गल्त इस्तेमाल किया है उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाए । स्पीकर साहब, जहां तक पंचायत का ताल्लुक है वहां भी काफी ऐम्बैजलमैंट होती है । एक गांव में सरपंच ने या सैक्रेटरी ने कुएं बनाने के लिये अगर दम हजार रुपये लिये हैं और वह रुपया ठीक यूटिलाइज न होकर सरपंच या सैक्रेटरी की जेब में चला जाए तो गांव का विकास कार्य तो बन्द हो गया । 1971–72 में 1200 पंचायतों का आडिट किया गया था जिसमें 336 ने मिस–यूटिलाइजेशन की, 1972–73 में 1500 में से 881 ने मिस–यूटिलाइजेशन की, 1973–74 में 1414 में से 500 ने मिस–यूटिलाइजेशन की और 1975–76 में 1100 में से 650 ने मिस–यूटिलाइजेशन या ऐम्बैजलमैंट की । तो 50 प्रतिशत पंचायतें ऐसी हैं. जिन्होंने विकास कार्य रोके । इसलिये कोई भी आदमी

उस पैसे को खाकर बैठ जाता है और यह बढ्ता ही जाता है । आज बीस सूत्रीय प्रोग्राम होने के बाद भी और हमें यह पता है कि भ्रष्ट आदमी कौन है, फिर भी उसे पकड़ा नहीं जाता । मुझे अफसोस है कि आज ऐमरजैसी के अन्दर भी क्रप्शन अपना सिर फैलाती जा रही है ।

स्पीकर साहब, जहां तक ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट का सवाल है इस के द्वारा किसानों को जो बीज दिये जाते हैं, उस पर किसान बड़ा भारी एतबार करके लेते हैं । अब की दफा हाइब्रिड बाजरे का जो सीड दिया गया वह इतना रद्दी था कि उस में सारे में ही बीमारी लग गई । जिस ने दस एकड़ में वहू सीड बोया उस पर और रुपया खर्च किया पानी दिया, खाद दी वह सारा बेकार गया और उससे एक एकड़ की पैदावार के बराबर भी पैदावार नहीं हो सकी । गरीब किसान रोता था कि उसने इतना खर्च किया, कर्ज लिया वहू लगा दिया लेकिन पैदावार नहीं हुई । किसान न कर्ज वापस कर सकता है न अपने वर का खर्च चला सकता है और उसे जेबरात तक बेचने पडे कर्ज वापस करने के लिये और अपने थर का खर्च चलाने के लिये । मैं चाहता हू कि सरकार इस बात की जांच कराये कि ऐसा निकम्मा बीज कहां से आया और बहु रद्दी कैसे साबित हुआ । दूसरे प्रांतों से भी इसके बारे में शिकायतें आई हैं कि वह इतना रद्दी और बीमार बीज था कि अगर किसी जानवर. ने खा लिया तो जानवर बीमार हो गया और अगर किसी आदमी ने खा लिया तो वह बीमार हो गया । तो

इस बात की जांच करवाई जाये और. इस बारे में मुनासिब कार्यवाही की जाये । फिर इस दफा सरसों में बीमारी लग गई लेकिन सारे जिला हैडक्वार्टरज पर स्प्रे करने के लिये पम्प नहीं मिला कि जिससे ये औस्टीसाइडज स्प्रे किये जा सकें । स्प्रे पम्पस तो हैं लेकिन कोई भी वर्किंग आर्डर में नहीं है । तो जब पम्पस हैं तो उनको देखना चाहिये कि आया वह काम करने लायक हैं या नहीं और अगर नही हैं तो उनको ठीक हालत में रखा जागे ताकि किसान ऐसी हालत में जब उसकी फसल कौ बीमारी लगी है पैस्टीसाइडज स्प्रे कर मके लेकिन किसान को न वैंड पम्प और न ही पावा क्रिमिनल नैगलीजैंस में मिला । यह जरायत के महकमा की बड़ी भारी नैगलीजैसं है और क्रिमिनल नैगलीजैंस है । इस बारे में सरकार को देखना चाहिये और ऐप्रोप्रिएट ऐक्शन लेना चाहिये ताकि आयंदा ऐसी बात न हो ।

जहां तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट का ताल्लुक है इस में कोई शक नही हमारी रोडवेज बहुत अच्छा काम कर रही है, बड़ी फास्ट बस सर्विसीज हैं और यहां से सारे जिला हैड– क्वार्टर्ज के लिये डायरैक्ट बसें चलती है । लेकिन इन बारे में एक बात जरूर कहना चाहता हुं कि हमारे बस स्टैडंज पर जो खाने की चीजें मिलती हैं वे ऐसी हैं कि उनको कोई खा नहीं सकता । जहां पर चाय और पकौड़े वगैरा बनते हैं वहां पर कोई पांच मिनट के लिये खड़ा नही हो सकता । चाय पी कर के आ जाती है और पकाने के लिये जो तेल इस्तेमाल होता है वह महीनों तक इस्तेमाल होता

रहता है और उससे बदबू आती है । महकमा को देखना चाहिये कि वहां पर जो खाने–पीने की चीजें हैं उनकी क्वालिटी ठीक हो, ताकि मुसाफिर रास्ते में बीमार न हों । इसके अलावा इन चीजों के रेट्स भी ज्यादा हैं । तो मैं कहुगा कि बम स्टैडंज पर खाने–पीने की चीजों की क्वालिटी और. प्राइनिज को ठीक किया जाये । फिर रोडवेज के जो बस ड्राइवर्ज और क्न्डक्टर्ज हैं ये बहुत काम करते हैं और सरकार को करोड़ों कमा कर देते हैं । एक कंडक्टर जो यहां से नारनौल औररू महेन्द्रगढ के लिये चलता है उसे' रास्ते में सैकडों मुसाफिरों से रोजाना बात करनी होती है । और तरह–तरह के टैम्प्रामैंट के लोग उसे मिलते हैं, कई तो हर वक्त उससे लडूने के लिये तैयार रहतै हैं और हर बात पर कम्पलेंट बुक मांगते हैं कि शिकायत लिग्डेंगे लेकिल वह अपनी सूझ–बूझ से हरेक को टैकल करता है । कंडक्टर्ज और ड्राइवर्ज जो इतना काम करते हैं उनका ओवर टाईम कम कर दिया गया है । अगर वे 12 घंटे ओवर टाईम भी लगाते हैं तो उनको सिर्फ आठ घंटे का मिलता हैं यह बहुत ज्यादती है । इनको पूरा ओवर टाईम मिलना चाहिये और इन चार घंटों का ओवर टाईम भी मिलना चाहिये । ये लोग बहुत काम करते हैं लोगों की सेवा भी करते हैं और सरकार को कमा कर भी करोडों रुपये देते है ।

सोशल वैल्फेयर के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यी बहुत अच्छा काम किया गया है कि हर गरीब हरिजन को सौ गज का प्लाट दिया गया है लेकिन मैं अर्थ करता हुं कि इस बीस

सूत्रीय प्रोग्राम को सही मायनों में इम्पलीमैंट करने के लिये सरकार को इन प्लाटों पर छोटे–छोटे मकान बना कर देने चाहिये । उनको कम से कम दो कमरे और एक ब्रांडा बना कर देना चाहिये, छतें बेशक आप टीन की बना दें या ऐस्बेसटास शीट्स की बना कर दें । ऐसा करने से ही इस बीस नुकाती प्रोग्राम की सही तौर पर इम्पलीमैंटेशन होगी ।

ये जो सफाई कर्मचारी हैं चाहे लोकल बाडीज के हैं या गवर्नमैंट के इन की डयूटी ऐसी है कि दूसरा आदमी उस काम को कर नहीं सकता है । जहां पर वह जिस काम को करते हैं, वहां पर कोई दूसरा पांच मिनट के लिये भी खड़ा नहीं हो सकता है । इन की तनखाह थोड़ी है और यह बढ़नी चाहिये और कम से कम एक कलर्क का ग्रेड इन को मिलना चाहिये । अगर आप समाजवाद लाना चाहते हैं और इस बीस नुकाती इकोनोमिक प्रोग्राम को सही तौर पर इम्पलीमैंट करना चाहते हैं तो सफाई कर्मचारियों की तनखाह इस तरह से बढ़ाई जानी चाहिये क्योंकि इन का काम बहुत सख्त है ।

मैंने यहां पर ट्रांसफारमर्ज के बारे में एक सवाल किया था और मुझे जवाब में बताया गया कि ये जो बिजली के ट्रांसफारमर्ज हैं ये 1971–72 में 1875, 1972–73 में 1763, 1973– 74 मे 1984 और 1974–7 5 में 216० जले । इस में शक नहीं कि हरियाणा में बिजली का बहुत फैलाव हुआ और बहुत सारे ट्रांसफारमर्ज लगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हजारों की

तादाद में ये जल जायें । एक छोटे ट्रांसफारमर की कीमत जो 25 के० वी० का होता है पांच हजार रुपये होती है । बड़े ट्रांसफारमर्ज तो बाइस–बाइस लाख रुपये के भी होते हैं । लेकिन अगर हम कम से कम पांच हजार रुपये का डैमेज एक ट्रांसफारमर का लगायें तो आप देखें यह डैमेज एक करोड़ से ज्यादा बन जाता है । यह डैमेज इस लिये हुआ क्योंकि अच्छी तरह से सुप्रविजन नहीं हो सकी । अगर हमारे पास पूरा स्टाफ नहीं, जो सुप्रविजन कर सके तो और मुलाजिम भर्ती कर लो ताकि वे इन ट्रांसफारमर्ज की पूरी तरह से सुप्रविजन कर सके इनको देखें कि तेल ठीक वक्त पर डला है और अगर उन में कोई नुक्स हो तो उसे ठीक कर दें । यह तो बड़े भारी न्उकसान की बात है कि हर साल जलने वाले ट्रांसफारमर्ज की तादाद बढ्ती जा रही है और करोड़ों का नुकसान हो रहा है । मैं सरकार से कहूंगा कि वह इस बारे में स्पैशल जांच करवाये । अगर तो स्टाफ की कमी है तो और भर्ती किया जाये अगर स्टाफ पूरा है तो जो सुप्रविजन ठीक प्रकार से नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये लेकिन इस नुकसान से हरियाणा को बचाया जाये । दरम्याने दर्जा का ट्रांसफारमर भी दो लाख का आता है जो 2 ऐम० ई० का होता है । हमारे महेन्द्रगढ़ में यूक दो ऐम०ई० का ट्रांसफारमर जल गया और फिर इसी तरह से अटेली में भी दो ऐम० ई० के ट्रांसफारमर जल गये । मैं नहीं कहता कि दो लाख का नुकसान एक के जलने से हो गया, हो सकता है पचास फीसदी नुकसान हो या कम हो और वह रिपेयर से ठीक हो जाये लेकिन नुकसान तो फिर भी है

और यह क्यों हो? तो यह देखने वाली बात है ।

नहरों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जवाहर लाल नेहरू कैनाल जो महेन्द्रगढ़ में जानी है उस पर आठ करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है और गवर्नमैंट तेजी के साथ इसे कम्पलीट करना चाहती है । मैं फिर भी चाहुगा कि यह नहर निहायत ही बैकवर्ड यूरिया की है इसलिये इस पर और तेजी के साथ काम किया जाये । यह जो बीस सूत्रीय प्रोग्राम चला है और जिस पर काफी चर्चा चल रहा है इसे मैं चाहता हूं कि इन लैटर ऐंड स्प्रिट इम्पलीमैंट किया जाये यह नहीं कि यह मेरा भाई है इसे छोड़ दो, यह मेरा दोस्त है और दोस्त का दोस्त है इसे छोड़ दो । मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब इसे इन लैटर ऐंड स्प्रिट इम्पलीमैंट करेंगे । अगर ऐसा किया जायेगा तब ही इसका पूरा इम्पैक्ट होगा वरना इसका अच्छा असर पड़ने की बजाये, बुरा असर ही पड़ेगा ।

स्पीकर साहब ऐमरजैसी के बारे में कहा गया है और काफी चर्चा इसके बारे में हुआ है और हो रहा है । मैं समझता हूं कि उससे पहले देश में ऐसे हालात हो गये थे कि हर तरफ अफा–तफ्री फैल रही थी और स्ट्राइकें हो रही थीं । तो ऐसे हालात में इस ऐमरजैंसी का अच्छा इम्पैक्ट हुआ है, नेशन में डिस्पिलन आ गया है और नेशन डिसइंटेग्रेशन से बच गई है इसलिये मैं इसे वैलकम करता हुं । इन अलफाज के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं ।

15.00 बजे ।

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा–अनुसूचित जाति) : स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप ने मुझे बोलने के लिये समय दिया है । बजट पर पहले दो दिन तक बहस हो चुकी है और आज बजट की डिमांडज सदन के सामने आई हैं जिन पर. बहस चल रही है । बहुत सारे भाइयों ने बीस नुकाती प्रोग्राम के बारे में और इस एमरजैसी के बारे में काफी कुछ कहा है । स्पीकर साहब 1971 में जो गरीबी हटाओ का नारा लगा और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये हमारे देश की नेता प्रधान मली ने जो प्रोग्राम बनाया, उस में बहुत सारी बाधायें आई । तो मैं समझता हूं कि इस बीस नुकाती प्रोग्राम को चलाने के लिये हमारे देश की नेता प्रधान मंत्री ने यकम जुलाई, 1975 को देश में आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का फैसला किया । अगर ऐमरजैसी लागू न होती तो इसके बारे में वही झगड़ा, वही शोर मचता और हुसको फेल करने की कोशिश की जाती । स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा हाउस में कहना चाहता हूं देश के अन्दर एक प्रथा रही हे । वह है आर्थिक व्यवस्था का पहला सवाल जिस में बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है । (इस समय सभापति तालिका के सदस्य चौधरी ईश्वर सिंह पदासीन हुए) आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जब भी गरीब की मदद करने की बात आती है तो इसके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं, कई रुकावटें आ जाती है और वे रुकावटें पूंजीपति पैदा

करते हैं । पूंजीपति ऐसा मुहाल बना लेते हैं, जिसके कारण वे गरीब का काम नहीं होने देते । अगर 1971 में ऐमरजैसी लागू हो जाती तो 'गरीबी हटाओ' का प्रोग्राम यूं का यूं कायम रहता ।

1971 में ऐमरजैसी लागू नहीं हुई, जिसकी बिना पर देश के अनेक पूंजीपतियों को मै मिल गया । उन्होंने रुकावटें पैदा कीं क्योंकि वे गरीब आदमी की हालत सुधारने से नाराज थे । वे इस बात को जानते थे कि अगर गरीब की आर्थिक व्यवस्था सुधर गई तो पूंजीपति को अपना मतलब हल करने का मौका नहीं मिलेगा । 1971 का जो 'गरीबी हटाओ'' प्रोग्राम था उसकी बिना पर बैक नैशनेलाईज हुए । पहले यह हाई कोर्ट में चौलेंज हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में चौलेंज हुआ। प्रिवी–पर्सिज खत्म करने का बिल भी कोर्ट में चौलेंज हुआ । ये सब रुकावटें आती रहीं । अगर ऐमरजैंसी लागू न होती तो देश की स्थिति पता नहीं क्या होती? 20 प्वांयट इकोनोमिक प्रोग्राम के बारे में, मेरे से पहले बोलने वाले दो सदस्यों ने, जिन में से एक जनसंघ के सदस्य थे और दूसरे चौधरी रिजक राम थे, उन्होंने कल कुछ बातें कहीं । चौधरी रिजक राम जी बड़े सुलझे हुए पौलिटिशियन हैं, उन्हेंने ऐसा जाहिर किया कि 20 सूत्रीय प्रोग्राम एक मजाक है । चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिए निवेदन करना चाहता हूं कि गरीबी हटाओ प्रोग्राम, जिसको उन्होंने मजाक में टाल दिया था, वह तो टाल दिया लेकिन 20 सूत्रीय प्रोग्राम मजाक में नहीं टलेगा क्योंकि यह प्रोग्राम देश की एक आवाज है, गरीब आदमी को रोटी

की जरूरत है, हर आदमी को रोटी, कपडा, मकान की जरूरत है इसलिए हर आदमी इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए. तत्पर है । चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिए मुख्य मन्त्री साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे इस तरफ खास तौर पर ध्यान दें और जो लोग गरीबों के हमदर्द बनने की झूठी कोशिश करते हैं किसानों के हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं और उन के आंसू पोंछने की झूठी कोशिश करते हैं उन से निपटें । चौधरी बंसी लाल जी उन से कहीं ज्यादा जमींदारों की समृद्धि चाहते थे, किसानों की हिमायत ज्यादा करते थे उन्होंने बजट का लगभग 80 फीसदी रुपया शहरों की बजाए देहातों पा खर्च किया । इतना होने के बावजूद भी अगर उन की नुक्ताचीनी करें तो यह महज नुक्ताचीनी की ही बातें हैं । चौधरी बंसी लाल ने अपने समय में लगभग 80 फीसदी बजट का मुंह देहातों के लोगों को सहुलतें देने के लिए फेरा । देहातों में सड़कें पहुंचाई, बिजली दी और जो किसान खेती करता है उसकी हालत सुधारने के लिए लगभग 80 फीसदी बजट खर्च किया । इतना ही नहीं, उन्होंने रचनात्मक ढंग से प्लान बनाकर, योजनांए बनाकर काम किए । जिस इलाके में बाढ़ आती थी, उस बाढ़ पीड़ित इलाके को बाढ़ से बचाया और जहां सेम होती थी वहां नहरों को पक्का करके सेम को टूर किया । जिस इलाके में पानी नहीं मिलता था, लोग पानी के लिए तरसते थे, लोग अपने सिर पर पांच पांच मील से पानी उठाकर लाते थे, उन को पीने का पानी दिया । जो लोग पानी न मिलने की वजह से एक दिन की रोटी मुकम्मल तौर पर नहीं कमा सकते थे, उनको

पानी देकर अपने पावों पर खडा किया । मुख्य मन्त्री जी बैठे हुए हैं । चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगले 10– 15 साल तक, इसी तरह देहातों पर खर्च होता रहा तो महिन्द्रगढ, भिवानी जैसे जो बैकवर्ड– इलाके हैं, जो बैकवर्ड जिले हैं, जिनको मुश्किल से पानी के दर्शन होते थे, वे कुछ परोस्पर हो जाएंगे । 10– 15 साल तक अगर बजट में प्रोवीजन रख कर उस इलाके के लोगों पर इसी तरह खर्च किया जाए तो इस अर्से में वे लोग, इनके बराबर तो नहीं, कम से कम 100 कदम पीछे तक पहुंच पाएंगे, इसके बावजूद भी बराबर नहीं पहुंच सकते । चेयरमैन साहब, करनाल और कुरुक्षेत्र के लोगों को बारे में मैं सोचता हूं कि वही के रह्ने वाले लोग बहीश्त में रहते हैं, वहां की आबोहवा, वहां का पानी, वहां का वातावरण बहुत अच्छा है । कई दफा मेरे साथी गर्ग साहब कहा करते हैं कि भिवानी तो उजडा हुआ इलाका है, उस पर खर्च करने का क्या फायदा? अगर कुरुक्षेत्र जिला के रहने वाले लोग, थोड़ी देर भिवानी जिला में रह कर देखें तो पता चलेगा कि जून के महीने में क्या गुजरती है । चेयरमैन साहब, मैं यह इस लिए कह रहा हूं कि ऐमरजैसी और 20 प्वांयट इकोनोमिक प्रोग्राम, ये दोनों को–रिलेटिड हैं । अगर 20 प्वांयट प्रोग्राम को, इस आर्थिक प्रोग्राम को सरकार पूरे तौर पर निभाना चाहती है, तो सही मायनों में गरीब की मदद करनी चाहिए और इस ऐमरजैसी को लागू रखना होगा । बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते कि गरीबों की हालत सुधारनी है, उनके दिल में तकलीफ होती है । जैसे चौधरी शिव राम यमी कह रहे थे

मजदूर की डेली वेजिज क्यों बढ़ा दी? सरकार ने तो यह बेहतरीन कदम उठाया है कि पहले 82 रुपये से 115 रुपये मिनिमम वेजिज फिक्स की थी और अब सरकार ने अगला कदम उठाया है कि मजदूर को 140 रुपये से 175 रुपये डेली वेजिज देंगे । लेकिन यह बढ़ौतरी उन को बरदाश्त नहीं होती और कहते हैं कि मजदूर को ज्यादा पैसा दे रहे हैं । हाउस में मजदूर की मुखालिफत करते हैं और हाउस के बाहर उसकी हिमायत करते हैं । जब तक ऐमरजैसी रहेगी तब तक गरीब को ऐक्सपलायट नहीं कर सकते । मैं समझता हूं कि आर्थिक स्वतन्त्रता लाने के लिए ऐमरजैंसी को कायम रखना निहायत जरूरी है, क्योंकि जो लोग अन्दर से कुछ हैं बाहर से कुछ हैं, चाहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, उन को आज पता लग रहा है । चेयरमैन साहब. आर्थिक व्यवस्था को जानन वाले बहुत सारे फिलौसफर है । उन्होंने लिखा है कि जब गरीब दु:खी होता है तो अमीर सुखी होता है, और जब गरीब सुखी होता है तो सारी दुनिया सुखी होती है । आज गेलू मोदी जैसे सेठ जेल में हैं । चेयरमैन साहब, जब हमारे बड़े बड़े ऐक्सप्लायटीयर नेता जेल के अन्दर बन्द हैं तो गरीब को इस बात की राहत मिलती है कि उसको ऐक्सपलायट करने वाले लोग नहीं हैं, जेल के अन्दर हैं या वे ऐसे कोने में लगे हुए हैं जिनको यह पता नही कि शाम को घर रहना है या जेल में रहना है । हमारी प्रधान मन्त्री ने इस बात का निर्णय लिया है, जैसे पंडित जवाहर लाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे पर आजादी का बिगुल बजाने का निर्णय लिया था, इसी तरह प्रधान मन्त्री ने 1 जुलाई, 1975

को आर्थिक स्वतन्त्रता का बिगुल बजाया है । उस गरीब का दर्द उन लोगों के दिलों में कैसे हो सकता है, जो गरीब हरिजन की छाया तक लेना पसन्द नहीं करते थे, अन्नने साथ नहीं लगाते थे, वे हरिजन की भलाई कैसे सोच सकते हैं? हमारी प्राईम मिनिस्टर ने इन लोगों के दर्द को समझा । वे लोग कहते हैं कि मजदूरी बढ़ा दी, सरकार ने ऐग्रीकल्चर पर ज्यादा टैक्स डाल दिया, इस तरह की अजीब बातें करते हैं, जो बेसलैस हैं । सबसे ज्यादा खुशी की बात यह कि हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री चौधरी बंसी लाल जी, जौ आज देश के डिफैसं मिटर हैं वे इतनी ताकत के मालिक हो गए हैं कि वे किसान की स्थिति को, यहां हरियाणा ' बैठकर नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठकर देख रहे हैं और वह किसान का बेटा जिसने अपने हाथ से जांडी काटी है, उसके दिल में किसान का दर्द है और वह जानना है किसान को किस तरह राहत मिल सकती है । चेयरमैन साहब, कामा गाटा मारू नगर में आल इंडिया कांग्रेस सैशन हुआ । उस सैशन के अन्दर आर्थिक शाम्वियों ने आर्थिक व्यवस्था पर अपने अपने प्रस्ताव रखे थे कि देश में आर्थिक नीति क्या होनी चाहिए किम तरह से किसानों की हालत को सुधारें, किस तरह से गरीब मजदूरों को रोटी मिले किस तरह से म्माल फारमर्ज को फायदा पहुंचे. इम नीति के बारे में हमारे साबका मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा । किसान की आर्थिक व्यवस्था को सोचने वाला, एक किसान का बेटा, जिसके दिल में किसान के लिए दर्द है, जो जानता है कि किसान को किस तरह से दिन और रात गर्मी और सर्दी को सहना पड़ता है, किसानों के

लिए योजना बनायी । चौधरी बंसी लाल जी को किसान की सारी तकलीफों का पता था । उनको हल करने के लिए उन्होंने अपने हाथ से हरियाणा के किसानों की हालत में सुधार लाने के लिए नक्शा बनवाया और हिन्दुस्तान में हरियाणा के किसानों को पहले नम्बर पर लाया । कोई कह नहीं सकता था कि किसान की ऐसी स्थिति भी होगी । इसी सैशन में फैसला किया गया । किसान जो अपने गन्ने को कोल्हू में पेलता है, उसको गुड़ का भाव 12 आने किलो मिलता है । अगर वह उसी गन्ने को शूगर मिल में देता है तो मिल मालिक को चार रुपये 35 पैसे किलो के हिसाब से मिलता है । अब सरकार इस बारे में निर्णय करना चाहती है कि किसान जो गुड़ बना कर बेचता है उसको 12 आने किलो क्यों मिलता है और उसी गन्ने की जो चीनी बना कर बेचता है उसको 4 रुपये 35 पैसे क्यों मिलते हैं? सिर्फ फर्क इतना है कि किसान अपने आप गुड़ तैयार करता है और मित्र मालिक गन्ना इकट्ठा करके बहुत बड़ी तादाद में कश करता है । सरकार विधि अनुसार कमीशन बना कर विचार कर रही है कि इसमें क्या सकैन्डल है? सरकार जांच कर रही है कि क्या गड़बड़ है? लेकिन यों ही किसी बात को मोटिवेटिड करके, प्रौपेगैन्डा करना कि सरकार इस बारे में नहीं सोच रही है, नामुनासिब बात है । यह बात सरकार के नोटिस में पहले से ही है और जांच पडताल कर रही है ।

चेयरमैन साहब, इसके अलावा एक बात और अर्ज करना चाहता ी वह यह है कि मंहगाई बढ्ती हुई आबादी, भष्ट्राचार,

असेन्शियल कमोडिटीज का न मिलना और हरिजनों की समस्या ये पांच प्रोबलम देश के सामने हैं । इन पांचों प्रोवलमज का हल केवल 20 सूत्रीय प्रोग्राम है । आज अगर देश के अन्दर 20 सूत्रीय प्रोग्राम के तहत इस ऐमरजैसी में काम होता रहे तो देश के गरीब लोगों को राहत मिल सकती है देश के किसान को राहत मिल सकती है देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक हो सकती है । जो भी रास्ते में रुकावटें हैं वे दूर हो रही हैं । ऐमरजेसी की वजह से तो आज उसी तरह हो रहा है जैसे कोई आदमी खेत में गोलिया घूमा कर जानवरों को भगा देता है । उसी तरह से ये लोग भी भागे हुए हैं । अगर ऐमरजैसी लिफ्ट होगी तो इस बीस सूत्रीय प्रोग्राम में कम से कम काम होंगे । अगर फिर भी हम मजबूर हो जायेंगे कि काम नहीं हो रहा तो हमें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा ।

चेयरमैन साहब हमारे एक साथी ने यहां हाउस में हुा कि हाउस के मेम्बरों को बीस सूत्रीय प्रोग्राम का पता ही नहीं है । मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि जिम तरह से चौधरी बंसी लाल जी ने हरियाणा की नबज को देख कर किसान को रीड की हड्डी समझ कर किसान को ऊंचा उठाया गरीब हरिजनों को खाती और लुहार को ऊपर उठाया इसी प्रकार से हमें भी इस 20 सूत्रीय प्रोग्राम का विरोधी दल के भाइयों से अधिक ज्ञान हे । चौधरी बंसी लाल ने योजना बना कर 77.7 परसैन्ट बजट किसानों की भलाई के लिए खर्च किया । ऐसा करने से हम फूडग्रेन में सरप्लस हुए ट्रांसपोर्ट में हमने चमत्कार दिखाया ।

अभी हम पिछले दिनों कलकत्ता गये आप भी चेयरमैन साहब हमारे साथ थे वे हरियाणा को हरियाणा के नाम से पुकारते हैं । वे कहते हैं कि हरियाणा में बहुत ही ज्यादा प्रगति और उन्नति हुई है । दूसरे सूबों के लोगों पर भी यह छाप है कि हरियाणा में बहुत ज्यादा प्रगति हुई है चाहे हम ट्रांसपोर्ट को इरीगेशन डिपार्टमैंट को इलैक्ट्रीसिटी को लें किसी भी महकमें को हाथ में लें सभी में नयी छाप नजर आती है । जब देश के हालात इस प्रकार हों––––(घंटी) चेयरमैन साहब मैंने तो अभी भूमिका ही बान्धी है अपने हल्के की भी बातें कहनी हैं । हां, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे विकास और प्रगति का हर सूबे में चर्चा है । तो इस ओर मैं अपनी ऐडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान भी दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से राजनैतिक पार्टियों की ड्यूटी है कि वे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम बनायें उसी तरह से अफसरान की भी ड्यूटी है कि जो भी प्रोग्राम उनको सौंपा जाये उसको पूरी तरह से लागू करें । क्योंकि सारा प्रोग्राम तो इन्हीं लोगों के हाथ में है ।

अब मैं अपनी कांस्टीच्यूसी के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । बवानी खेडा की इलैक्शन के वक्त. तहसील हांसी और जिला हिसार पडता था । अब मेरा हलका भिवानी जिले में शामिल हो गया है । मेरे हलके के सारे गांवों का मुंह पहले हांसी की तरफ और हिसार की तरफ पड़ता था । अब बवानी खेड़ा अलग से तहसील बन गई है और दूसरे रोड पर पड़ती है भिवानी जिला बनने से सारा ही उलट हो गया है । अभी जैसे आज क्वैश्चन

आवर में एक सवाल आया था कि सिवानी से बवानी खेड़ा को रोड दे दी जाये ताकि जो गांव इन्टीरियर में हें उनको भी सुविधा हो सके । उनको हिसार से होकर जाना पड़ता है या उनको तोशाम जाना पड़ता है फिर बयानी खेड़ा आना पड़ता है । इन दोनों सड्कों को लिंक रोडों से मिला दिया जाये तो उनको काफी सुविधा हो जायेगी । वहां छपर बस भी चल सकती है कई एक और भी सडकें हैं जो बननी बहुत जरूरी हैं । जैसे बांठे ब्राह्मण से बालावास बांठे रागजन से कंवारी और इसी तरह से सिपर बोले से होते हुए जमालपुर, पपोसा से बवानी खेड़ा रतेरा से तोशाम अगर ये लिंक रोड मिला दिये जायें तो उन गांवों को काफी सहूलियत हो सकती है । वे बवानी खेड़ा तहसील हैड क्वार्टर पर आसानी से पहुंच सकते हैं ।

मेरे हल्के में जो बवानी खेड़ा तहसील में लगता है 55 गांव हें । इनमें से 1 5— 20 गांवों में बिल्कुल खारी और कडुवा पानी है जो पीने काबिल नहीं है । इसलिए इन गांवों में पानी का प्रबन्ध किया जाये । एक रोहनात गांव है । रोहनात गांव की कहानी बड़ी दर्दनाक है । यह हमारी हरियाणा की तारीख से जुड़ी हुई कहानी है । उस गांव को पिछले दिनों सवा लाख रुपया सम्बोलिक कम्पनसैशन भी मिला है । 1857 में वहां के बुजुर्गों ने अंग्रेजों से गइटे हकवाये थे । अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी । अंग्रेजों ने उस गांव की सारी जमीन को छीन लिया था. केवल श्मशान भूमि को ही छोड़ा था । 15 अगस्त 1947 तक वे लोग

गुलामी की जिन्दगी बसर करते थे । अगर किसी अंग्रेज के कुते को भी यह पता चल जाता था कि यह रोहनात गांव का रहने वाला है तो वह भी उसके पीछे लग जाता था इतनी मुश्किलात का वक्त उनके सामने गुजरा है । मैं चौधरी बंसी लाल की सरकार का भी धन्यवादी हूं कि उसने उस गांव को सवा लाख रुपया सम्बोलिक कम्पनसैशन दिया । यह हरियाणा का पहला गांव है । वहां पर मोडल विलेज भी बसाया है लेकिन उनको सब से बड़ी जो दिक्कत है वह खारी पानी की है ।

अभी पिछले दिनों हमारे आई० पी ० एम० साहब वहां गये थे । उन्होंने माडल विलेज के अन्दर पंडित नेहरू की मूर्ति का अनावरण किया था । गुप्ता साहब के सामने भी उन्होंने अपनी दिक्कत पेश की थी । उन्होंने वहां कहा था कि वाटर वर्क्स जरूर बनायेंगे । इसी प्रकार से मैं सरकार का ध्यान और मुख्य मती जी का ध्यान दूसरे गांवों की तरफ भी दिलाना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो भी वायदा करके आते हैं उसको पूरा करते हैं । इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि इस बारे में ध्यान दें और वहां के लिये वाटर सप्लाई स्कीम बनायें और उस पर जल्दी से जल्दी कार्य करें । वहाँ के लोगों से कुछ पैसा सरकार ने मांगा है जिसे उन्होंने जमा करवा दिया है । इसी तरह से एक गांव सिवाल है । वहां पर भी कड़वा पानी है । वहां पर भी वाटर सप्त्नाई स्कीम बनायी जाये । बासी मिलकपुर और भररी में भी पीने के पानी की दिक्कत है । भररी गांव में लोग

जोहड का पानी पीते हैं । चेयरमैन साहब वहां पास कोई गांव नहीं, जिससे वे मीठा पानी ले सके । जोहड का पानी जिसमें भेसे नहाती हैं, वहां के लोग पीते हैं । इसके अलावा तीन चार और गांवों की एक स्कीम, जिसमें हरिता हरी, बाढे. ब्राहमण बाडे जाटान शामिल हैं, अन्डर कन्सीड्रेशन है । मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस ओर भी वह गौर करे ।

अब मैं पशु पालन या ऐनीमल हस्बैडरी के बारे में कुछ कहना चाहता है । पशु धन जो है, वह भी हिन्दुस्तान मैं स्त्री धन की तरह से है । किसान के लिये पशु इतना फायदेमन्द चीज है कि वह व्याह शादी के मौके पर पशु बेचकर अपना काम चला लेते हैं और यही नहीं टूसरे बड़े काम भी पशु होने की वजह से चल जाते हैं । पशु धन की रक्षा के लिये डिस्पैसरी और हास्पिटल स्टाफ का होना निहायत ही आवश्यक है हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणा के अन्दर बहुत सारे हास्पिटल और डिस्पैसरिया खुली हैं । मेरे हल्के के अन्दर एक गांव साडवा है जिसकी बात मैं फाइनैंस मिनिस्टर साहब के नोटिस में भी एक दो बार लाय। । उस गांव के लोगों ने 60— 70 हजार रुपया खर्च करके गांव के अन्दर एक डिस्पेंसरी और डाक्टर्ज के क्वार्टर्ज भी बना दिये हैं लेकिन अभी तक वहां डाक्टर और कम्पाउन्डर भेजने की तकलीफ सरकार ने गवारा नहीं की । तो. मैं आपके द्वारा सरकार से यह अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर स्टाफ जल्दी से जल्दी भेज दिया जाये । इससे वहां के लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और

इससे उनको लाभ भी होगा । वहां पर 12 किलोमीटर रेडीयस में कोई कैटल डिस्पैमरी नहीं है जिसकी वजह से कई दफा तीन–तीन, चार–चार हजार रुपये की भैंस मामूली से अफारे की वजह से गुजर जाती है, क्योंकि वहां पर किसी भी दवाई – का साधन नहीं होता । इसलिये अगर वहां पर डिस्पैंसरी का इन्तजाम हो जाता है, तो किसान तकलीफ से बच जायेगा और उसे तकलीफ से बचाने के लिये वहां पर डिस्पैसंरी का होना निहायत ही जरूरी है ।

इसी तरह से मैं ऐजुकेशन के बारे में भी अर्ज करना चाहता द् । यह ठीक है कि हमारे सूबे में प्राइमरी स्कूल्ज, हाई स्कूल्ज बनाने में कोई कमी नहीं रखी गई है । हालांकि पिछले दो सालों से अपग्रेडेशन पर बैन भी लगा रखा हे लेकिन तब भी हम यह समझते हैं कि प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और कालेज हमारे यहां दूसरी स्टेटों के मुकाबले में काफी हैं । (घंटी) मैं लास्ट प्वांयट्स पर हूं । पिछले दिनों यह फैसला किया गया कि 55,000 और 85,000 रुपया स्कूल की अपग्रेडेशन कराने के लिये देना पड़ेगा । मैं आपके द्वारा सरकार से और ऐजुकेशन मिनिस्टर साहब से और खास तौर पर मुख्य मंत्री महोदय से यह नम्र निवेदन करना चाहता हू कि ऐसे स्कूल जो प्राइमरी स्कूल हैं जैसे बलियानी गांव का है, वहां पर पहले मस्जिद में लड़कियों को पढ़ाते थे लेकिन फिर लोगों ने प्राइमरी स्कूल बनवा दिया और अपना चन्दा इकट्ठा करके बिल्डिंग बनवा दी, उनको अपग्रेड करना

चाहिए और उन पर से यह बैन हटना चाहिए । इसके अलावा जो लड़कियों के स्कूल हैं, उनको अपग्रेडेशन के मामले में प्राथमिकता देनी चाहिए । उन पर से यह बैन भी हटा देना चाहिए कि वह पैसा इकट्ठा करके दें क्योंकि एक लड़की को पढ़ाना एक खानदान का पढ़ाना है जबकि एक लड़के का पढ़ाना एक व्यक्ति को पढ़ाना है । मेरे कहने का मतलब यह है कि लड़कियों को पढ़ाना निहायत ही जरूरी है और जहां ऐजुकेशन की बढ़ोत्तरी की बात आती है तो वहां लड़कियों के स्कूलों को जरूर अपग्रेड करना चाहिए । मैं यह समझता हूं कि जहां सरकार इतने विकास के काम कर रही है उसे इस बारे में भी सोचना चाहिए और इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

इसके अलावा चेयरमैन साहब अब मैं इंडस्ट्रीज के मुताल्लिक कहना चाहता हुं । जहां भी जिक्र होता है दो ही बातों का जिक्र होता है किसान और जमीन । जमीन पर से बोझ हटाने के लिये लाजमी तौर पर दस्तकारी का फैलाव करना होगा और उसमें भी छोटी दस्तकारी को प्रोत्साहन देना होगा । आज देश के अन्दर ऐग्रीकल्चर शोअबे में सब को काम नहीं मिल सकता दस्तकारी में मिल सकता है । हिन्दुस्तान के अन्दर यही चीजें हैं जो लोगों को ऐम्पलायमैंट दे सकती हैं एक तो ऐग्रीकल्चर और दूसरी इंडस्ट्री । ऐग्रीकल्चर तो जमीन के ऊपर डिपेन्ड करती है । जमीन ऐसी चीज है जो खींच कर बढ़ाई नहीं जा सकती । जमीन तो जितनी है उतनी ही रहेगी । हां साधन बढाकर पैदावार जरूर

ज्यादा की जा सकती है । दूसरी चीज है दस्तकारी जिसको घर–घर पहुँचाने के लिये साधन जुटाने होंगे और प्रयत्न करने होंगे । सरकार एक योजना बनाकर हैंडीक्राफ्ट एण्ड हैंडलूम कारपोरेशन बनाने जा रही है और इसी प्रकार से एक इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट बोर्ड भी है । इन सारी बातों से ज्यादा लाभ होगा और खासकर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज से गरीब तबके को लाभ होगा । मेरा यह सुझाव है कि मल्टी– पर्पज कोओप्रेटिव सैटंर्ज ब्लाक लैवल पर बिग विलेज लेवल में खोले जायें । जैसे हैरो बनाने का काम है ऐग्रीकल्चर इम्पलीमैंट्स बनाने का काम है खेलों का समान जैसे फुटबाल या वालीबाल के कवर बनाने का काम है इसी तरह से हैंडलूम की चादरें बनाने का काम है निवार बनाने का काम है, ये सारी चीजें बनाने के लिए मल्टी पर्पज इंडस्ट्रियल सैटर ब्लाक लेवल पर, बिग विलेज लेवल में, तहसील लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खोलने चाहिए । इससे गरीब आदमी को रोजगार मिल सकेगा । सबसे बड़ी फायदे की बात 20 प्वांयट प्रोग्राम में यह हुई है कि जो असैंशियल कोमोडीटीज की कीमतें थीं, वह कम हुई हैं । जो बढ्ती हुई मंहगाई थी वह किसी से नहीं रुक पायी थी लेकिन इस 20 प्यायट प्रोग्राम के बाद यह रुकी है । अगर यह लागू न होता तो शायद यह न रुकती ।

राक दूसरी चीज जो दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर सका. वह आज हमारी प्रधान मैली नें कर दिखाया है वह यह है इन्फलेशन को रोकना । करेन्सी का फैलाव जिसको अमरीका और

फांस भी नहीं रोक सका दुनियां के सारे मुल्क जिसमें फेल हुए हैं उसमें हिन्दुस्तान ने सफलता हासिल की है और वह प्रधान मंत्री के 20 प्वांयट प्रोग्राम पर चलकर हासिल हुई है । आज आप जानते हैं कि 15 अरब रुपया जो बिल्कुल जमीन के नीचे गाड़ रखा था जो डिस्कलोजड नहीं था और जिसका किसी को पता नहीं था कि किसी ने दबा रखा है वह डिस्कलोज हुआ है । अभी और आयेगा और इस तरह का पैसा अगर वे नहीं निकालेगे तो या तो वे जेल में होंगे या फिर किनारे लगे होंगे वे मैदान में नहीं होंगे । देश के पूंजीपति को फिर गरीब आदमी को धंधा देने के लिये पैसा लगाना होगा । वह पूंजीपति अगर देश के गरीब आदमी का खून चूसकर पैसा तहखानों मे रखना चाहेगा तो नहीं रख सकेगा । आज देश का इस तरफ रुझान है और चेयरमैन साहब. मैं यह समझता हूं कि यही एक मौका है जिसमें देश के हर एक राजनीतिक कार्यकर्त्ता कोइस बात को महत्व देना चाहिए और इस बात को ध्यान में रखकर चलना चाहिए क्योंकि यह एक क्रान्ति है और यह आर्थिक क्रान्ति आक रहेगी । इस मैं चाहे कोई अमीर आदमी दुःख पाये या कोई पूंजीपति दुःख पाये, इस बात में कायल होने की जरूरत नहीं है । आज जो नीचे है. वह कल जरूर ऊपर उठेगा । जिसको पहले रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिल पाया था उसको अब अवश्य मिल सकेगा ।

इसके अलावा एक बात और मैं कहूंगा । चेयरमैन

साहब, ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने बहुत प्रगति की है । सारे देश के अन्दर सबसे पहले हमने सारी बसों का नैशनेलाइजेशन किया । 4 लाख किलोमीटर डेली हमारी बसे चलती हैं और 4 लाख 42 हजार मुसाफिर रोजाना सफर करते हैं । इस बारे में मेरा सुझाव है । कई जगह हम देखते हैं कि बसें खराब हो जाती हैं और रास्ते में ही खड़ी हो जाती हैं और जब तक दूसरी बस नहीं आती है मुसाफिरों को काफी तंगी होती है । इस बारे में मेरा सुझाव है कि एक मोबाइल वैन होनी चाहिए । मेरा मतलब मोबाइल वैन वर्कशाप से है । जो लम्बे रूट की बसें हैं जैसे हिसार से चंडीगढ़ भिवानी से चंडीगढ़ दिल्ली से चंडीगढ । इन रूट्स पर मोबाइल वैन वर्कशाप होनी चाहिए जो इस बात पर नजर रखे कि कोई बस रास्ते में तो खराब नहीं हो गई है और मुसाफिरों को कोई तकलीफ तो नहीं है । इन मामूली–मामूली सी बातों से बसों की लाइफ बढ़ेगी । मैं महसूस करता हूं कि हमारी बसों का इन्तजाम जितना बेहतरीन होना चाहिए था उतना अभी नहीं है । हमारे यहां बेहतरीन किस्म के मैकेनिक होने चाहिएं जिससे कि अच्छे किस्म की रिपेयर हो सके । सरकार से मेरी प्रार्थना है कि मोबाइल वैन वर्कशाप का इन्तजाम अवश्य होना चाहिए ।

चेयरमैन साहब बवानी खेड़ा में पिछले दिनों 150 मकान गिर गए थे । मेरी गुजारिश है कि उन लोगों को सैटल करने के लिए हर प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए । इन 150 आदमियों को प्लाट दुकानों के तौर पर अलाट करने चाहिए ।

इसी तरह से जब बयानी खेड़ा तहसील बन गई है तो उसको तहसील का स्टेट्स भी मिलना चाहिए । वहां पर तहसील– दार के बैठने के लिए विल्डिग होनी चाहिए बी० डी ० ओ0 को बैठने के लिए जगह होनी चाहिए पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग होनी चाहिए । अब होता क्या है कि तहसीलदार. रैस्ट हाउस में बैठता है थानेदार धर्मशाला में बैठता है और बी० डी० ओ० किसी प्राइवेट जगह पर बैठता है । रैवेन्यू मिनिस्टर साहब ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 'नो' । चेयरमैन साहब 'नो' कहने से काम नहीं चलेगा । जब तहसील बनी है तो तहसील हैडक्वार्टर का स्टेट्स भी देना चाहिए । बवानी खेड़ा में एक छोटी सी डिस्पैन्सरी है । वहां पर एक अस्पताल होना चाहिए । चेयरमैन साहब तहसील हैडक्वार्टर का जो नार्म है वह पूरा होना चाहिए । मुझे उम्मीद है कि वह नार्म पूरा किया जाएगा । चेयरमैन साहब मैं आपका आभारी कि आपने मुझे समय दिया ।

चौधरी श्याम लाल (पलवल):चेयरमैन साहब सदन में दो दिन से सामान्य बजट पर चची होती रही और आज डिमान्डज पर बहस हो रही है । आपने मुझे समय दिया इस क्यै लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में और वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का उल्लेख किया और इस पर सदन में जो भी माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने अपने विचार रखे । यदि स्वतन्त्रता की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी उसका इतिहास गम्भीरता से पढ़ें

तो उस वक्त जनता के सामने.

चौधरी पीर चन्दः चेयरमैन साहब आन ए प्वांयट आफ आर्डर इन्होंने डिमान्ड का नम्बर नहीं बताया कि कौन सी डिमान्ड पर बोल रहे हैं.?

चेयरमैन चौधरी पीर चन्द : आप कोई डायरेक्ट क्वैश्चन नहीं पूछ सकते कि वह क्या बोल रहे हैं?

चौधरी श्याम लाल : यह आपके पेट में दर्द होने की जरूरत नहीं है । चेयरमैन साहब उस समय जनता के सामने स्वतन्त्र भारत का जो नक्शा पेश किया वास्तव मेँ वह सही चित बीस सूत्रीय कार्यक्म की सफलता पर निर्भर करता है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हरियाणा सरकार इसमें अग्रणी रही है । मजदूर वर्ग की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर और हथकरघा निगम की स्थापना का प्रस्ताव देकर और ऋणों की माफी करके कई प्रशसंनीय कदम उठाए हैए जिससे आज के हर प्राणी को उन्नति करने के बराबर अवसर मिलेंगे ।

चेयरमैन साहब अब मैं सीधा डिमान्डज पर आता हू और सब से पहले मैं डिमान्ड नम्बर दम के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । क्योंकि हमारे स्वास्थ्य भली यहां पर उपस्थित नहीं हैं इसलिए वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह ध्यान से सुनें । स्वास्थ्य समाज की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक चीज है लेकिन मुझे दु:ख है कि मेरा हल्का यानी पलवल इस सुविधा से

वंचित है । वहां पर नाम माल का एक अस्पताल है जोकि बाबा आदम के जमाने का, म्युनिसिपल कमेटी के जमाने में था और आज भी अस्पताल उसी बिल्डिग में चल रहा है और हर पूरक प्रश्न जो भी किया जाता है या जो भी मन्त्री महोदय मेरे हल्के में जाते हैं वहां पर इस बात की डिमान्ड की जाती है । चेयरमैन साहब मैं यह निवेदन करना चाहता हु कि मुझे वह भाषा बताई जाए जिसके द्वारा मैं सरकार से इस उचित मांग के बारे में निवेदन करूं । पिछले दिनों वहां पर फैमिली प्लानिंग का एक कैम्प लगा और 40 के करीब आप्रेशन भी किए गए । वहां पर हमारी हैल्थ सैक्रेटरी मिस मीरा सेठ भी गई थीं । मैं इसे दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं कि उस दिन वहां पर बारिश हो गई और हमारे उच्चाधिकारी को वास्तविकता देखने को मिली । वह बिल्डिग बुरी तरह से टपक रही थी । मीरा सेठ ने कहा कि अब जिन लोगों का आप्रेशन हुआ है उनका क्या होगा और स्वयं उनका दिल दहल उठा । उस समय उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं चंडीगढ़ जाकर सरकार से बात करूंगी । यह तो अधिकारी वाली बात हुई । चेयरमैन साहब. उस अस्पताल का शिलान्यास हमारे. तत्कालीन स्वास्थ्य मली श्री खुरशीद अहमद ने रखा था 1970 में और उससमय उन्होंने कहा था कि कुछ ही दिन के पश्चात मैं बिल्डिंग का उद्घाटन करूंगा । आज वह सत्ता में नहीं हैए लेकिन जो उन्होंने वचन दिया उसका तो पालन करना ही चाहिए । पिछले वर्ष 25 दिसम्बर. को हमारे भूतपूर्व मुख्य मैली वहां गए और एक बहुत बड़ी रैली में उनसे जब यह मांग की गई तो

उन्होंने यह घोषणा की कि यह पलवल का अस्पताल अगले वर्ष के शु रू में आरम्भ हो जाएगा लेकिन उस वर्ष का अब अन्त होने को जा रहा है सुबह पंडित चिरन्जी लाल ने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि चौधरी बंसी लाल ने सड़क बनाने का जो वायदा किया था उसके लिए कोई समय निश्चित नहीं किया था लेकिन चेयरमैन साहब चीफ मिनिस्टर साहब वहां पर तो समय निश्चित करके आए थे । जब सरकार उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का वायदा करती है तो उनके द्वारा किए गए ऐलान और वायदों को पूरा करना चाहिए और खुशकिस्मती से हमारे वर्तमान म्उख्य मली भी उस सभा में उपस्थित थे । गवाही के तौर पर वे सभा में उपिस्थित थे और हमारी राज्य स्वास्थ्य मैली श्रीमती शारदा रानी भी उस सभा में उपस्थित थी और बीच बीच में मैं उनसेप्रार्थना भी करता रहा हूं कि कहीं वह भुल न जाएं । मेरी वित्त मन्नी जी से प्रार्थना है कि इस मांग को गम्भीरता से देखते हुए बजट में कोई न कोई प्रोविजन करने की कूपा करें । बजट को देखने से तो ऐसा लगता है कि कोई पुराना ही बजट रखा है । ऐक्सप्लेनेटरी मैमोरेन्डम टू दि बजट 1976–7 7 के सीरियल नम्बर 52 पर लिखा है––

On page XXXVI at Serial No. 52

"Opening of Pri mary Health Centre at Village Kheri Kalan in Faridabad Block."

जब कि यह प्राइमरी हैल्थ सैन्टर पहले ही है । पता

नहीं कि वहां कोई दूसरा हैल्थ सैन्टर खोलने की योजना है । या तो इस में मिस प्रिंट है या फिर दूसरा खोला जाएगा । इसी प्रकार सीरियल नं० 55 में दिया हुआ है "Continuance of Maternity Block of the Primary Health Cenre Bawal District Gurgaon. " डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में तो बावल है नहीं । मेरे ख्याल में तो यह पिछले साल का ही बजट है । उन्होंने गल्ली से इसे वैसे का वैसा ही छाप दिया है । कोई नई चीज इसमें नहीं जोड़ी गई है । अगर पलवल के हास्पिटल के लिये पैसा हो तो ठीक है, नहीं तो हमारे लिये यह सब बातें पुरानी हैं । एक बार मेरे हल्के में अलालवपुर में डिस्पैन्सरी के सिलसिले में हैल्थ मिनिस्टर साहिबा गई थीं और यह घोषणा कर के आई थी कि यहां पर जल्दी ही एक डिस्पैसरी खोल दी जाएगी लेकिन अभी तक वहां पर कोई डिस्पैन्सरी नहीं खोली गई है । अतः मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि वहां शीघ्र ही एक डिसपैन्मरी खोली जातु ।

उसके बाद एक और विषय पर आता हू । बिजली और सड्कों के बारे में जब भी कोई बातें आती हैं तो सदन में बड़ा हंगामा होता हैऔर भूतपूर्व मुखर मन्त्री महोदय ने यह एलान भी किया था कि जिस प्रकार गांव–गांव में बिजली दी गई है उसी प्रकार सड्कों का जाल भी बिछाया जाएगा । इस ऐलान से लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई । जिन गांवों को सड्कों के साथ नहीं जोड़ा गया है, वह जब देखते हैं कि पड़ोसी गांव सड्कों से जुड़ गया है तो उनको यह देख कर दु:ख होता है कि पड़ोसी गांवों को सड्कों के माथ मिन्ना दिया गया है और वे लोग अभी तक

इस सुविधा से वंचित हैं । वे यह कहते हैं कि जानबूझ कर हमारा गांव छोड़ दिया छू? । पलवल सोहना रोड पर ग्राम गगेरा से ककराली रोड है । उसमें केवल प्वांयट 8 किलोमीटर का एक छोटा सा टुकड़ा है 35 परसैन्ट सडक बननी बाकी है, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कृपा की जाए ताकि लोगों को असुविधा न हो । इस काम को प्रायरिटी पर करवाया जाए । कुछ और सड़के हैं जिनको प्रायरिटी मिलनी चाहिये । एक पलवल घोडी रोड से ग्राम चिडवारी सड़क जोडनी है, दूमरी अहरवा से नगली पद्यानकी तक । ग्राम अलीका से आदूपुर कौ मिलाना भी जरूरी है ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा इस से आगे चल कर मैं कुछ पुलों के बारे में जिकर करना चाहता हूं जिन के न होने से लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है । गौन्ची ड्रेन पर जो प्रुल बनने हैं उन पुलों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । ह्य ड्रेन की गहराई इतनी है कि लोग उसे पार नहीं कर सकते । अतरू गांवों की सुविधा के लिये सिकन्दरपुर, धंतोर, कैराका और छपरोला के पास पुल बनवाने का शीध्र ही सरकार को प्रबन्ध करना चाहिये । इनके लिये भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी ने पलवल की जनसभा में ऐलान भी किया था ।

उससे आगे डिमांड नं ० 3 पर बोलूंगा जोकि ला एण्ड आर्डर के सम्बन्ध में है । यह तो ठीक है कि हरियाणा में ला एण्ड आर्डर सन्तोषजनक स्थिति में है लेकिन हमारे जिले में कई जगहों

पर कुछ होसी स्थिति है कि एक तरग? तो राजस्थान का और ट्सरी तरफ ल ० पी ० काार्डरब लगता है इन प्रान्तों के बदमाश हमारे यहां वारदात कर जाते हैं । अभी सौंधद में जो होडल के गाम है इन डाका पिछले दिनों में पड़ा. दो औरतों ने छत पर चढ कर सहारे के लिये आवाज उठाई और उनको वहीं गोली से उड़ा दिया गया और वे लोग महाजनों के घरों को लूट कर भाग गये । किसी ने आवाज नहीं उठाई वरना लोगों को गोलियों से भून कर ढेर कर जाते । इसी प्रकार मूंह के पास खेडला गांव है, उस में भी इसी किस्म की वारदातें हुई । फिर गदपुरी आश्रम के पास कुछ लोग डी० ऐल० जैड० कार में आये और ग्राम हरफली पर रात को सर्च लाइट फैकी और दो तीन बार फायरिंग भी की गई और फिर वह लोग भाग गये पता नहीं वही टोली थी या कि दूसरी । तो इस प्रकार से ऐसी दहशत वहां फैली हुई है । सरकार को जल्दी ही इस ओर ध्यान देना चाहिये ताकि ऐसी वारदातें आगे से न हों । ऐसे ऐलीमैन्ट्स को सख्ती से कुचला जाना चाहिये ताकि गरीब आदमी, भले आदमी आराम से रह सकें (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) ।

अध्यक्ष महोदय, अब इसके बाद मैं ऐजुकेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हू । एजुकेशन में जो एक केंसर हो चला था, वह था नकल । पिछले वर्ष से जो नकल रोको अभियान सरकार ने चलाया है उससे अच्छे परिणाम होंगे । इस पर अगर इस प्रकार से अमल किया गया तो बहुत बड़ा उधार होगा क्योंकि अब जो

ऐजुकेशन का पैमाना था वह था सनद होना उससे जो आदमीं कमजोर थे वहू तो फस्ट डिवीजन ले रहे थे और होशियार लड़कों के ऊपर यूं ही झूठे केस बन जाते थे । यह एक ऐसी बीमारी चल पड़ी थी जिस से हमारी आने वाली पीढी अपने हाथों से अपने जीवन को नष्ट करने में लग रही थी ।

स्पीकर साहब, मैं आपको बताता हू कि सन् 1961 की सैन्सस के अनुसार हमारी स्त्री–शिक्षा का स्तर 92 था और 1971 में दस सालों में 146 हो पाया है । यह कोई सन्तोषजनक प्रगति नहीं है । चौधरी ईश्वर सिंह जी ने बोलते हुए कहा था कि स्त्री–शिक्षा समाज के उत्थान के लिये बहुत जरूरी है । क्योंकि लड़का जब पढ़ता है वह अकेला पढ़ता है और लड़की जब पढ़ती है तो समझो दो परिवार उन्नत हो रहे हैं । इसलिये स्त्री–शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाए । अप–ग्रेडेशन के बारे में चौधरी साहब से जब भी बात करते हैं तो वह करते हैं इस साल कोई अप–ग्रेडेशन नहीं होगी । मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम स्त्री–शिक्षा की उन्नति को ध्यान में रखते हुए लड़कियों के स्कूलों को तो अप–ग्रेड कर दो ।

अब मैं डिमांड नम्बर 1 5 के बारे में बोलना चाहता हू जो इरीगेशन के बारे में है । इरीगेशन के सम्बन्ध में तो हरियाणा का कार्य भारत में पहले नम्बर पर है । यह भी एक वंडर है कि जमीन से 550 फुट की ऊंचाई तक पानी को उठा कर खेतों को दिया जा रहा है । इसके लिये हम सरकार और विशेष रूप से

भूतपूर्व मुख्य मन्त्री चौधरी बंसी लाल जी के आभारी हैं । लेकिन इन बड़ी–बड़ी 'योजनाओं के पीछे जो छोटी–छोटी योजना हैं वह दबी रह जाती हैं । ठीक है शरीर की बड़ी बीमारी का इलाज होना चाहिये लेकिन जो छोटी मोटी फिन्सीयां हैं उसका भी तो इलाज होना चाहिये । इस विपय में मैं एक निवेदन करना चाहता हु कि मेरे हल्के में एक डटावर डिस्ट्रीब्यूटरी गुजर रही है । वह पिछले दिनों चल रही थी क्योंकि वह नीचे से खोदी नहीं गई थी और रेतीली होने की वजह से उसके किनारे टूट गये । एक गांव में एक जमींदार की जमीन में डिस्ट्रीब्यूटरी टूटने की वजह से 10–12 किल्लो में पानी ही पानी भर गया । जब उस जमींदार को पता लगा कि जमीन में पानी भर गया है तो वह कस्सी लेकर अपनी जमीन पर गया ताकि पानी को रोकने का कोई इन्तजाम किया जा सके । जब वह पहुंचा तो उधर से अधिकारी लोग भी जा पहुंचे । अधिकारियों ने उस आदमी को देखा जिसकी जमीन थी । उन्होंने समझा कि इसी ने पानी तोड़ा है और उस पर केस बना दिया कि तुमने ही तोड़ा है । तो मेरा यह निवेदन है कि जब तक यह डिस्ट्रीब्यूटरी पक्की नहीं की जाती तब तक यह चल नहीं सकती है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस डिस्ट्री– ब्यूटरी को पक्का करवाया जाए । मेरे इलाके में दो तीन गांव ऐसे हैं जो पानी के सिलसिले में बड़े दुर्भाग्यशाली हैं । किसानों ने कई सौ फुट तक बोरिंग की लेकिन पानी खारा निकलता है । ये गांव हैं जतौली, पिरथला और अहखां । इन गांवों के लिये या तो माइनर इरीगेशन ट्यूबवैल्ज कार्पोरेशन द्वारा ट्यूबवैल दिये जाएं या इनके

साथ–साथ जो रजवाहे हैं उनको ऐक्सटैंड किया जाए । इसके बाद में एक दो छोटी–छोटी बातें और कहना चाहता हू, जैसे फारैस्ट की बात है । हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है । ऐसे ही यू ० पी० और हिमाचल फारैस्ट प्रधान हैं । यू ० पी० का तो हम मुकाबिला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने थोड़े समय में जो प्रगति इस सिलसिले में की है वह उल्लेखनीय है, जैसे हमने मोरनी हिल्ज पर जाकर देखा और हम सड्कों के साथ–साथ भी देखते हैं । लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि कुछ समय पहले कुछ गांवों में फारैस्ट के लिये जमीन रिजर्व की गई थी लेकिन जिस उद्देश्य के लिए जमीन रिजर्व की गई थी उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है । मेरे हल्के में एक दीघोट गांव है वहां 60 एकड़ जमीन फारैस्ट के लिये रिजर्व की गई थी, लेकिन वहां वृक्ष नाम की कोई चीज नहीं है । वृक्ष लगाने के लिये वहां जो आदमी लगाए हुए हैं उनकी तनखाह पड़ रही है और उसके अलावा उन्होंने एक तरह का आमदनी का धंधा बनाया हुआ है । तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जहां–जहां ऐसी जमीनें हैं, वे किसानों को लौटा दी जाएं ताकि वे उसे कृषि के प्रयोग में ला सकें । इसी से संबंधित ऐग्रीकल्चर भी है । ऐग्रीकल्चर ने हमारे प्रदेश में बड़ी नुमाया तरक्की की है । और हमारी ऐग्रीकल्चर युनिवर्सिटी हिसार जो है वह मैं समझता है कि हिन्दुस्तान में एक ही चीज बनी है और उसमें जो प्रयोग करके हाई इल्डिग वैरायटी के बीज किसानों को दिये जाते हैं उससे हमारी कृषि की उपज में बड़ी बढौत्तरी हुई है । कृषि के उत्थान में एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन ने

भी बड़ा अच्छा भाग निभाया है यानी किसानों की खेती अब मैकेनाइज्ड फार्मिग होती जा रही है । छोटे–छोटे किसान भी आज ट्रैक्टरों के पीछे भागते हैं । उन ट्रैक्टरों को खरीदने के लिये, उनकी रिपेयर के लिये और उनके पुर्जे खरीदने के लिये यह ऐग्रो इंडस्ट्री साधन जुटा रही है । मैंने पीछे भी कहा था कि यह जो ऐग्रो इंडस्ट्री ने वर्कशाप खोले हुए हैं इनको और भी बढ़ाया जाना चाहिये । मैंने एक और भी तजवीज दी थी कि हर ब्लाक में एक कामन फैसिलिटी वर्कशाप हैं जो नो प्रोफिट नो लौस बेसिज पर चलाए गये थे । लेकिन किसी भी ब्लाक में आपने जाकर देख लें वह बेकार पड़े हें । मेरे हल्के में दो वर्कशाप हैं दोनों बेकार पड़े हैं । इसलिये उनको ऐग्रो इंडस्ट्री वर्कशाप में तबदील किया जाए । इंडस्ट्री की बात तो मैं क्या कहूं क्योंकि हमारे वहां तो कोई इंडस्ट्री नहीं है लेकिन मैं यह मांग करूंगा कि वहां की लोकेशन को देखते हुए वैसे ही वहां इंडस्ट्री होनी चाहिये । वहां पर ड्राई पोर्ट बननी चाहिये । आप लोगों ने अखबार में पढा होगा और जो अधिकारी वहां गये थे उनकी भी यही राय थी कि पलवल के अतिरिक्त ड्राई पोर्ट के लिये कोई और स्थान उचित नहीं है । लेकिन कई दफा राजनीतिक दखल की वजह से बाईकाट हो जाता है । मेरा सरकार से निवेदन है कि उस इलाके में ड्राई पोर्ट बनाया जाना चाहिये जिससे हमें बहुत भारी उपलब्धि होगी । मैं तो यह समझता हूं कि हमारी तो मारी मांगें पूरी हो जाएंगी, अगर वहां ड्राई पोर्ट बना दिया जाए क्योंकि ड्राई पोर्ट की वजह से वहां हस्पताल भी अपने आप बन जाएगा और सड़कें भी बन जाएगी ।

इस काम के होने से जहां मेरा अपने हलके का स्वार्थ है वहां इससे हरियाणा का भी स्वार्थ जुड़ा हुआ है । इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

16—00 बजे

मलिक सतराम दास बतरा (कलानौर) : अध्यक्ष महोदय, बड़ी सराहनीय बात है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदयने अपने भाषण में हरियाणा में वाटर रिसोर्सिज बढ़ाने के बारेमें एक लौंग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने और एक मास्टर प्लान बनाने की बात कही है । डिमांड नम्बर 1 5 में सात करोड़ रुपया मांगा गया है और व्यास डैम पर जो काम चल रहा है उसके लिये यह है । मैं समझता हू कि इस डैम के बनने से हमारी आशायें सफल होंगी और हुमारे जो सूखाग्रस्त इलाके हैं उनको पानी मिलेगा । अध्यक्ष महोदय किसान को कई किस्म की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है । कभी सूखा है, कभी ज्यादा बारिश है और कभी मौनसून का जुआ है जिससे किसान हर साल खेलते रहते हैं । कभी तौ ऐसा होता है कि कई—कई साल तक बारिश नहीं होती, गांव में कुओं का पानी कडुवा हो जाता है और हमारे कई क्षेत्र ऐ से हैं जहां पर पानी बैकिश है । तो मैं सरकार से आशा करूंगा कि सरकार इन इलाकों की हालत सुधारने के लिये इस तरह से लौंग टर्म स्ट्रैटेजी और मास्टर प्लान बनाये जैसे कि इस बजट में आये हैं और उन पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च होता रहे । वह वक्त आयेगा जब हम कहेंगे कि सारे हरियाणा की चप्पा—चप्पा

जमीन में पानी लग गया है या थोड़े ही समय में लग जायेगा । इसके साथ–साथ मैं अर्ज करता हूं कि जो हमारे पुराने वक्तों के नाले हैं जिन पर सीपेज को रोकने के लिये पक्का करने का काम एऊएम० आई० टी ० सी० ने शुरू किया है उन की तरफ अफसरान को ध्यान देने की जरूरत है । वे देखे कि कुछ नाले छेसे हैं जो दो अढाई मील लम्बे हैं जिनकी लम्बाई ज्यादा होने की वजह से टेल पर फलो कम हो जाता है । वहां पर फलो इतना कम हो जाता एं कि जब पानी टेल पर पहुंचता है तो 12/14 घंटे में भी एक किल्ले की सिंचाई नहीं होती । मूड में पानी लगने पर 3/4 घंटा में एक किला की सिंचाई होती है । यह तो पालिसी बनाई है कि तीन सौ एकड़ से कम पर आउटलैट न हो यी तो ठीक है और यह नहीं होना चाहिये कि दो अढाई मील लम्बे नारने पर एक ही आउटलैट हो क्योंकि जब टेल की जमीन पर पानी जाता है तो कई मील पानी जाने की वजह से उसका फलो घटु जाता है जिससे किसान को बहुत मुश्किल होती है । हम जौ सूखाग्रस्त इलाकों में रहते हैं जहां पर पानी की कमी है उन की इन प्रोजैक्ट्स से, जो बने हैं और बन रहे हैं जैसे व्यास प्रोजैक्ट है, आशायें बंधी हैं । एक स्कीम यू ० पी० से गंगा से पानी लेकर इधर डालने की बात चली थी लेकिन उस में हम सफल नहीं हुये हैं लेकिन फिर भी अगर हम इस तरह से काम करते जायें तो वह वक्त दूर नहीं जब हमारे स्वप्न पूरे हो जायेंगे और हमारे सूखे खेतों को पानी मिल जायेगा तो मेरा सुझाव है कि जहां ऐम० आई० टी ० सी० का काम चल रहा है जहां नहरों से वाटर

लागिंग हो गई थी, जमीन कल्लर हो गई है उनको पक्का कर रहे हैं ताकि सेम खत्म हो, सीपेज बंद हो कर खेती के लिये ज्यादा पानी मिल सके वहां किसान की बहबूदी के लिये यह भी जरूरी है कि ये जो लम्बे–लम्बे नाले हैं जिन में लम्बा होने की वजह से पानी कार फलो घट जाता है और टेल के किसान को मुसीबत आ जाती है उसकी खेती को पानी नहीं मिलता, एक दिन में एक किल्ला भी सैराब नहीं होता, उनको छोटा किया जाये ताकि पानी का फलों बढ़े । डिमांड 16 किसान की तरक्की के लिये और उसकी खुशहाली के लिये बहुत जरूरी है और यह स्माल स्केल इन्डस्ट्री के बारे में है । जो किसान थोड़ी जमीन के मालिक हैं, जो सीलिंग के बाद थोड़े एकड़ के मालिक रह गये हैं और जैसे–जैसे आबादी बढ़ रही है, जमीन बंटने से छोटे–छोटे टुकड़ों में जमीन बंट गई है और बहुत छोटे किसान बन गये हैं उनको इस स्माल स्केल इन्डस्ट्री के फैलाव से बहूत फायदा हो सकताहै । जमीन थोड़ी होने की वजह से उनके पास सारे साल के लिये काम नहीं होता और वह बेकार रहते हैं । इससे एक तो मैन–पावर आइडल रहती है, दूसरे किसान की आमदन कम हो गई है क्योंकि जमीन थोड़ी है उनके पास और उनका जमीन से गुजारा नहीं चलता है । तो अगर देहात में यह छोटी इन्डस्ट्री चली जाये और ऐसे काम देहात में शुरू हो कि जिन से उनको रोजगार मिल जाये लेकिन इस में दिक्कत यह आती है कि जो बड़े बड़े शहरों में जो प्लांट्स हैं, जो आटोमैटिक होते हैं और बड़े सरमाये वालों के होते हैं उनके सामने मुकाबला पर स्माल

स्केल इन्डस्ट्री वाले टिक नहीं पाते, क्योंकि उनको मार्किट नहीं मिलती । इसलिये मेरा सुझाव है कि जो स्माल इन्डस्ट्री वाले सामान बनायें, उनको सरकार खुद खरीदे और आगे मार्किट में ले जाये । छोटे दस्तकार के लिये ऐसी मार्किट की सुविधा हो कि जो सामान बनाये शाम को वह मार्किट में बिक जाये । अगर इस तरह की कोई योजना बनेगी, तभी यह स्माल स्केल इन्डस्ट्री की स्कीम कामयाब हो सकेगी । देहात में कोआप्रेटिव बेसिज पर खड्डी का काम भी शुरू हो रहा है । इस बारे में मैंने पहले भी अफसरों को सुझाव दिया था कि जब तक इनके पीछे मार्किट की' सुविधा नहीं होगी खड्डी देहात में पनप नहीं सकेगी । तो मेरा सुझाव है कि स्माल स्केल इन्डस्ट्री को देहात, में फैलाया जाये ताकि वहां पर बेकार किसानों को जो अब थोड़ी जमीन के मालिक रह गये हैं और जो खाली बैठे रहते हैं उनको साइड बिजनैस मिल जाये, उनकी आमदनी बढ़ सके लेकिन जो सामान वहां पर बने उसकी मार्किट का प्रबंध जरूर किया जाये ताकि वे बड़े प्लांटों वालों के मुकाबला में स्टैड कर सकें । गांव में बिजली चली गई है लेकिन वह लोग बिजली की यूटिलाइजेशन चक्की और गंडासा चलाने के लिये ही करते हैं क्योंकि और कोई उद्योग वहां पर है नहीं । इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि पावर जो इन्डस्ट्री के लिये जरूरी होती है पहले ही गांव–गांव में चली गई है अब वहां पर स्माल स्केल इन्डस्ट्री चलाने की जरूरत है ताकि उन बेकार लोगों को काम मिल सके । जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया अगर देहात में कोई छोटा उद्योग चलाता भी है तो वह फेल हो जाता है क्योंकि

पाम में देहली में बड़े बड़े प्लांटों के मालिकों के सामने वह टिक नहीं पाता और अपने माल कें लिये मार्किट कायम नहीं कर पाता । इस बात की तरफ ध्यान देने की जरूरत है ।

अब मैं खेतीबाड़ी की तरफ आता हूं । इसमें शक नहीं कि इसमें बहुत तरक्की हुई है । यह जो सरकार ने डेढ़ दो साल से गोबर गैस प्लांट का प्रयोग चलाया है इससे मैं समझता हूं कि देहात के किसान को बहुत फायदा हुआ है । पहले वह गोबर को चूल्हे में जलाता था लेकिन अब इस गोबर गैस की स्कीमें चलने सेन सिर्फ किसान का गोबर जो बेहतरीन बाद है जलनेसे जाया होने से बच गयाहै बल्कि मेरा जाती तजरुबा है उसे डेढ दो सौ रुपये महीना का फायदा भी हो गयाहै । पहले किसान एक दो ट्राली महीने में गोबर की जला देता था । खाद महंगा हो जाने की वजहसे गोबर की कीमत बहुत बढ़ गई है और गोबर की एक ट्राली पचास साठ रुपये से कम पर नहीं मिलती है । मेरा यह जाती तजरुबा है कि गोबर गैस प्लांट से जहां कर में सफाई रहती है, वहां जो गोबर किसान ईंधन के लिये जला देता था वह अब बच कर खाद के काम आताहै और डेढ दो सौ रुपये महीने का उसे फायदा भी हो जाता एट । चीजों के बारे में जो सुधार हुआ है वह भी बहुत सराहनीय है । लेकिन इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन जमींदारों को फाउंडेशन सीड दे कर सरकार बीज उगवाती है और फिर उस बीज को लेकर आगे दूसरी स्टेट्स को बेच कर जो मुनाफा कमाती है उस मनाके में उस जमींदार को

भी हिस्सेदार बनाया जाये । आप उसे यह फाउंडेशन सीड इतना मंहगा देते हैं कि एक बैग उसे 32/33 रुपये में पडता है । फिर उसे इतना मंहगा लेकर उगाता है और बहुत सारा रुपया ट्रांसपोर्टेशन और ग्रेडिंग वगैरा पर खर्च करता है और इतना खर्च करने के बाद आप उसे 150 रुपये का भाव देते हैं जो सरकार आगे मुनाफा पर दूसरी स्टेट्स को सप्लाई करती है । तो मेरा सुझाव है कि यह जो मुनाफा सरकार को होता है उसका हिस्सा उस जमींदार को भी मिलना चाहिये जो उसे उगा कर सरकार को देता है । गन्ने के बारे मेंमैं कहना चाहताहूं कि बहुत अच्छी–अच्छी किस्म का गन्ना निकाला गया है और इसमें कई तरह के प्रयोग हुये हैं । 975 और 1148 से 1158 की किस्मों का गन्ना निकाला गयाहै जिससे गन्ने की पैदावार भी बढ़ी हैऔर शूगर कन्टैंटस भी बढ़े हैं । आज वह देशी गन्ना 12 नम्बर का कहीं नहीं मिलता, क्योंकि उस में कीड़ा हो गया था और उसकी पैदावार और शुगर कन्टैटंस में कमी आ गई थी । लेकिन अब जो गन्ना जमींदार उगा रहा है उससे पैदावार भी ज्यादा होती है और शुगर कन्टैटंस भी ज्यादा बढ़े हैं । रोहतक शूगर मिल एरिया में गन्ने की पैदावार इस वक्त 60 लाख टन से भी ज्यादा है लेकिन रोहतक शूगर मिल की गन्ना पेलने की कपैसिटी 17 लाख के करीब है । मगर गन्ना इससे कहीं ज्यादा पैदा होता है । मैं नहीं समझता कि सरकार क्यों खामोश है? अगर मिल सारा गन्ना नहीं पेल सकती तो क्यों न सरकार जमींदारों को क्रैशर लगाने के लाइसैसं दे देती ताकि उन का गन्ना जाया न जाए । यह जमींदार के साथ अन्याय है ।

आप सरकार के आंकड़ों को देखें कि 60 लाख की प्रोडक्शन है और मिल की कपैसिटी 17 लाख की है । तकरीबन 42 लाख का गन्ना बचता है । आप बताएं, किसान उसको कैसे पेले? इसलिए अफसरान को सही रिपोर्ट देनी चाहिए ताकि सरकार कोई पालिसी बना सके और मेरी सरकार से दखवास्त है कि इस सिलसिले में कोई न कोई फैसला करे ।

स्पीकर साहब, 2० प्वांयट प्रोग्राम के अन्दर ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ाने की बात कही गई । मैं उन जमींदारों की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने इस साल रिकार्ड–तोड़ गन्ना पैदा किया है । सरकार को चाहिए कि इन के लिए ऐसी सहलियात उपलब्ध करे जिससे किसान परेशान न हो । यह ठीक है कि हारवैस्ट सीजन शुरु होने से जमींदार का ध्यान फसल काटने में लग जाता है और गन्ना खड़ा–खड़ा खराब हो जाता है, गन्ना मिलों में नहीं जाता क्योंकि किसान व्यस्त होता है । इसलिए सरकार इस तरफ ध्यान दे कि जल्दी से जल्दी गन्ना क्रश किया जाए ।

इसके इलावा सरकार ने सर्प्रिकलिग पम्पों का जो प्रोग्राम ऐक्मपैरिमैंट बेमिज पर शुरू किया है, यह निहायत ही फायदेमन्द चीज है । जिन जिन इलाकों में मर्प्रिकर्लिग पम्प लगे हैं, मैं समझता हु कि सरकार की और खाम तौर पर चौधरी बंसी लाल के दिमाग की उपज है कि उन्होंने उन रेतीले इलाकों में जिन में एम० आई० टी० सी० के कुछ नहीं, नहीं नहरें, पानी नहीं पहुंचता, रेतीला इन्नाका है, रैगूलर पानी की सप्लाई नहीं है,

केवल मानमून में बरसात होती है, उन इन्नाको में फैमिन और कहत रहता है, ऐसे इलाकों में तजर्बे के तौर पर सर्प्रिकर्कालंग पम्प लगाए हैं, मैं हुस बात की प्रशंसा करता हु । जापान और इजरायल जैसे देश, चौथाई हिस्सा पानी इस्तेमाल करके हमसे ज्यादा फसल उगाते हैं । हमारे यहां जो नाके लगते हैं उन से पानी बहुत वेस्ट होता है, उसकी निस्बत सर्प्रिंकलिग पम्पों से पानी देने से चौथाई हिस्सा पानी खर्च होता है । इन के इस्तेमाल करने से सीपेज भी नहीं –होती, पानी की बचत होती है । मर्प्रिंकलिग पम्पों की स्कीम बड़ी सराहनीय है, इसको जल्दी से जन्दी सारे हरियाणा में, सब–डीविजनल लेवल पर, जहां खेतों में ज्यादा पानी लगता है, लागू करना चाहिए । जहां तक एम ० आई० टी० सी ० का ताल्लुक है, इसके मुताल्लिक मैं अभी कह रहा था, ठीक है कई स्थानों पर एम ० आई० टी ० सी 9 का काम शुरू है लेकिन कृछ इंजीनियर्ज, जिन की मर्जी यह थी कि पत्थरों की नालियां बनाका उन में जल्दी से जल्दी पानी चलाया जाए, उनका यह तजुर्बा गलत साबित हुआ क्योंकि पत्थर अपनी जगह स्टैड नहीं कर सकता । बड़ा अच्छा हुआ, सरकार ने इस पात्निसी को बदन्न दिया । और नालियाँ इंटों मै बनानी शुरू कर दीं । इसके माथ ही साथ मैं सरकार से सिफारिश करूंगा कि नालियों में अच्छे से अच्छा मैटीरियल लगाएं । नालियां बनाने से पहले इनका सर्वे करवाया जाए क्योंकि कई नालियां ऐसी हैं जो नीचे मैं जाकर नीची रह गई हैं और टेल ऊंचा है । ऊंची नीची होने के कारण पानी ठीक से नहीं चलता । (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुईं ।

) इमके इलावा किसान से 27 परसैटं सुपरवाइजरी चार्जिज वसूल करते हैं । डिपार्टमैंट को इतना चार्ज नही करना चाहिए । ओवर सीयर की गलती हो, चाहे किसी और की गलती हो, उस गलती का न्उकसान किसान को भुगतना पड़ता है । इसलिए एम ० आई० टी० सी ० ठीक तरह के सर्वे करवाए और मैटीरियल अच्छा लगाए ।

इसके इलावा मिल्क प्लांट सरकार ने तीन स्थानों पर लगाए हैं । एक लाख लिटर दूध की कपेसिटी का प्लांट रोहतक में कमीशन होने जा रहा है, एक 15 हजार की कैपीसिटी का भिवानी में चल रहा है और एक जींद में चल रहा है । अम्बाला में भी. एक मिल्क प्लांट है । किसान को यह प्रोत्साहन दिया जाता है कि वह सरकार से या बैकों से कर्जा लेकर भेसे खरीदे । वह तीन चार हजार की भैस खरीद कर उसको बनौला, चना नहीं चरा सकता क्योंकि बनौले और चने का भाव बहुत महंगा है । मिल्क प्लांट वाले फैटकन्टैट लेते हैं और उसी हिसाब से दूध लेते हैं और पेमेंट करते हैं । अगर किसान घास डाल कर दूध दे तो उसमें फैट कंटैंट कम होते छंद और पेमेंट कम होती है । अगर उसने दो रुपये किलो द्ध बेचना है और सही रेट लेना है तो उसको बनौले चराने ही पड़ेंगे लेकिन बनौलों और चनों का भाव अधिक होने के कारण वह चरा नहीं सकता । इसलिए मेरी गुजारिश है कि किसान को वगैर फैट वाले दुध के का मोल दिया जाए । इस दूध से बेबी–फूड बनता है, ड्राई मिल्क बनता है,

सप्रेटा दूध से कई किस्म के पाउडर बनाते हैं, इन चीजों में भी किसान का हिस्सा होना चाहिए । किसान की भैस 6 महीने दूध देती है । अगर किसान यह मान कर चले कि उसे इस में प्रौफिट होगा और यह उसका साइड बिजनैस है तो उसका उत्साह बढेगा । इमलिए मेरी सरकार से प्रार्थना हैकि सफेद क्रान्ति लाने के लिए सरकार इस काम में सहयोग दे । जब किसान सोचने लग जाएगा कि मुझे इसमें फायदा है तो वह लग्न से काम करेगा । जसे एक हलवाई सोचता है कि उसे दूध में फायदा है, चाहे दूध गाय का हो, चाहे भैस का हो, चिलिग सैटर से चार–आठ आने फालतू देकर वह दूध खरीद लेता है, क्योंकि उसको फायदा होना है । इसी तरह किसान को भी इन्सैंटिव होना चाहिए । अभी हमारे मिनिस्टर साहब, दो दिन पहले मिल्क प्लांट्स के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपकी मार्फत बताना चाहता हूं कि तीनों मिल्क प्लांट घाटे में चल रहे हैं । आप इनका आडिट करवाओ या न करवाओ, ये हिसाब दिखाएं या न दिखाए, लेकिन यह ठीक है कि ये घाटे में चल रहे हैं । इसलिए यदि आप जमींदार को सहुलियत नहीं देंगे और सिर्फ कर्जा देकर भैंसें ही बांधेंगे तो इस दिशा में लिए तरक्की नहीं हो सकती । किसान को घाटा पड़ेगा, किसान के दुध के दाम ऊंचे से ऊंचे मिलने चाहिएं ताकि उसकी हालत सुधर सके ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, हैल्थ के बारे में कई सदस्यों ने कहा, डिमांड भी की है । मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं उनके नोटिस

में लाना चाहता हूं कि कलानौर बहुत बड़ा कस्बा है, वहां पर नोटिफाइड एरिया कमेटी है । जहां और काम हो रहे हैं, वहां एक छोटी सी डिस्पेंसरी बना दी जाए तो बहुत मेहरबानी होगी । एक टूटी हुई डिस्पेंसरी है जिस के लिए बी० एंड आर० वालों ने एक नोट लिख कर भेजा है कि अगर कोई मरीज उसके अन्दर रखा जायेगा और ऊपर से छत गिर गई तो हम जिम्मेवार नहीं होंगे । उसकी छत गिरने वाली है । मन्त्री महोदय इस की तरफ ध्यान दें । ठीक है, यहां पर रैफरल हौस्पिटल बनाने की स्कीम है लेकिन कलानौर का नम्बर 21 वां आता है और अभी तक 11 नम्बर तक पहुंचे हैं । इसका मतलब यह हुआ कि हौस्पिटल जल्दी बनने वाला नहीं है । लेकिन कस्बे वाले बहुत ज्यादा धन राशि दान के रूप में देंगे जिसकें बारे में मैंने मु ख्य मन्त्री साहब को बता दिया है और आपको भी बतला रहा हूं । इस काम में पांच छः लाख रुपया लगेगा । जितना बड़ा यह कस्बा है उसी हिसाब से यहां एक हौस्पिटल होना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं । उपाध्यक्ष महोदया, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे बोलने के लिए टाईम दिया ।

चौधरी कबीर अहमद (नूह) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे अपने हल्के में बहुत ही ज्यादा काम हुआ है और काफी तरक्की हुई है । यह बहुत बड़ा काम था, मुश्किल का काम था लेकिन हमारी सरकार ने किया और हमें हर सहूलियत सरकार ने दी ।

दूसरी बात यह है कि आजकल हमारे हर गांवों में पीने का पानी मिल रहा है । पहले हमें तीन–तीन मील से पानी लाना पड़ता था । लेकिन अब वहां पर वाटर सप्लाई स्कीम से पानी लोगों को मित रहा है । जहां हरियाणा के अन्दर नहरें नहीं थी वहां पर इस सरकार ने नहरों का इन्तजाम किया । जहां पर सड़के नहीं थी, उन गांवों को सड्कों के साथ मिला दिया । इस जमाने में जिन चीजों की लोगों को जरूरत थी, वही मुहैया की गई ।

महात्मा गान्धी जी ने हमें सन् 1947 में एक बहुत अच्छी बात बतायी । उस टाईम पर गांव के लोग घबराते थे कि हमारा क्या होगा? उन्होंने कहा कि तुम घबराते क्यों हो? देहात में ही सब कुछ पैदा होता है । उन्होंने कहा था कि इस सृष्टि में कितने ही देहात हैं । उन्होंने बताया था कि 85 लाख 86 हजार गांव हैं और हुनमें छोटे–छोटे और भी काफी हैं । उन्होंने कहा जो कुछ भी करेंगे देहात वाले ही करेंगे । सरकार की मदद करोगे तो भी तुम ही करोगे । सरकाररू सारे काम तुम्हारी कमेर से ही कर रही है । जब सरकार के खजाने खाली हो जाते हैं, तो सरकार हमारे पर टैक्स लगाती है । जब किसी दूसरे मुल्क ने हिन्दुस्तान पर हमला किया, तो इन गांवों के लोगों ने जीत करके दिखायी है । हमें भी हुस बात को याद रखना चाहिए कि हमारी सरकार हमारी परवरिश कर रही है । हमारे पहले चीफ मिनिस्टर ने और दूसरे चीफ मिनिस्टर ने बहूत काम किया है और आगे भी हमारे चीफ

मिनिस्टर साहब बहुत काम करेंगे । हमारी हकुमत ने वही काम किया है जिसको हम चाहते थे । हमने अंग्रेजों की हकुमत को भी देखा है । उन्होने हमारे लिए कोई खास काम नहीं किये थे । मैं तो यह कहूंगा कि जब से यह दुनियां बसती आ रही है तब से आज तक कभी इतना काम नहीं हुआ । हम अपनी हकूमत को किसी भी चीज से इन्कार नहीं करते हैं, चाहे यह कितने. ही टैक्स लगाये. चाहे हमारी कितनी ही जमीन ले ले, हम सब कुछ देने के लिए तैयार है ।

दूसरी बात यह है कि मेरे हल्के के कुछ काम ऐसे हैं जो बाकी रह गये हैं । गुडगांवा कैनाल है यह तीन धाराओं में बहती है । एक तो डिस्ट्रिब्यूटरी उटावड है, दूसरी इन्डरी और तीसरी डिस्ट्रिब्यूटरी नूह है । तीनों डिस्ट्रिब्यूटरीज आगे जा कर रूक गई हैं । इनका पानी आगे तक नहीं जाता है । मैं सिंचाई के अफसरों को मोटर गाड़ी में बैठा कर ले गया था औंर उनको सारा मौका दिखाया था कि इनमें आगे पानी नहीं चल रहा है । सिंचाई विभाग के अफसर भी यह मान गये हैं कि इनमें आगे पानी नहीं चलता है । इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि इनको पक्का किया जाये ।

दूसरे हमारे यहां कुछ पुल भी ऐसे हैं, जिनके बिना हमारे इलाके के लोगों को दिक्कत पड़ती है । उन पुलों के न होने से हमारे मवेशी पहाड़ों में नहीं जा सकते हैं । गुड–गांव कैनाल से इडरी डिस्ट्रिब्ट्री निकलती है । इस पर एक पुल

खानपुर से इन्डरी जाने वाले रास्ते पर होना चाहिए । महकमे के अफसरान ने भी इसकी सिफारिश की है । जब हमारे मवेशी पहाड़ों में जाते हैं तो नहर को पार करके निकलना पड़ता है । नहर सरकार के कन्ट्रोल में है । वे नहर में से मवेशियों कौ पार होने से रोकते हैं । इसलिए मैरी सरकार से गुजारिश है कि ये पुल जरूर बनना चाहिए और भी चार पांच छोटे–छोटे पुल हैं, जो बनने चाहिएं ।

एक पुल उजीना डेरन पर जोगीपुर से हैथीन वाली सड़क पर बनना बहुत जरुरी है । ईसके बिना भी लोगों को काफी मुश्किल पेश आती है । वहां पर भी लोग पहाड़ों में नहीं जा सकते हैं । इसी ट्रेन पर एक पुल घसैडा गांव से छपडा गांवों के रास्ते पर बनना चाहिए । इस पुत के न बनने से बारिश के दिनों में हमारी बहिन बेटियां कपड़े उतार कर निकलती हैं । तीसरा पुल उजैना ड्रेन पर जिसका नम्बर आर० डी० 40200 है पापडा गांव के रास्ते पर बनना चाहिरा । यह रूल तो इसलिए भी बनना जरूरी हए कि जब इस गांव के लोग इस ड्रैन को पार करते हैं, तो वहां दुनियां भर के लोग खड़े हो जातै हैं क्योंकि हमारी बहिनों को कपड़े उतार कर इस ड्रैन को पार करना पड़ता है । तो हुन पुलों को जरूर बनाया जाये । हमारी जो नहर का पुत्र है वह भी जरूर बनाने की कृपा करें । अगर कोई औंर तकलीफ होगी तो वह भी हम सरकार से कहेंगे । हमारी हकूमत बहुत अच्छी है और इस हरियाणा में बसने वाले लोग इसको सदा याद रखेंगे । मैं इतना

कह कर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए टाईम दिया ।

चौधरी पीर चन्द (बरवाला अनुसूचित–जाति) : उपाध्यक्ष महोदया, बजट के ऊपर कई दिनों से बहस चल रही थी और आज डिमान्डज पर भी हाउस में चर्चा हो रही है । मैं सब से पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोरनने के लिए टाईम दिया । मैं आपके सामने डिमान्ड नम्बर दो, तीन. नौ, दस और 13 पर बोलना चाहता हूं और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हुं । यदि हमारे मुख्य मली जी यहां हाउस में होते तो और भी अच्छा होता लेकिन फिर भी काफी दूसरे मिनिस्टर बैठे ट्रे, वे भी मेरी बातों पर गौर करेंगे ।

डिमान्ड नम्बर 3, जो गृह विभाग से सम्बन्ध रखती है । इस डिमान्ड के लिए कोई माह बारह करोड़ के करीब रुपया मांगा गया है । मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां इस डिमान्ड के लिए सरकार ने इतना रुपया दिया वहां इस विभाग के कर्मचारियों कौ भी सरकार हिदायत करे कि कोई भी गलत काम न करें । यह हमारे हरियाणा के अन्दर सब से बड़ा डिपार्टमैंट है । इसके हाथ में सारे हरियाणा के इन्तजाम की बागडोर है । लोगों को इन्साफ देना भी इनके हाथ में है, अदालतों में तो बाद में लोग पहुंचते हैं । मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि लोगों पर जो गलत केसिज बनते हैं, मुकदमे बनते हैं, ये नहीं बनाये जाने चाहिए । इस ऐमरजैसी के

अन्दर तो ऐसे केसिज बिल्कुल नहीं बनने चाहिए क्योंकि ऐमरजैसी के अन्दर तो लोग इन्साफ की ज्यादा तवक्को रखते हैं, उनको तो उम्मीद होती है कि इंसाफ होगा लेकिन हुआ क्या? सब कुछ उल्टा हुआ है । मैं तो यह कहूंगा कि इस ऐमरजैसी की वजह से पुलिस के हाथ ज्यादा मजबूत हो गये हैं । पुलिस अपनी मनमानी कर रही है । आजकल उनके सामने कोई भी चूं तक नहीं करता है क्योंकि ऐमरजैसी का डन्डा उनके सिर पर है । बहुत से बेगुनाह लोग हमारे जेल में हैं, जिनका कोई दोष नहीं है । उनके बारे में यह भी नहीं बतलाया जाता है कि उनका क्या दोष है? जब उन पर कोई जुर्म नहीं बनता है तो भी उनको जेल में क्यों रखा हुआ है?

हमारे ट्रिब्यून अखबार के नामानिगार काक को भी जेल में डारन दिया है, जो वे हिसार में थे आज तक भी उनका पता नहीं कि उन पर क्या दफा लगायी गई है, किस कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है । मदर लैन्ड अखबार के ऐडिटर को भी गिरफ्तार किया हुआ है । हमारे हिसार के साबका एम०एल० ए० श्री बलवन्त राय तायल को भी घर बैठे हुए गिरफ्तार किया । वे हमारे कांग्रेस (ओ) पार्टी के प्रदेश प्रधान हैं । दूसरे हमारे छः एम० एल० एज ० को भी जो अपोजिशन के हैं घर बैठे हुए गिरफतार किया गया । उनके आज बच्चे तड़प रहे हैं । हम यहां बैठे भी सोचते हैं कि उनके बिना हमारा सदन अधूरा ही है । हमारे मुख्य मंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं । हमें इन पर विश्वास

भी है कि वे नेक आदमी हैं, सुलझे हुए हैं । मैं उनसे यह आशा रखता हूं कि जो बेगुनाह आदमी हैं उनको छोड़ दिया जायेगा । ऐसा करके सरकार हरियाणा का नाम ऊंचा करेगी । यही नहीं उपाध्यक्ष महोदया, जमींदारों की यह हालत है कि उनको भी पकड़ लेते हैं और उनकी कनक भी पकड़ लेते हैं । उन्होंने इतनी गलती जरूर की है कि ज्यादा अनाज पैदा किया । बेगुनाह गरीब मजदूर किसानों को पुलिस पकड़–पकड़ कर अन्दर करती है और वह इस वास्ते कि उनको केस जरूर बनाना होता है । उन गरीब आदमियों पर किसी पर शराब का केस बनाते हैं, किसी की जेब में अफीम डाल देते हैं तो किसी के जिम्मे नाजायज हथियार रखने का केस बना दिया जाता है । यह हालत है पुलिस की । पुलिस को चाहिए तो यह कि वह उन लोगों को पकड़े जो देश के या हरियाणा के गुनाहगार हैं या उनके ऊपर कोई भी सही चार्जिज हों और गरीबों पर जुल्म किया हो, ताकि गरीब को इन्साफ मिले लेकिन उलटा हो रहा है । सारी की सारी, तमाम की तमाम पुलिस इस बात पर –तुली हुई है कि झूठे केस बनाये । वह लोग किसी की भलाई को नहीं देखते । उस हल्के का रूलिंग पार्टी का एम० एल० ए० जिनका नाम ले दे, उनको बन्द कर देते हैं या फिर जिससे उनको कोई रंजिश हो, उनको बन्द कर देते हैं । इस बात के सिवाय उनको कोई काम नहीं है । हमारे मुख्य मंत्री महोदय भी एक बहुत बड़े क्रान्तिकारी आदमी रहे हैं । इनका भी हिन्दुस्तान के अन्दर, अंग्रेजों को यहाँ से निकालने में बहुत बड़ा हाथ था । इन्होंने भी सजाएं काटी हैं,

उस वक्त भी जुल्म होते थे लेकिन उस जमाने में यह बात नहीं होती थी कि किसी पर गलत मुकदमे बनें । अंग्रेज किसी पर गलत मुकदमे नहीं बनाते थे जिस तरह से आज की सरकार गलत मुकदमे बनाती है ।

श्री के० एन० गुलाटी : आन ए प्वांयट आफ आर्डर । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्होंने यह कहा कि रूलिंग पार्टी के एम० एल० ए० नाम लेते हैं । क्या वे यह बतायेंगे कि कौन से वे एम ० एल० ए० हैं जिन्होंने नाम लिये हैं?. (व्यवधान)

चौधरी पीर चन्द : अगर किसी एक आध का नाम हो, तब तो बताऊं । अगर मारे ही हों तो क्या बताऊं ।. (व्यवधान व शोर)

Deputy Speaker : Order please. Please speak on the demands.

चौधरी पीर चन्द : मैं डिमान्ड पर ही बोल रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्रारा मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस चीज में सुधार लाया जाये और गरीब आदमी को पूरी मदद मिलनी चाहिए ताकि आपकी 2० स्लीय प्रोग्राम पूरा करने में सफलता हो । मैं यह बता रहा था कि इतने झूठे मुकदमे बने । मुझ पर खुद पर भी मुकदमा बना । मैं' यूक स्टेज पर बोरा रहा था, कोई गलत बात नहीं थी ठीक बात कही थी लेकिन मुझे पकड़ कर ले गये । दूसरे दिन पता लगा कि मेरे ऊपर 107/151 दफा लगी है । यह कहा गया कि आपने यूक आदमी को जिसको 5– 6

मील दूर गगवा गांव में बुलाया गया, जिसके पास हथियार (बंदूक) थी और जो दस नम्बरी था, हमारे यहाँ एक वकील हैं पीताम्बर जी, उसने और मैंने, दोनों ने मिलकर पकड़कर मारा । आप ही बताओ कि यह गलत बात नहीं है तो क्या छउ? कोई भी आदमी रोमा नहीं. जिम पर इन्होंने सही मुकदमा बनाया हो । इसलिये मैं तो मुख्य मती साहब से यह निवेदन करूंगा कि वे ऐसे मुकदमे न बनवायें और न ही बनने चाहिए । पुलिस को ऐसी हिदायत दी जाए कि ऐसे गलत मुकदमे न बनाओ ।

अब मैं डिमान्ड नं 0 13 पर बोलने जा रहा हूं जो कि हरिजनों से सम्बन्धित है । सरकार की नीति बड़ी अच्छी है और हम भी यह चाहते हैं और इसे मानते हैं कि गरीब आदमियों को मकान और रोजगार जरुर मिलना चाहिए । यह बात ठीक है जो सरकार मानती है और करना चाहती है । यह बड़ी खूशी की बात है लेकिन डिमांड नं० 13 के अन्दर कोई ऐसी बात नजर नहीं आयी जिससे कि उनकी हालत में कोई सुधार हो सके । इसमें तकरीबन 24– 25 लाख रुपया रखा गया है । हरियाणा प्रान्त में 3० लाख के करीब हरिजन है । इससे अन्दाजा यह लगता है कि एक व्यक्ति के हिस्से राक माल के अन्दर एक रुपया पड़ेगा । मैं यह समझ नहीं पाया कि इस तरह से किम तरह सरकार सुधार करना चाहती है । अगर कोई और रुपया 2० सूत्रीय प्रोग्राम में है तब तो ठीक बात है । हमारे मुख्य मती महोदय ने यह बतलाया था कि एक लाख 48 हजार लोगो को प्लाट दिये गये हैं । मैं यह

मानता हु कि कुछ लोगों को प्लाट दिये गये होंगे । शायद वह उन प्लाट्स पर मकान न पायें क्योंकि वह जमीन या तो गड्ढे में है या फिर ऐसी जगहों पर है जो हरिजनों की जमीन से दूर है और जहां जमींदारों की जमीन है जहाँ पर जमींदार का कब्जा है, जिसको वह कभी खाली भी न करा सकें । तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हरिजनों का कोई भला करना है या उनकी हालत में सुधार करने का प्रोग्राम है चाहे वह खेती बाड़ी से है या जमीन देकर है, वह सही तौर पर होना चाहिए । जमीन देने की बात पर हमारे एक मली महोदय ने यह कहा कि 22 लाख एकड़ के करीब जमीन सरप्लस निकलेगी । लेकिन दरअसल देखने से यह जाहिर होता है कि सरप्लस जमीन निकलने की कोई बात नहीं है । पिछली सरप्लस जमीन भी इसी के अन्दर जजब होने लग रही है । अगर सरकार की जमीन देने की नीति है और वह उन लोगों को जो काश्त करते हैं, वाकई जमीन देना चाहती है तो जो उस की अपनी जमीन है, वह दे । जैसे नहर की जमीन है । जो पुरानी नहर थी, वह वहां से दूसरी तरफ मोड़ी गयी हैं । आज उस जमीन को जिसको अब भी हरिजन बीजते हैं उसको भी खाली करवाने की बात हो रही है । हिसार के अन्दर एक बीहड़ है । उसमें 52 हजार एकड़ जमीन अकेले हिसार बीहड़ की है जिस पर 423 मुजारे बैठे कुंए, आज आप उनको भी उठाना चाहते हैं । एक तरफ तो सरकार जमीन देने की बात करती है और दूसरी तरफ उनको उठाना चाहती है । इसमें से कौन सी बात ठीक है और कौन सी बात गलत है, मैं यह समझ नहीं पाया । (घंटी)

उपाध्यक्षा: आपके दस मिनट हो गये हैं ।

चौधरी पीर चन्द : मुझे कुछ टाईम तो और मिलना चाहिए

Deputy Speaker : You may speak for two minutes more.

चौधरी पीर चन्द : जमीन का मसला अगर सरकार हल करना चाहती है, तो कर सकती है क्योंकि काफी ऐसी जमीन पड़ी हुई है जोकि कागजों में है और लोगों को मिल नहीं रही, वह उन्हें दी जाये । जहां तक हरिजनों की हालत में सुधार करने की बात है, उनके लिये छोटी–छोटी इंडस्ट्रीज लगायी जायें और बैकों से उन्हें रुपया दिया जाये जोकि बगैर सूद के हो । इसके अलावा जो भी डिपार्टमैंट या बैकों का पिछला सूद है, वह उन्हें माफ किया जाये । इस के इलावा जो दूसरे कर्जों के मामले में एक साल के लिये स्टे दिया गया है, इससे नुक्सान ही हुआ है, फायदा नहीं है । उनको बैक वाले भी कर्जा देंगे नहीं तो फिर उनकी हालत में सुधार कैसे होगा? इससे हरिजन और नीचे को जायेगा । तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि इसमें सुधार करने की सख्त जरूरत है । जैसे कि यहाँ पर एक लाख 48 हजार लोगों को प्लाट देने की बात आयी है । मैं यह चाहूंगा कि उनको मकान बनाने के लिये रुपया देना चाहिए । (घंटी) एक प्लाट वाले को दस हजार रुपये बगैर सूद के दिया जाये ।

उपाध्यक्षा : आपका टाईम खत्म हो गया है ।

चौधरी पीर चन्द.:बस जी, मैं अब बैठ ही रहा हूं । मैं यह कह रहा था कि हरिजनों को मकान बनाने के लिये रुपया मिलना चाहिए और उनसे वह रुपया आसान किश्तों से वसूल किया जाहू । अब मैं डिमान्ड नं ० 3 पर कहना चाहूंगा ।... (घंटी)..

श्रीमती चन्द्रावतीः जनाब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है । मेरा प्वांयट आफ आर्डर यह है कि यह घंटी की आवाज तो बिना बोलने वालों को भी चौंका देती है, इसलिये जरा घँटी की आवाज को तो मधुर करवाइये ।

राव निहाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, जब घंटी बजानी हो, तो चन्द्रावती जी को बनवा त्रिया जाये

चौधरी पीर चन्द : डिप्टी स्पीकर साहिबा, डिमान्ड नम्बर 10 चिकित्सा के बारे में है । आज हालत यह है कि जो अस्पताल हैं उनमें दवाई नहीं हैं । जो बीमार जाते हैं – उनसे दवाई मंगाई जाती है । मरीजों को ठहरने के लिए अस्पतालों में कोई जगह नहीं है । आपके द्वारा मैं मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां–जहां दवाइयां नहीं हैं वहां पर फौरन ही दवाइयों का इन्तजाम होना चाहिए । मैं जेल के अन्दर भी रहा हूं वहां पर भी दवाइयों का कोई इन्तजाम नहीं है । मेरा वहां पर चार किलो वजन घट गया था । वहां पर हम लोगों को काफी परेशानी थी । वहां पर खाने–पीने का भी अच्छा इन्तजाम नहीं है..

.

उपाध्यक्षा : जेल में तो हर आदमी का ख्याल रखा जाता है ।

चौधरी पीर चन्दः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा तो चार किलो वजन घट गया था । वहां पर दवाओं का अच्छा इन्तजाम नहीं है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जहां कहीं भी दवाएं नहीं वहां उनका प्रबन्ध करन। चाहिए । इतना कहकर डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

चौधरी प्रभु राम (छछरौली–अनुसूचित जाति) : डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं आपके जरिए सब से पहले नए चीफ मिनिस्टर साहब, श्री गुप्ता जी को बधाई देता हूं कि वह बहुत ही अच्छे चीफ मिनिस्टर चुने गझ हैं । इसके साथ ही साथ अपने जो पहले चीफ मिनिस्टर थे चौधरी बंसी लाल उनको भी मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने हरियाणा को बहुत अच्छी तरह से चमकाया और आपके जरिए अपने प्रधान मती को भी पुरजोर बधाई देता ी कि उन्होंने हमारे हरियाणा के मुख्य भली को भारत का रक्षा मंत्री बनाया । डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो भी सरकार आई उसने मेरे हल्के में बहुत काम किए । पहले किसी को यह भी पता नहीं था कि यह हल्का कहां है लेकिन इस सरकार ने मेरे हल्के में बहुत काम किए हैं । मेरे हल्के के लोगों को यह भी पता नहीं था कि बिजली क्या होती है, बिजली कहां से पैदा होती है लेकिन आज मेरे इलाके में बिजली घर–घर में चमक रही है और मेरे इलाके

को बहुत भारी फायदा पहुंचा है । मैं आपके जरिए एक बात सरकार के नोटिस में लाना चाहता हू कि बिजली का फायदा उस इलाके को बहुत हुआ है लेकिन जो गरीब आदमी हैं, चाहे वह हरिजन हैं या गैर–हरिजन हैं और जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं, बल्कि झोपड़ी है उनको बिजली का फायदा नहीं ददुआ है । इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि उन गरीब आदमियों के लिए सरकार मकान बनाए जिससे कि वे बिजली का फायदा उठा सकें ।

जिस प्रकार से सरकार ने सारे हरियाणा में सड़कें बनाई हैं उसी तरह से मेरे इलाके में भी सड़के बनाई हैं लेकिन अभी भी बहुत सी सड़के अधूरी पड़ी हैं । उनको जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए । मेरे इलाके में कई पुल हैं जो अभी तक नहों बने हैं । एक–दों पुल ऐसे हैं जो चौधरी बंसी लाल ने मेरे हल्के में जाकर ऐलान किये थे कि ये पुत्र बना दिए जाएंगे । इसी प्रकार का एक पुल बिलासपुर से रंजीतपुर वाली सड़क पर है । लेकिन इस पुल पर अभी तक कोई तवज्जुह नहीं दी गई है । मैं आपके जरिए सरकार से प्रार्थना करूंगा विरू वह पुल जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे इलाके में ज्यादातर फूंस के मकान हैं और बरसात के मौसम में नदी नालों में बाढ़ आ जाती है और वह उन मकानों को गिरा देती है । फसलों को वहू बाढ़ उजाड़ देती है लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा बान्ध नहीं बांधा गया है जिससे कि वे गांव बचाए जा सके, जो

फूंस के मकान हैं उनके लिए टिन की चादरों का कोई इन्तजाम नहीं किया गया है । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस इलाके में फ्लड से जो नुकसान होता है उसको ध्यान में रखते हुए उनकी मदद की जाए ।

मेरे इलाके में जंगलात बहुत हैं और फून और सरकंडे बहुत होते हैं लेकिन उस इलाके में रोजगार की बहुत कमी है । मेरी प्रार्थना है कि सरकार उन इलाके को कोई अच्छा कारखाना दे ताकि गरीब आदमियों को रोजगार मिल सके । इससे सरकार को भी लाभ पहुंचेगा ।

जिस प्रकार हाउसिंग बोर्ड हर जगह मकान बना रहा है उसी प्रकार से मेरे इलाके में भी मकान बनाए जाए । वह इलाका काफी बैकवर्ड है । अगर उन देहातों में भी यह मकान बना दिर' जाए तो लोगों को भी काफी फायदा होगा और सरकार को भी आमदनी होगी । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे इलाके में गन्ना बहुत अधिक होता है लेकिन आजकल गन्ने की बहुत बेकदरी हो रही है । जब गन्ना कम होता है तो मिल मालिक किसानों को पाबन्द कर लेती है कि मारा गन्ना लिया जाएगा और अगर गन्ना ज्यादा हो जाता है तो मिल गन्ने को नहीं लेती । इस साल गन्ने का रेट ग्यारह रुपए क्विंटल रखा है, लेकिन मिल सवा दस रुपए देती हैं । चीजों का जो भाव पिछले साल था वही भाव इस साल है तो फिर गन्ने का रेट भी वही होना चाहिए, वह पिछले साल से कम नहीं होना चाहिए ।

ऐमरजैंसी से देश का काफी फायदा हुआ है और गरीब आदमियों को काफी सहुलियतें मिली हैं । यह जारी रहनी चाहिए । सरकार ने जमीन देने का जो ऐलान किया है उमके लिए मैं सरकार को मुबारिकबाद देता हु और उम्मीद करता हु मेरे इलाके में जो गरीब हरिजन या गैर–हरिजन हैं उनको भी जमीन दी जाएगी।

सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है और वह है फैमिली प्लानिंग । मैं चाहता हूं कि यह चीज तहसीलदार, पटवारी या चेयरमैन पर छोड़ने की बजाए इसके लिए कानून बना दिया जाए कि दो या तीन बच्चों से ज्यादा न हो । अगर ऐसा कर दिया जातु तो अच्छा होगा और इससे सरकार को भी फायदा पहुंचेगा और देश को भी लाभ होगा । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो हमारी प्रधान मन्त्री महोदया ने 20 सूत्रीय प्रोग्राम लागू किया है इस के बारे मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि हमारे हरियाणा में यह सब से पहले लागू होगा, मुझे जरूरी उम्मीद है कि सरकार अवश्य ही जल्दी इस पर अमल करेगी, जिससे कि लोगों का भन्ना होगा । अतः इसके लिये मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने सब से पहले अगने प्रदेश में इसे नाम करने का निर्णय कर रखा है ।

इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा के अन्दर एजुकेशन ने बहुत बड़ी तरक्की की है । मैं अपने ऐजुकेशन मिनिस्टर साहब से यह दरखास्त करूंगा कि

मेरा जो हल्का एं वह हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है । वहां पर ऐसे स्कूल हैं जिनमें 500–600 के करीब बच्चे पढ़ते हैं । ऐसे स्कूलो को अप–ग्रेड किया जाए ।

ऐसा करने से लोगों की भलाई होगी और ऐजुकेशन की और बढावा मिलेगा ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे इलाके के पास से एक नहर जमन गरबी गुजरती है, जिमका मेरे गांव को पानी मिलता है लेकिन वह पानी बरसात के दिनों में बन्द हो जाता है और लोगों को काफी नुकसान होता है । इसलिये मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि बरसात का जो पानी बंद हो जाता है उसको निकालने का प्रबध किया जाए ताकि लोगों की फसलों को जो नुकसान होता है, लोग उससे बच सकें और ऐसे इलाकों से आबयाना किश्तों में लिया जाया करे ताकि गरीब आदमियों को कुछ राहत मिल सके । इस के साथ साथ वहां पर एक मनहार माइनर का काम अधूरा पड़ा हुआ बुश, उसको भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए । सरकार की तरफ से ट्यूबवैल लगे हुए हैं और वहां पर जो नालियां बनी हुई हैं वह पक्की हैं । लोग आबयाना देते हैं लेकिन हमारे हल्के में कई ऐसी नालियाँ हैं जो कच्ची हैं, जो नहरों के साथ माथ खेतों को जाती हैं । उन नालियों को पक्का बनाकर खेतों को पानी देने का प्रबन्ध किया जाए जिससे पैदावार भी बढ़े और लोगों को भी फायदा हो । जो कच्ची नालियां हैं, वह हफ्ते हफ्ते के बाद टूट जाती हैं और लोगों को नुकसान होता है ।

इसलिए मेरी दरख्वास्त हए कि उन नालियों को पक्का किया जाए । डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं आपके द्वारा सरकार से यह भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जिस तरह से नारायणगढ में सरकार ने टयूबवैल्ज लगा रखे हैं उसी तरह से हमारे हल्के छछरौली में भी सरकार की तरफ से ट्यूबवैल लगाएं जाएं, जिन से लोग फायदा उठा सकें । ट्यूबवैल तो पहले लगे हुए हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं ।

इससे आगे मैं ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमैंट वालों की तवज्जुह इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कलेशर में कोई बस अड्डा नहीं है । लोग वहां पर बरसात के दिनों में तंग होते हैं और न ही वहां पर कोई शैड वगैरह ही है । हम जब जी० टी० रोड से गुजरते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में जगह जगह पर लोकल बस–अड्डे बने हुए हैं । उसी प्रकार कलेशर में भी बस अड्डा बनाने का प्रबन्ध किया जाए ।

एक और बात सरकार के नोटिस में लाना चाहता हू कि छछरौली में एक बस अड्डे के ऊपर एक ग्राम सेवक को गोली मार दी गई और फिर वे लोग भाग गये लेकिन अभी तक उस का कोई सुराग नहीं मिला । पुलिस में गये तो वे कहते हैं कि हम क्या करें हमारे पास कोई विहिकल्ज नहीं हैं । इसलिये मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि हर पुलिस थाने में मोटर साईकल या जीप दी जाएं ताकि वे ऐसे केसों को ट्रेस करने में कामयाब हो सकें । यह सभी बातें जो मैंने यहां पर कहीं हैं, इनके बारे में मेरी दरख्वास्त

है कि सरकार इन पर पूरा ध्यान दे ताकि लोगों को इन्साफ मिल सके और हर प्रकार से आराम मिल सके ।

17.00 बजे

राजस्व मन्त्री (पंडित चिरंजी लाल शर्मा) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एक दौ चीजों के बारे में अपने ख्यालात आपकी वसातत से इस सदन में रखना चाहता हु क्योंकि विरोधी दल कें कुछ माननीय सदस्यो ने जो कुछ यहां कहा, उसके बारे में ट्रेजरी बेंचिज के एक दो आनरेबल मेम्बर्ज ने हाऊस की तवजुह दिलाई । सो मैं हाउस साइट्स के बारे में यहां कुछ कहना चाहता है । परसों एक अपोजीशन के माननीय सदस्य ने यह कहा कि सरकार यह दावा करती दी सरकार यी कह रही है कि 1, 81, 894 समथिंग लाइक दैट यह इलिजीवल परसन थे, जिन में से 148 400 आदमियों को प्लाट दे दिये और यह भी कहा कि क्या दे दिया, शामलात की जमीन थी, दे दी । एक आनरेबल मैम्बर ने कहा कि जो प्लाट्स दिये गये हैं वह किस आधार पर दिये गये हैं, मौके पर निशानदेही नहीं की गई, कब्जा नहीं दिलाया गया । आनरेबल मैम्बर ने जो अपने ख्यालात का एजहार किया है वह हकाकत पर नहीं है । हमारे प्राईम मिनिस्टर साहिबा का 2० सूत्रीय प्रोग्राम पहली जुलाई 1975 को अनाउंस हुआ था लेकिन हरियाणा सरकार ने इससे पहले ही यह निर्णय दिया क्योंकि भारत सरकार का यी पुराना फैसला था कि हिन्दुस्तान के हर नागरिक कौ समाजवाद में रहने का हुक होगा । इम के मायने हैं कि हरेक

आदमी को खाने के लिये रोटी, पहनने के लिये कपड़ा और रहने के लिये मकान मिलना चाहिये । तो इस निर्णय के अनुसार हमारी सरकार ने फरवरी औत मार्च में यह फैसला किया कैबनिट के चार मैम्बरों की एक कमेटी बनी जिस में श्री कन्हैया लाल पोसवाल. श्री श्याम चन्द. चौधरी गोवर्धन दाम और मैं भी शामिल था और हम ने तीन चार सिटिंग्ज की और यी फैसला किया कि इन प्लाट्स को देने के लिये अलाट करने के लिये क्या बेम बनाया जाए । यह फैसला किया गया कि जिस के पास कोई मकान नहीं है बे–जमीन हैं, बैकवर्ड क्लासिज के लोग हैं, हरिजन भाई हैं उन में यह प्लाट्म दिये जाए लेकिन मैं यह यकीन से कह सकता हुं कि हमारे हरियाणा में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिस के पास सिर छुपाने के लिये मकान न हो । जैसे कि हमारे आनरेबल मैम्बर चौधरी रिजक राम जी ने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पाम बड़ी बड़ी कोठियां हैं, महलात हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं गरीब हरिजन, वे जमीन, जिन' के पास छोटे छोटे मकान हैं देहातों में रहते हैं, आप भी वहीं रहते हैं, बेटा भी वहां रहता है और कभी दामाद भी आ जाए तो वह भी वहीं पर ही रहता है और यहां तक कि मवेशियों को भी वहीं पर बांधा जाता है और मवेशी खटोले पर गोबर कर देते हैं । तो हमारी भारत सरकार ने, इन्दिरा जी ने और कांग्रेस पार्टी ने इस चीज का एहसास किया कि स्वतंत्र भारत में उनको भी एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का अधिकार है । इस संबंध में हमारी सरकार ने भी चार मिनिस्टरों की एक कमेटी बनाई जिसने यह फैसला किया कि हर हरिजन

और बैकवर्ड क्लास के आदमी के पास जैसे धनिक, खाती चमार वगैरह–वगैरह हैं जिनके पास मकान नहीं हैं या हैं और उनका परिवार बढ़ गया है उनको कम से कम सौ गज की हाउस साइट दी जाए । उस टाईम जिस वक्त हमारा हिन्दुस्तान आजाद हुआ हमारी आबादी 36 करोड़ थी और आज हमारी आबादी 60 करोड़ है और हरियाणा जिस वक्त वजूद में आया उस वक्त इसकी आबादी 76 लाख थी और आज एक करोड़ 13 लाख है । यहां पर यह कहा गया लैडलैस हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के जो लोग थे उनको प्लाट दिये गये और उनमें से कुछ आदमियों ने प्लाट बेच डाले । इसकी मैं तरदीद नहीं करता, क्योंकि पांच दस मरले का प्लाट अगर किसी ने बेचा तो क्यों बेचा? इसलिये बेचा कि या तो उसने कर्जा देना था या लड़की की शादी करनी होगी इसलिये नहीं बेचा कि वह पांच मरले जमीन बेच कर जिन्दगी भर का गुजारा कर सकता था । अगर जमींदार भी अपनी जमीन बेचता है तो वह हालात का शिकार होकर बेचता है । इसलिये उन गरीबों ने भी ऐसे हालात में ही प्लाट बेचे । तो यह चीज कह देना कि चूंकि उन्होंने अगने प्लाट बेच दिये हैं इसलिये अब उनको न दिये जाएं । उनको पहले प्लाटों को 20– 25 साल का अर्सा हो चुका है तो इस चीज को मद्दे नजर रखते हुए हमने निर्णय लिया है कि जो ऐसे आदमी हैं, हरिजन हैं या बैकवर्ड क्लासिज के लोग हैं जिसके पास सौ गज के मकान हैं और उसके चार लड़के हैं और चारों शादी शुदा हैं तो उन चारों को भी हमने सौ सौ गज का प्लाट दिया है, जिसके पास पांच सौ गज का प्लाट है उसको नहीं

दिया है । इस फैसले के अनुसार 24830 कनाल जमीन पर हमने 1, 4 8, 400 के करीब प्लाट दिये हैं । यह जमीन उसके अलावा है जो उनके घरों के बीच में रास्तों के लिये छोड़ी गई । एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि गांव से एक एक मील के फासले पर प्लाट दिये गये हैं । मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसकी तरदीद करता हूं कि एक भी मिसाल हरियाणा के 6669 गांवों में से दो कि एक एक मील के फासले पर प्लाट दिये हुए हैं । अगर यह बात सच साबित हो जाए तो मैं कटहरे में खड़ा होकर सजा भुगतने के लिये तैयार हूर । यह काम वैसे तो सोशल वैलफेयर डिपार्टमैंट का था लेकिन साबिका मुख्य मन्त्री ने मुझे बतौर रैवेन्यू मिनिस्टर के सौंप दिया । मैंने तमाम जिलों का दौरा किया । मैं खतों–किताब को अच्छा नहीं समझता था इसलिये मैंने वहां पटवारी, तहसील– दार, एस० डी० ओ० और डी० सी० की मीटिंग बुला कर यह पालिसी ऐक्सप्लेन की । वह जमीन जो शामलात देह है । जो पंचायत में वैस्ट करती है, जो गांव की 36 बिरादरी की है, जिसमें बिस्वेदार और गैर–बिस्वेदार सब शामिल हैं, आज यह कहा जाए कि आबादी की वह जमीन ले ली गई––कानून में, विलेज कामन लैड ऐक्ट जब से लागू हुआ तब से शामलात की वह जमीन बिना लिहाज बिस्वेदार गैर–बिस्वेदार सब का राईट है । All rights litle interest whatever in the name vested int he Gram Panchayats which represent the entire village community, landowner or the landless.अब उस जमीन पर विलेज कामन लैड ऐक्ट के रूल 10 के तहत ग्रामीण पंचायत को

भी अधिकार है और हम इसमें लीगल इम्पलीकेशज में नहीं पड़े हैं, हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टज पर यह फैसला किया कि फलां तारीख तक अलाट करने हैं, हमनेइंस्ट्रकशंज दीं कि The Revenue Officers, not below the rank of Naib Tehsildar, he may be Naib Tehsildar, Recovery, Naib Tehsildar, Accounts, Naib Tehsildar, Agrarian, Naib Tehsildars (Mahal) or Sub-Divisional Officers, were supervisory Officers and the Deputy Commissioners were to keep a vigilant और फिर मैंने हर जिले का, सब डिविजन हैडक्वार्टर का खुद दौरा लगाया, चौक किया और अब मैं इस हाउस में आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि इसमें कोई फर्जकारी है तो वह बताएं । पानीपत में 5–6 महीने हुए काम किया जा रहा था उस वक्त भी इस सदन के दो माननीय सदस्यों ने प्रैस में स्टेटमैंट दी थी that the allotment of house sites by the Government is a hoax. और एक माननीय सदस्य ने मुझे चिट्ठी लिखी थी । चौधरी चांद राम आज यहां नहीं हैं । मैंने उनको जवाब दिया था, उसके बाद वे जेल में चले गये । मैंने कहा यह जो आपने गवर्नमैंट की नियत पर शुबहा किया है, इसको होकस करार दिया है, मैं आपके हुस चौलेंज को एक्सैपट करता है । आप गवर्नमैंट के नेक काम में भी गवर्नमैंट पर शुबहा करते हैं । मैं इसकी तरदीद करता हूं और आप किसी भी आदमी को जिस पर आपको विश्वास हो, अपोजीशन का कोई मैंबर, कोई भाई जिसको उचित समझें वह किसी गांव में जाकर इस चीज की पड़ ताल करे और अगर वह यह साबित कर दे कि इसमें कोई फर्जकारी है तो हम उसकी

इन्क्वायरी करुवाएगे । उस अफसर ने, उस रैवेन्यू अफसर ने जिसने कोई फर्जकारी दिखाई है या गल्त रिपोर्ट की है या गावर्नमैंट की आंखों में धूल डालने की कोशिश की हए अगर वह सच पाई गई तो उसके मुताबिक उसको मजा दी जाएगी । तो यह चीज कही गई कि कोई कव्जे नहीं मिले । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि प्लाट्स बाकायदा दिये हैं, लैड डिमारकेट हुई, नम्बरान निकाले गए और उनकी ट्रिपलीकेट कापी और नकशे तैयार हुए हैं और जिस तरह से जमाबन्दी तैयार होती है उसी तरह से हर एक गांव का रजिस्टर मैंनै ट्रिपलीकेट तैयार करवाया है जिसकी एक नकल पटवारी के पास होती है, एक तहसील में जाती है और यूक सदर में और जिलों की सारी रिपोटस जो हैं उनकी कापी यहां हैड– क्वार्टर पर आई है और इसके अलावा ग्रामीण पंचायत से डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट की कोआ– प्रेशन से रैजोल्यूशन पास करवाए गये । उन रैजोल्युशंज का अमल दरामद कागजों में किया जा रहा है । अभी हाल ही में गवर्नमैंट ने फैसला किया है कि उन लोगों को जिनको प्लाट दिये गये हैं, उनको बाकायदा मालिक बनाया जाए और ट्रांसफर आफ प्रौपर्टी ऐक्ट में कोई अगर गैर–मंकूला प्रोपर्टी ट्रांसफर करता है और वह सौ रुपये से ऊपर हो, उसका जो ट्रांसफर है वहू तब तक नहीं होता जब तक कि उसकी रजिस्ट्रेशन न हो । तो अब रजिस्ट्रेशन करने का फैसला किया गया और इन हरिजनों और पिछड़े. हुए वर्ग की माली हालत को ध्यान में रखते हुए गवर्नमैंट ने यह फैसला लिया कि उनको रजिस्ट्रेशन फी और स्टैम्प चार्जिज से मुखतला करार दिया जाए,

इसलिये ताकि उनको यह एहसास हो । इसके साथ साथ यह हिदायत दी गई कि वह मौके पर फिजीकल पोजैशन लें । एक एक दो दो फुट के ओटरे निकाल ले और अपने फैक्चुयल पौजेशन ले लें और साथ ही हमने यह भी कहा कि साल भर के अन्दर अन्दर थोड़ी बहुत उसके ऊपर कन्स्ट्रक्शन जरूर करें और यह हिदायत दी गई कि बीस साल तक इन प्लाट्स को उनको बेचने का हक नहीं है । जो एप्रिहैन्शज, जो खदशात मैंबरान ने जाहिर किये हैं कि वे बेच देते हैं, यह हम इसलिये नहीं कर रहे हैं कि उनको बेचने की रुकावट है लेकिन गवर्नमैंट की इनटैनशन यह है कि उन लोगों की हालत सुधारी जाए । यह ठीक है कि उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वे हजार दो हजार रुपये. इस पर हुक दम इनवैस्ट कर सकें, मा सिवाए चन्द फीसदी के । लेकिन इसका यह मतलव नहीं है । कि वे मकान बना नहीं सकते और उनको प्लाट भी न दिये जाएं । डिप्टी स्पीकर सहिबा, प्राईम मिनिस्टर महोदया ने ए० आई० सी० सी० के सैशन में यह फरमाया था कि भारत वर्ष. में तकरीबन 6० लाख ऐसे आदमियों को हम प्लाट दे चुके हैं । इन्दिरा जी ने यह भी कहा था कि अगर इसमें कोई गलती हुई है तो हम उसे दुबारा वैरिफाई करेंगे । 6० करोड़ की आबादी हमारे हिन्दुस्तान में इस वक्त है और हरियाणा की आबादी एक करोड़ 13 लाख के करीब है । हमने एक लाख 48 हजार ऐसे लोगों को प्लाट दे दिये हैं और 18 फीसदी काम हमारा बाकी है । ये जो बाकी रह गये हैं ये इसलिये रह गये हैं क्योंकि कुछ दांव के अन्दर शामलात देह नहीं थी और

जमीन मिल नहीं सका । इस बारे में भी हम कोशिश कर रहे हैं और सरकार ने फैसला किया है कि उन गांव में जहां शामलात की जमीन नहीं है वहां पर जमीन ऐक्वायर करेंगे और रूरल एरियाज के उन बाकी रह गये गरीब हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को रिहायशी प्लाट्स देंगे । जिन 1 छ फीसदी को अभी तक नहीं मिले हैं, उन सब को देने की कोशिश की जा रही है । यह कहना कि यह सरासर कागजी कार्यवाही है, यह निहायत ही गलत बात है । मैं अर्ज करता हूं कि मैंने अपने फायनैंशल कमिश्नर, कमिशनर्ज, डी ० सीज ० और तमाम रैवेन्यू एजैंसीज को इन राइटिंग हिदायत जारी कर दी हैं कि लैड रैवेन्यू ऐक्ट में जिस तरह से प्रोविजन है उस तरह से इन प्लाट्स के कबजे उन लोगों को दिलाये जायें, मुशतरी, मुनादी से और रोजनामचा में बाकायदा दर्ज करके कब्जे दिलाये जायें ताकि कल कोई यह न कहे कि साहिब हमें कबजा नहीं मिला था । Positivie evidence of delivery of factual possession will be there is writitng as a documentary evidence. यह हो सकता है कि बहुत से गांव में जहां इन प्लाट्स की अलाटमैंट हो चुकी है, डिमारकेशन हो चुकी है उन में डिलिवरी आफ पोजैशन की कार्यवाही पूरी न की गई हो लेकिन the work has not been stopped it is still in rogress and the Revenue Officer are on their guard. इसके बारे में मुकम्मल तौर पर हिदायत दे दी हुई हैं और मैं फिर बड़े अदब से सदन के मैंबर साहिबान को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस बारे में हरियाणा सरकार की नीयत पर शक करना और यह कहना कि

कुछ नहीं हुआ हए यह ठीक नहीं है । हां अगर किसी को इस बारे में कोई शिकायत है तो वह सपैसिफिक तौर पर मुझे, डी० सीज0 और ऐस० डी० एम्ज० को चिट्ठी लिखे और दरखास्त दे । मेरे पास अब भी दस पांच दरख्वास्तें रोजाना आ जाती हैं और इस बारे में मैं ने डी० सीज० को चिट्ठी लिखी हैं कि मेरे पास रोजाना शिकायतें आती हैं कि फलां जगह फलां आदमी को प्लाट नहीं मिला इस बात को बाकायदा बैरीफाई किया जाये और हम ऐसी बात सुनना नहीं चाहते कि किसी को इस बारे में कोई शिकायत हो । मैं मैंबर साहिबान से कहूंगा कि चाहे वह इधर बैठे हैं चाहे उधर बैठे हैं, इस में ट्रैजरी या अपोजीशन बैंचिज की बात नहीं है, और यह चीज नहीं है कि जिन हलकों की हमारे विरोधी दल के भाई नुमाइंदगी करते हैं, उनको हम डेढ़ आंख से देखते हैं । तो सभी मैंबरान से मैं अर्ज करूंगा कि वह अपने अपने हलकों में जाकर वैरीफाई करें और अगर उनके नोटिस में कोई ऐसी शिकायत आती है कि किसी हरिजन को जो मुस्तिहक है, इलिजिबल है, प्लाट नहीं मिला है और गलत रिपोर्ट की गई है कि मित्र गया तो उस गलत रिपोर्ट की सजा मुताल्लिका रैवेन्यू अफसर को जरूर दी जायेगी और जिनको जिन का हक नहीं मिला है उनको उनका हक दिलायेंगे । We are always open to conviction. We mean business. we dot not believe in paper transactions. हमारी प्रधान मंत्री इन्दिरा जी ने इस बीस प्वांयट प्रोग्राम से जो समाज को नया मोड़ दिया है, एक नई करवट दी है, उसका यह सब से जरूरी जुड है कि देश के हर नागरिक को

देश में रहने का हक है जिस ने कि हिन्दुस्तान में जन्म लिया है लेकिन घर बनाने के लिये जमीन खरीदने की शक्ति नहीं रखता । बहुत से ऐसे भाई हैं जो न हरिजन हैं और न बैकवर्ड क्लासिज के हैं और उनके पास भी मकान नहीं है लेकिन जो गवर्नमैंट ने फैसला लिया उस में वे शामिल नहीं हैं क्योंकि हरिजनों को तो कोई बाइज्जत आदमी जमीन बेचने के लिये तैयार ही नहीं है और न ही उन में खरीदने की शक्ति ही है । आप अंदाजा लगायें कि डेढ़ लाख प्लाट जो दिये गये उनकी क्या कीमत हुई और सरकार ने कितना जबरदस्त काम ऐसा करके इस बीस नुकाती प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिये किया है

चौधरी रिजक राम : हां बहुत खर्च कर दिया, मुफत लेकर दे दी?

पंडित चिरन्जी लाल शर्मा : रिजक राम जी कहते हैं कि बड़ा भारी खर्च कर दिया लेकिन मैं कहता हूं कि आम खाने हैं या पेडू गिनने हैं । अगर बिना खर्च किये जमीन दे दी तो क्या बुराई 'हौ गई । मैं अर्ज करता हूं विलेज पंचायत को भी हक है कि शामलात में से फ्री इनको जमीन दे दे । Under rule 10, the Village Panchayat is competent to allot a plot, I me3an for a house site, to a landless person if it feels that he needs it. तो हम ने ग्राम पंचायत को ही यह अख्तियार ऐक्ट में दिया हुआ है कि जो नीडी हैं और मुस्तिहक हैं उनको दे दे । मैं कहना चाहता हूं कि पैसा ही दुनियां में सब कुछ नहीं है कि हर बात में उसे

खर्च करें जहां पर खर्च करना जरूरी होगा वहां पर खर्च करेंगे भी और करते भी हैं लेकिन आज हिन्दुस्तान में यह बात बरदाश्त नहीं होगी कि एक तरफ तो चांदी के थाल में दस कटोरियों में तीतर बटेर, रबडी और मलाई खाई जाये और दूसरी तरफ चंडीगढ की सड़क पर बैठा तुक मोची सुबह से शाम तक जूतियां गांठे फिर भी अगर सुबह को खा ले तो शाम की फिकर में लगा रहे और एक एक टुकड़े रोटी के लिये तरसा करे । आज इस देश में ऐसा नहीं होने दिया जायेगा, क्योंकि हमारी सरकार, इन्दिरा की सरकार और कांग्रेस की सरकार मीन्ज बिजनैस । लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि यह समाजवाद लाने की बात और गरीबी हटाने की बात एक मिनट में छूमंत्र से नहीं हो जायेगी इस के लिये तो लड़ाई करनी पड़ेगी । हम ने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई 1857 में शुरू की थी और पूरे 9० साल तक बराबर यह लड़ाई खून दे दे कर, जवानियां लुटा लुटा कर लड़ी थी । आप जानते हैं कि 9० साल तक हमारे महबूब नेताओं ने गांधी जी और पंडित जवाहर लाल नेहरू की सरप्रस्ती में 1942 में फिर क्विट इन्डिया का नारा लगा कर अपनी अंधी जवानियां अंग्रेज की काल कोठडियों में गुजारी । हमारे मुहब्बाने वतन को ठोकरें मार मार कर हडिडयां तोड़ी गई, बरफ की सिलियों के साथ बांधा गया था, तब जाकर इतने संघर्ष के बाद हमें यह आजादी की देवी मिली थी और हमें उसके सर पर ताज रखने का मौका मिला था । यह कोई अल्ला दीन का चिराग नहीं और छू मत नहीं कि उससे सब चीज हो जायेगी । इस समाजवाद को लाने के लिये दस पन्द्रह साल संघर्ष. करना

पड़ेगा, काम करना पड़ेगा महिज तकरीर कर देने से गरीबी नहीं हटेगी और समाजवाद नहीं आयेगा ।

चौधरी रिजक राम : यह गरीबी घटी है या बढ़ी है ?

पंडित चिरन्जी लाल शर्मा : हम ने घटाने की कोशिश की है, घटाने के साधन किये हैं और साघन अख्तियार कर रहे हैं । हिन्दुस्तान की 55/60 करोड़ जनता का 4600 करोड़ रुपया चंद लोगों के हाथों में था और जनता के इस करोड़ों रुपये के बलबूते पर ये बिरला और टाटा राज करते थे । हमारी प्रधान मली ने अपनी कल्म की एक नोक से यह सारा रुपया अपने कब्जा में लेकर हिन्दुस्तान की साठ करोड़ जनता के बीच फैंक दिया, उनकी बहबूदी के काम में ला दिया

चौधरी रिजक राम : हां बांट दिया सब को ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : क्या इस बात से आप इनकार करेंगे कि आज हिन्दुस्तान के हर किसान के लिये कर्जा, ट्रैक्टर खरीदने के लिये कर्जा, ट्यबवैल लगाने के लिये कर्जा, बीज खाद खरीदने के लिये कर्जा, गाये भैंसें पालने के लिये कर्जा, खाल पक्के करने के लिये कर्जा, रिकशे टांगे टैक्सियां खरीद करने के लिये कर्जे दिये गये हैं और दिये जाते हैं । तो यह सारा पैसा कहां से आया और यह रुपया किस का था? यह रुपया हिन्दुस्तान की जनता का था जो चंद खानदानों कें हाथों में था और जिस पर वे चंद खानदान ही पलते थे । जब हमारी दलेर

प्रधान मंत्री ने नैशनलाइजेशन का फैसला किया तो हमारे विरोधी दलों के नेताओं ने इसका विरोध किया । मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता । प्रिवी परसिज को एबालिश करने का जब फैसला किया गया तो हमारे विरोधी नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की कि यह वायदा खिलाफी होगी । मैं उनकी कोई पर्सनल नुकताचीनी नहीं करता और न करना चाहता हूं क्योंकि वे हमारे नेता रहे हैं और उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी हुई है लेकिन वे लकीर के फकीर रहे, उन्होंने जनता की नबज को नहीं पहचाना कि वह क्या चाहती है और वे गद्दियों से चिपटे रहना चाहते थे, समाजवाद विरोधी थे । जब बैक्स की नैशनेलाइजेशन का सवाल आया तो फिर उन्होंने उसका विरोध किया और अपनी नेक खाहिशात देकर इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चौलेंज करवाया । सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन किया । हमारी बहादुर और दलेर प्रधान मंत्री ने फिर एक तारीखी कदम उठाया । पार्लियामैंट को डिकाल्व करदिया और जनता से इन बातों के बारे में निर्णय लिया । क्या यह छोटी बात थी? यह समाजवाद लाने की तरफ एक कदम था । आज आप देहात में जायें चौधरी रिजक राम जी अपने हल्का में जायें तो उनको देहात में बैक्स की ब्रांचिज मिलेंगी खुली हुई । क्या पहले कोई बैक इन गरीब लोगों को कर्जा देता था? कर्जा तो क्या इन गरीब लोगों को वे बैकंस के दरवाजे तक के पास फटकने नहीं देते थे और उन गरीबों को पता नहीं था कि यह बैक नाम की क्या बला है । मासिवाये कोआप्रेटिव सोसायटीज और कोआप्रेटिव बैंक्स के उनको कहीं से एक दमडी कर्ज की नहीं

मिलती थी । कल चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया था कि पानीपत में स्टेट बैंक खुला है । इन बैंक्स को आर्डर दिये गये हैं कि देहात में जाओ और लोगों को बिला जमानत कर्जे दो । तो क्या यह कम बात है? तो क्या फिर भी आप कह सकते हैं कि यह इनकलाब, इक्तसादी इनकलाब लाने की तरफ कदम नहीं है? मैं पूछता हू कहां गये वह बड़े बड़े रजवाडे और जमींदार जो गांव के गांव के मालिक थे? अब 18 एकड़ पर ला दिये हैं और उन से ली गई सरप्लस जमीन को गरीबों में, बे जमीनों को बांटा जा रहा है । क्या फिर भी आप कहते हैं कि समाजवाद नहीं लाया जा रहा है? अगर कहते हैं तो आप सही बात को सही कहने से डरते हैं और आप में सच को सच कहने की जुर्रत नहीं । जो मजदूर हैं, खेती करके गुजारा करते हैं उनको फैसिलिटीज दीं । आप देखिए. इन्द्र की पूजा करते हैं । इन्द्र. को राजा कहते हैं, क्यों इन्द्र को राजा कहते हैं? राजा इन्द्र, जो वर्षा का देवता है, समुद्रों से पानी उठा कर, आसमान में बादल बनाकर उन सूखे मैदानों में वर्षा करता है जिनको पानी की निहायत जरूरत होती है । आज क्यों इंदिरा की गरीब पूजा करते हैं? इसलिए कि इन्दिरा ने महलों के सरमाये के अम्बार को, दौलत को उठाकर उन गरीबों की झोपड़ियों में पहुंचाया जिनको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हे!ती थी । आप उस इन्दिरा की नुक्ताचीनी करते हैं डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक अलाटमैंट आफ प्लाट्स का ताल्लुक है, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात आपकी वसातत से एक आनरेबल मैम्बर के नोटिस में लाना चाहता हूं कि

जिस वक्त वे अपनी वलवला, मारकाखेज तकरीर कर रहे थे तो हाउस में गलत आँक्रूडे देकर हाउस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे जिस का मुदल्लल जवाब हमारे मुख्य मन्त्री साहब ने अपनी एक घंटे की तकरीर मैं दिया । हमारे अन्दर सुनने की और बरदाश्त करने की शक्ति है और मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कि आप खूबसूरती के साथ सुने जहां तक प्लाट्स का ताल्लुक है, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि अगर किसी को प्लाट न मिले, तहसीलदार, एस0 डी० ओं0, डिप्टी कमिश्नर वगैरा उसकी बात न सूने तो आनरेबल मैम्बर मुझे लिखें, मैं उसकी इन्क्वायरी करवाऊंगा । प्लाटस के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, रोड्ज का महकमा मेरे पास है, और आनरेबल मेम्बर्ज रोड्ज के बारे में बहुत कुछ कहते हैं । हाउस में कहते हैं कि मेरे हल्के में फलाँ सड़क नहीं है..

चौधरी रिजक राम : पुलों की क्या पोजीशन है?

पंडित चिरन्जी लाल शर्मा : पुलों के बारे में भी बताऊंगा । जहां तक चौधरी रिजक राम के हल्के का ताल्लुक है, उनके हल्के में रोड्क बन चुकी हैं । जिस वक्त हरियाणा वजूद में आया था तो कुल 5100 किलो मीटर सड़कें थीं और इस साल 14 हजार किलो मीटर से ज्यादा सड़कें हैं और 6 5–6 6 परसैटं गांवों को सड्कों से मिला चुके हैं । हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री

चौधरी बंसी लाल ने ऐलान किया था कि 26 जनवरी, 1973 तक हरियाणा के हर गांव को सड्कों से मिला देंगे । यह प्रोग्राम लेकर हम चले थे

चौधरी रिजक राम : यह प्रोग्राम टूट क्यों गया.?

पंडित चिरन्जी लाल शर्मा : 92 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट सड़कों के लिए बनाया गया था कि हरियाणा के हर एक गांव को सड्कों से मिला देंगे । इस रकम में से 45 करोड़ रुपया फाइव ईयर प्लान में खर्च हो चु का है । इसके बाद जून, 1972 में गवर्नमैंट आफ इंडिया ने इतराज किया कि सड्कों पर काफी काम कर चुके हो, अब हरियाणा वालो, तुम बिजली और पानी पर अपना दिमाग कंसैन्ट्रेट करो । फिर हमने अपना रुख बिजली और पानी की तरफ मोंड़ा । जो काम बिखरा पड़ा है, कहीं अर्थ–वर्क हुआ है, कहीं सोलिग होनी है, कहीं मैटीरियल बिखरा पड़ा है, कहीं लैड एक्वायर हुई है लेकिन कम्पनसेशन नहीं दिया, इस किस्म का काम रहता है । तकरीबन 500 किलोमीटर का गैप है जिसकी या तो हाई कोर्ट में रिट चल रही है, या कोई और वजह है । हमने 4000 के करीब कलवर्टस बनाने हैं और अब जो रुपया हम मांग रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर मैं गलती नहीं करता, 1976–77 में 3 करोड़ 30 लाख रुपया रोड्ज के लिए दे रहे हैं जिस में से 30 परसेंट एस्टेबलिशमैंट का चला जाता है, कुछ बिचुमन खरीदना पड़ता है और भी कई किस्म के खर्चे हैं । तो मुश्किल से रोड्ज के लिए, एक्चुअल अर्थ–वर्क के लिए तकरीबन 1

करोड़ रुपया बचता है । इस रुपये में हम 500 किलो मीटर के गैप को पूरा करें या नई सड़कें बनाएं या कलवर्टस प्रोवाइड करें, कितना काम कर सकते हैं आपने बजट में देखा होगा, बिजली और पानी के लिए कितना परसैटं एरिया मार्क किया है? मैं जानता हू आनरेबल मेम्बर्ज के जजबात को कि उन के इलाके में सड्कों की तकलीफ है और खास तौर से पड़ोस के गांव में सड़क बन गई हो और उन के गांव में न हो तो महसूस होता है । मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि ज्यों ज्यों हमें रुपया मिलता रहेगा, हम जल्दी से जल्दी हरियाणा के गांवों को लिंक– रोड्ज से कनैक्ट करने की कोशिश करेंगे । मैम्बर्ज कहते हैं कि फलां हलके में सड्कों का काम नहीं हुआ है, यह किसी एक हल्के की बात नहीं है, सारे हरियाणा में सड्कों का काम करना है, जैसे बिजली पहुंचाई है, उसी तरह सड़कें पहुंचाएंगे लेकिन कुछ दिक्कत है और वह है–''पौसिटी आफ फंड्ज ।'' फण्डज का मसला है । जहां लोगों की डिमांड है वहां गवर्नमैंट की भी कुछ मजबूरियां हैं

चौधरी रिजक राम : जब से आपने चार्ज लिया तब से फण्डज की कमी हुई है या पहले भी थी.....?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : मैं इस चार्ज को तसलीम करता हूं, उस वक्त यह पोजीशन नहीं थी । चौधरी रिजक राम के टाईम में बहुत अच्छा काम हो गया था, मुझे इस बात का फख्र है लेकिन मैं सड़कों के मुकाबले में बिजली और पानी को ज्यादा अहमीयत देता हूं । बिजली और पानी की अहमीयत को मद्देनजर

रखते हुए हमने निर्णय लिया कि सड़कें तो बनती रहेंगी लेकिन सबसे पहले खेतों में काम करने वाले जमींदार की शक्लोसूरत पर निखार आना चाहिए और वह तभी आ सकता है जब उसके खेत में पानी देंगे । सड़कें तो बनती रहेंगी । मैं चौधरी साहब के चार्ज को बमरो चश्म कबूल करता हूं । प्लाट्स के बारे में दो तीन दिनों से चर्चा चल रही थी । माननीय सदस्य इस के बारे में कह रहे थे, इसलिए मैंने अपना फर्ज समझा कि जो गलतफहमी उनके दिल में है उसको दूर कर दिया जाए । इन लफ्जों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हैं ।

श्री जोगी राम (राजौंद–अनुसूचित जाति) : माननीय डिप्टी स्पीकर साहिबा, म्उझे ज्ञउशी हुई जो आपने बोलने के लिए टाईम दिया । हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री चौधरी बंसी लाल जी, आज सैन्टर में डिफैंस मिनिस्टर के पद पर पहुंच गए हैं । हरियाणा उनका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य करके दिखलाया । हर जगह बिजली गई, नहरें गई और ट्यूबवैल लगाए गए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके जरिए सदन से कहना चाहता हूं कि चौधरी बंसी ताल ने जमीन के चप्पे चप्पे के अन्दर, कण कण के अन्दर काम किया है और अब हरियाणा की बागडोर श्री बनारसी दास गुप्ता के हाथ में आई है । वे बड़ी समझ और सूझबूझ के व्यक्ति हैं और हमें उनसे बड़ी आशा है क्योकि वे कांग्रेस के बहुत पुराने वर्कर हैं, उनकी बड़ी

कुर्बानियां हैं । 1946– 47 की आजादी की लड़ाई में उन्होंने बड़ी कुर्बानियां की थी, हमें उन से बड़ी आशा है और उन्होंने हरियाणा में बड़े अच्छे तरीके से काम करके दिखलाया है । चौधरी बंसी लाल ने मुख्य मंत्री बनते ही हरियाणा का नक्शा बदल दिया और अब हमारे मुख्य मन्त्री श्री बनारसी दास जी बन गए हैं ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे हल्के की कुछ डिमान्डज हैं, मैं उनके बारे में जिक्र करना चाहता हूं । हमारे पी ० डब्ल्यू ० डी ० मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हुए हैं और उन्हीं के पास रेवैन्यू डिपार्टमैंट भी है । मेरे हल्के में जो प्लांट्स दिये गये हैं वे गांवों से काफी दूर के फासले पर दिये गये हैं, एक एक मीत दूर दिये गये हैं । कुछ प्लाट्स तो शमशान भूमि और जोहडों के अन्दर दिये गये हैं । मैं आपके सामने सबूत पेश करूंगा, यह उन लोगों के माथ ज्यादती हुई है । (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए प्रार्थना करूंगा जिन दो चार गांवों के अन्दर गढे और शमशान भूमि के अन्दर प्लाट्स दिये गये हैं उनके बारे में सरकार विचार करे और उनको अच्छी जगहों पर प्लाट्स दिये जायें ।

मेरे हल्के में ट्यूबवैल्ज बहुत थोड़े हैं वहां पर पानी की कमी है । इसलिए अपने मुख्य मती साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वहां पर भी पानी अधिक देने का प्रबन्ध किया जाये ।

स्पीकर साहब, मैं अपने हल्के की सड्कों के बारे में भी

जिक्र करना चाहता हूं । राजौन्द से माजरा तक पक्की सड़क है और माजरा से ले कर अरहेडा किठाना तक कच्ची सड़क है, उस पर मिट्टी पड़ी हुई है । किठाना गांव से मांडी कला, खेडी शेरखां तक यानी मेरे अपने गांव तक पक्की हो गई है, इस टुकड़े को यदि पक्का कर दिया जाये, तो बस चल सकती है । दूसरा टुकड़ा लोघर से काबरशाह तक है । यह तीन मील का टुकडा है । इस पर रोडी पड़ी हुई है इसको भी पक्का कर दिया जाये तो आपकी मेहरबानी होगी । करनाल से असन्द और असन्द से राजौन्द हो कर नरवाना तक सड़क मिला दी जाये तो हिसार को सड़क मिल सकती है ।

स्पीकर साहब पांच सात गांव तहसील नरवाना के हैं । उनको वाया कैथल, वाया जीन्द हो कर आना पड़ता है । अगर इनको मैन सड़क से मिला दिया जाये तो इनकी दिक्कत दूर हो सकती है । ये दो चार बातें मैंने अपने हल्के के बारे में आपके सामने रखी हैं । मैं आपके जरिए प्रार्थना करता हूं कि इन मांगों को सरकार पूरा करे । मैं आपका शुक्रिया करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

वित्त मंत्री (श्री राम सरन चन्द मित्तल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने अपने सुझाव पेश किये हैं । जहाँ–जहाँ उनको त्रुटियाँ नजर आयी, उन्होंने हाउस में प्रकट कीं । जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, डिमान्डज एज ए होल, लोगों की जरूरियात बहुत ज्यादा हैं । लोगों को यह भी ध्यान रखना

चाहिए कि 1966 के पहले हरियाणा की क्या हालत थी और अब क्या कुछ यहाँ पर हुआ है । पहले से अब काफी अच्छे हालात हैं । उसके लिए कितने ही रुपये खर्च हुए और कितने की ही जरूरत है । तमाम जरूरियात को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत है । हमारा उत्पादन बढ़ा । अगर हमारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बढ़ती है तो उससे इन्डस्ट्री भी इन्कीज होती है, हैन्डीक्राफट भी इन्क्रीज होता है । उससे सारी चीजें इन्क्रीज होती है । हमारा बजट बोलता है कि देहातों के अन्दर अनाज पैदा होता है, देहातों के अन्दर अच्छी हालत हुई है । काफी जरूरियात उनकी पूरी की गई हैं लेकिन जो बातें पूरी नहीं हुई, उनको एक साथ पूरा करना मुश्किल होगा । हमारे लिमिटिड रिसोर्सिज हैं, छोटी स्टैट है । छोटी स्टेट होते हुए भी कही से हमने अपने रिसोर्सिज किये, अपनी स्टेट की डिवैल्पमैंट की है । हमें सैन्ट्रल गवर्नमैंट से अस्सिटैंस मिलती है, कर्जा भी लेते हैं, टैक्स वसूल करने की पूरी कोशिश करते हैं । जो टैक्स इवेजन होता है, उसको रोकने की कोशिश पूरी करते हैं । हर तरह से जितना रुपया मिलता है, वह खर्च करने हैं, फिर उसमें भी प्रायरिटी देते हैं । वह बजट के अन्दर हैं । स्पीकर साहब, खास तौर पैर राव दलीप सिंह ने कुछ को–आप्रेटिव डिपार्टमैंट के बारे में, फूड्ग्रेन और पंचायत के बारे में सुझाव दिये । यह ठीक बात है कि ऐम्बैजलमैंट है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । उसके लिये सरकार भी कोशिश कर रही है, स्टैप्स ले रही है । को–आप्रेटिव डिपार्टमैंट में जो भी ऐम्बैजलमैंट करते हैं उनको सजा दिलायें में ताकि आइन्दा न हों

। जितनी भी ऐसी बातें हैं,

उनके बारे में पूरी कोशिश की जायेगी । एक बात उन्हेंने यह भी बतलायी कि जहाँ–जहाँ पर बसें रुकती हैं, वहां पर केटरिंग की शिकायत है कि चाय और पकोड़ों में से बदबू आती है । मैं इसके मुताल्लिक माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर दिलाऊगा कि हरेक डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रांसपोर्ट कमेटी बनी हुई है । उस कमेटी का मैम्बर जनरल मैनेजर, मैडीकल आफिसर और डिप्टी कमिश्नर है । डिप्टी कमिश्नर उसका चेयरमैन होता है । अगर ऐसी शिकायत नजर आये तो उनको उस कमेटी के नोटिस में लाना चाहिए ताकि वे तुरन्त ठीक हो जायें और यहाँ पर बताने की जरूरत ही न पड़े । चौधरी अमर सिंह जी और बत्तरा साहब ने कुछ हैन्डीक्राफ्ट, दस्तकारी, स्माल–स्केल इंडस्ट्री और विलेज इंडस्ट्री के बारे में कहा कि वे गांवों में होनी चाहियें । उन्हें मार्किटिंग फैसिलिटीज मिलनी चाहियें । मैं तो एक बात से हैरान हुआ कि हम लोगों को तो यह कहें कि स्वदेशी चीजों को बढ़ावा दें और खुद उनको इस्तेमाल न करें । अब अगर विलेज इंडस्ट्री को महज गवर्नमैंट पैट्रोनाइज कर दे और लोग खुद पैट्रोनाइज न करें तो कैसे काम चलेगा हमारा कपड़ा है, करोकरी का सामान है, और बहुत सी चीजें हैं, जब तक हम उनको पैट्रोनाड्ज नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें गैट्रोनाइज नहीं हो सकतीं । इधर तो हम लैक्चर देते हैं कि गाँव का प्रोडक्ट है, गवर्नमैंट को एन्क्रेज करना चाहिए, उधर इसको इस्तेमाल न करें । दोनों बाते कैसे चल

सकती हैं? गान्धी जी का एक असूल था । उन्होंने कहा कि हमारे देहातों में गरीबी बढ़ती जा रही है । उन्होंने चर्खा चलाया । मुझे याद है कि उस समय एक कार्ट नू निकाला गया उसमें कहा कि चर्खा कातने का मतलब यह धै, उन्होंने चर्खे को तोप की शक्ल में रखा । उस चर्खे में से जो बम्ब निकलता है, वह लंकाशायर और मानचौस्टर पर जाकर गिरता दिखाया गया था । तो अगर हमें देहात के लोगों के साथ हमदर्दी है तो हमारी प्रधान मंत्री ने हैन्डलूम का एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया है, उसको कामयाब बनाना चाहिये । हम भी हैंडलूम और हैन्डीक्रास्ट कारपो– रे शन बना रहे हैं और यह दूसरी जगहों में भी बनने जा रही है क्योंकि यह तो सारे इंडिया का प्रोग्राम है । लेकिन जब तक हमारी स्प्रिट स्वदेशी नहीं होगी और स्वदेशी में भी रुरल प्रोडक्ट इस्तैमाल नहीं करेंगे, तब तक कोरा कहने से कोई फायदा नहीं हो सकता । गवर्नमैंट अपना फर्ज अदा कर रही है और हम हर तरह से यह कोशिश कर रहे हैं कि विलेजिज के अन्दर जितनी हैन्डीक्राफट फेसिलिटीज दे सकते हैं, देंगे । हम उनकों मार्किट फैसिलिटी भी देंगे लेकिन हमारा एंगल आफ विजन इस ओर कुछ न कुछ बनना चाहिये । तो मेरा कहने का मतलब यह है कि गवर्नमैंट जहां अपना फर्ज अदा कर रही है, वहाँ हमें खुद भी कुछ न कुछ एग्जेम्पल सैट करनी चाहिए । हमें विलेज प्रोडक्टस को पैट्रोनाईज करना चाहिए ।

चौधरी श्याम लाल जी ने अपने अस्पताल के बारे में भी

कहा । उनको एक प्राइमरी हैल्थ सैटर की कुछ गलतफहमी सी हो गयी कि वह कहाँ खोल रहे हैं, दरअसल वह जगह है खेडी कलाँ । वहाँ प्राइमरी हैल्थ सैटर आलरेडी बन रहा है । वह कोई नया नहीं है बल्कि कान्टीन्यूइंग स्कीम है क्योंकि वह जेरे तामीर है । पहले से ही बन रहा है लेकिन अब उसको अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए उसको कम्पलीट करने के लिये इसमें प्रोवीजन है । तो इस तरह वह कोई नयी चीज नहीं है और वह खेडी कलां जगह है जहां पर कि यह बन रहा है । उनकी एक मांग थी कि पलवल में ड्राईपोर्ट होनी चाहिए । हम सब चाहते है कि उनके यहाँ ड्राई पोर्ट होनी चाहिए लेकिन ड्राई पोर्ट का होना या न होना और कहाँ होगी, यह दरअसल सैट्रल गवर्नमैंट का काम है और उनके हाथ में है । जहाँ तक हमारी स्टेट गवर्नमैंट का ताल्लुक है, हमारी स्टेट गवर्नमैंट इस बात पर पूरी तरह से तुली हुई है कि अगर हरियाणा में कहीं ड्राई पोर्ट. बने, तो पलवल में बननी चाहिए । यह हमारा स्टैन्ड है । यह हमारे हाथ में नहीं है । हमारे जो पिछले मुख्य मंत्री थे, वे और जो अब हैं, वे भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि ड्राई पोर्ट पलवल में बनाई जाए । यह कहना कि बन जायेगी, यह दिल्ली वालों के हाथ में है, चंडीगढ़ वालों के हाथ में नहीं है । हाउस साइट्स के बारे में और रोड्ज के बारे में हमारे साथी पंडित चिरंजी लाल जी ने आपके सामने विस्तारपूर्वक कह दिया है । मैं सब सदस्यों को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने अपने–अपने हल्कों की जो मांगें पेश की हैं, 'उन पर सम्बिन्धित विभाग पूरा विचार करेंगे और जितना बन्

सकेगा, उतना किया जायेगा । अब मैं चाहूंगा कि इन डिमान्ड्ज को पुट किया जाये और पास किया जाये । शुक्रिया ।

Mr. Speaker : Now I will apply guillotine and put the various demands to the vote of the House, one by one.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 27,32,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77

in respect of the charges under Demand No. 1-Vidhan Sabha.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 4,63,52,677 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect f the charges under Demand No.2-General Administration.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 12,32,50,840 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 3-Home Department.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 3,28,31,470 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 4-Revenue Department.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 1,52,33,251 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 5-Excise and Taxation Department.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 3,79,02,395 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77

in respect of the charges under Demand No.6-Finance Department.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 2,92,93,436 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 7-Other Administrative Services.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Sum' not exceeding Rs. 20,04,29,730 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 8-Buildings and Roads Department.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 35,85,60,030 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect f the charges under Demand No. 9-Education Department.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs.17,20,85,770 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course f payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 10-Medical and Public Health Dapartments.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 10,82,53,140 be

granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 11-Urban Development Department.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 2,01,94,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 12-Labour and Employment Department.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 2,86,25,840 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation Departments.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 92,94,55,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 14-Food and Supplies Department.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 65,39,81,670 to granted to the Governor **to defray** the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 15-Irrigation Department.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 2,97,46,095 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the coures of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 16-Industries Department.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 14,25,36,660 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 17-Agriculture Department.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 4,71,81,790 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 18-Animal Husbandry Department.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 27,87,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 19-Fisheries Department.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

The a sum not exceeding Rs. 1,56,06,050 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 20-Forest Department.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 3,24,18,360 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 21-Community Development Department.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 26,33,74,650 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 22-Co-operation Department.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 37,43,41,317 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No. 23-Transport Department.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 15,89,150 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demand No 24-Tourism Department.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 42,07,05,500 be granted to the Governor to defray the charges that will some in the course of payment for the year 1976-77 in respect of the charges under Demend No. 25-Loans and Advances.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 2 p.m. tomorrow.

17. 48 बजे

(The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Thursday, the 22nd January, 1976).

परिशिष्ट

कृपया डिबेट के पृष्ठ (8)22 पर पद टिप्पणी देखे ।

Common Facility Workshops in the State

***1555. Rao Dalip Singh ;** Will the Minister for Agriculture be pleased to state -

(a) the district-wise total number of Common Facility Workshops set up in the State to—date ;

(b) the present strength of staff working in each Common Facility Workshop ;

(c) the total amount invested on machinery and equipment in each Common Facility Workshop ; and

(d) the total turnover of services rendered in each Common Facility Workshop during 1974-75 to-date ?

Agriculture Minister (Col. Maha Singh) :

(a)

(b)

The statement is laid on the Table.

(c)

(d)

STATEMENT

District-wise total number of Common Facility Workshop (24) with details of staff, investment on Machinery and equipments and turnover of services rendered.

S.No	Name of District	Total No. of CFWs in a District	Location of CP W (with block)	Trade	No. of staff	a inv ma equ
1	2	3	4	5	6	
1,	Ambala	1	Naraingarh	Light Engg. & carpentry	1. One Supervisor 2, One Genl. mechanic. 3. One Mate-cum-Genl, Assistant 4. One Peon-cum. Chowkidar.	23
2.	Kurukshetr	2	Shahabad	Leather	1, One	58

	a				Supervisor	
			Markanda	Tanning	2, One Mechanic.	
					3. One-Peon-cum-Chowkidar.	
			Pundri	—do—	—do—	13
3.	Karnal		Kalron (Gharaunda)	—do--	1. One Supervisor	22
					2. One Genl. Mechanic	
					3. One-Peon-cum-Chowkidar (under suspension),	
4.	Gurgaon	4	Pataudi	Light Engg. & carpentry	1. One Supervisor	21
					2. One Genl. Mechanic	
					3. One Mate-cum-	

					Genl. Assistant	
					4. One Peon-cum-Chowkidar	
			Alawalpur (Palwal)	—do—	— do—	25,
			Hathin	—do—	—do—	28,
			Deglot (Hodel)	Light Engg. & carpentry	1. One Supervisor (under suspension)	34
					2. One Genl. Mechanic	
					3. One Mate-cum-Genl. A ssistant	
					4. One Peon-cum-Chowkidar	
5.	Mohindergarh	4	Kuksi	—do—	—do—	13

			(M. Garh)			
			Bawal	—do—	—do—	21
			Jhagrauli (Kalina)	—do—	—do—	12
			Ateli Nangal	—do—	—do—	35
6.	Bhiwani	2	Bond Kalan (Dadri I)	—do—	1. One Supervisor 2. One Genl.Mechanic (under suspension) 3. One Mate-cum-Genl. Assistant 4. One Peon-cum-Chowkidar	18
			Mondhal (Bawani K F era)	—do—	—do—	22
7.	Hissar	6	Tohana	Light Engg. & carpentary	1. One Supervisor 2. One	32

					Genl. Mechanic	
					3. One Mate-cum-Genl. Assistant	
					4. One Peon-cum-Chowkidar	
			Jakhod Khera (Hissar II)	—do—	—do—	22
			Barwala Bhathu	—do—	—do—	33
			(Fatehabad)	—do—	—do—	17
			Narnaund	—do—	—do—	31
			Dabra (Hissar I)	Light Engg. & Carpentry	— do—	49
8.	Rohtak	2	Kalanaur	—do—	—do—	31
			Akheri Madanpur (Nahar)	—do--	—do—	25
9.	Sonepat	I	Gohana	—do—	—do—	25
10.	Jind	1	Bilarkha	—do—	—do--	30

(Narwana)

Total	24 CFWs	93	6,52,733.33